

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 54] No. 54] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/MAGHA 29, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2016

<u>(अंतिम जांच परिणाम)</u>

विषय: यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सऊदी राज्य, चीनी ताइपेई तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 2-एथिल हेक्सानॉल (2-ईएच) के आयात संबंधी पाटन-रोधी जांच।

एफ. सं. 14/24/2014-डीजीएडी .- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

2. यत: आंध्र फार्मेस्युटिकल्स लिमिटिड (जिसे आगे याचिकादाता कहा गया है) जो कि भारत में 2-एथिल हेक्सानॉल (2-ईएच) (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) का एक मात्र घरेलू उत्पादक है, एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सऊदी राज्य, चीनी ताइपेई तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश/क्षेत्र" कहा गया है) से संबद्ध वस्तुओं के आयात होने तथा उसके परिणाम स्वरूप उसे क्षित होने का आरोप लगाया है तथा उपरोक्त देशों/क्षेत्रों के खिलाफ पाटन-रोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

843 GI/2016 (1)

3. और यत: प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर दिनांक 20 नवंबर, 2014 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जो कि भारत के राजपत्र आसाधारण में प्रकाशित हुई थी, जिसमें नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार उपरोक्त देशों के मूल की अथवा वहां से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करने तथा आरोपित आयात के विद्यमान होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटन-रोधी शुल्क का निर्धारण करने जिसे यदि लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने का उल्लेख किया गया था।

क. क्रिया-विधि

- 4. प्राधिकारी ने इस जांच के संबंध में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया है :-
- (1) प्राधिकारी ने नियमावली के उप-नियम 5 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए आवेदन के बारे में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को सूचित किया है। भारत और कोरिया जनवादी गणराज्य के बीच हुए गहन आर्थिक सहभागिता करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.14 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में उसके दूतावास के माध्यम से कोरिया गणराज्य सरकार को भी सूचित किया गया है।
- (2) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के बारे में नई दिल्ली में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया है।
- (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनसार 20 नवंबर, 2014 की जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों को भी प्रेषित की थी। इस जांच से संबद्ध हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/आयातकों की सूची के साथ संबंद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबंद्ध देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह परामर्श दें कि वे इस संबंध में प्रश्नावली के अपने उत्तर निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकारी को भेज दें।
- (4) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका के अगोपनीय वृतान्त की प्रतियां, ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई थी।
- (5) नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातकों की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
 - (क) बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, पहांग, मलेशिया
 - (ख) बीएएसएफ पेट्टोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, सेलान्गोर, मलेशिया
 - (ग) जेडएके, जॉक एस.ए.यू.एल. पौलेंड
 - (घ) ईआईएफ एटोकेम एस.ए. फ्रांस
 - (ड़) सोल्वेंट्स डोकूमेंटेशन सिंथेसिस एस.ए. फ्रांस
 - (च) एक्सोनोमोबाईल केमिकल हॉलैण्ड बीवी, रोटारडम

- (छ) बीएएसएफ, वोहलस्ट्रास्से, जर्मनी
- (ज) सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कोर्पोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब
- (झ) परस्टोप ओक्सो एबी, स्वीडन
- (ञ) एलजी केमिकल्स, कोरिया
- (ट) अरकेमा, फ्रांस
- (ठ) पीटी पेट्टो ओक्सो न्युसान्तरा (पीटी पीओएन), इंडोनेशिया
- (ड) नॉन या पुलास्टिक्स कोर्पोरेशन, ताईवान
- (ढ) विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका
- (ण) आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका
- (त) बीएएसएफ, संयुक्त राज्य अमरीका
- (थ) डॉब केमिकल्स, संयुक्त राज्य अमरीका
- (द) ईस्टमेन केमिकल कंपनी, संयुक्त राज्य अमरीका
- (6) संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के बारे में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
 - (क) मेसर्ज पीटी पेट्रो ओक्सो न्युसान्तरा (पीटी पीओएन), इंडोनेशिया
 - (ख) मेसर्ज सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर
 - (ग) मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कोर्पोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब
 - (घ) मेसर्ज एल-जुबैल फर्टलाईजर कंपनी सऊदी अरब (एल्बेरोनी)
 - (ङ) मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच, जर्मनी (ओक्सिया)
 - (च) मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई
 - (छ) मेसर्ज बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (बीपीसी)
 - (ज) मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
 - (झ) मेसर्ज एलजी केम लिमिटिङ, कोरिया जनवादी गणराज्य (एलजी केम)
 - (ञ) मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिङ, संयुक्त राज्य अमरीका
 - (ट) मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका
- (7) नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नाविलयां भेजी गईं थीं :-

1.	सी.जे. शाह एंड कंपनी, मुंबई	2.	पेट्रोकेम मिडल ईस्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटिड, मुंबई
3.	केएलजे रिसोरसिज एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली	4.	दीपक नाईटराईट लिमिटिड, मुंबई
5.	ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटिड, थाणे	6.	पेटकेम प्रोडक्टस – गुजरात, मुंबई
7.	पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लिमिटिड, नई दिल्ली	8.	अगसार पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटिड, टूटीकोरिन
9.	सीएजी इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश	10.	सी एंड ई लिमिटिड, हरियाणा
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी, तेलांगना	12.	केरोक्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटिड, कर्नाटक
13.	रघुनाथ डाई केम प्राईवेट लिमिटिड	14.	सेलीकाईलेट्स एंड केमिकल्स प्राईवेट
	कुरनूल		लिमिटिड, तेलांगना
15.	उषोदय पेंट्स, आंध्र प्रदेश	16.	सन्निधि केमिकल इंडस्ट्रीज, तेलांगना
17.	लक्ष्मीनारायण विशंभरनाथ, उत्तर प्रदेश	18.	राईनो रेसिन्स प्राईवेट लिमिटिड, तेलांगना
19.	निकोलस पिग्मेंट्स एंड इंक्स, कानपुर	20.	निशा डाई केम, अहमदाबाद
21.	मोदी इंटरप्राईजिस, महाराष्ट्र	22.	इंडस्ट्रियल प्रोडकट्स मेन्युफेक्चरिंग कंपनी, महाराष्ट्र
23.	एसोसिएटिड डाईस्टफ प्राईवेट लिमिटिड, गुजरात	24.	इंडोकेम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटिड, गुजरात
25.	शालीमार पेन्ट्स लिमिटिड, पश्चिम बंगाल	26.	राईट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटिड, पश्चिम बंगाल
27.	जगदम्बा केमिकल्स, पश्चिम बंगाल	28.	अग्रवाल सेल्स कोर्पोरेशन, पश्चिम बंगाल
29.	पायल पोलीप्लस्ट प्राईवेट लिमिटिड, नई दिल्ली	30.	रचना प्लास्टिसाईजर्स, मुंबई
31.	अमर इंडस्ट्रियल सर्विसिज, तेलांगना	32.	इंडियन एडिटिव्स लिमिटिड, चेन्नई
33.	केजेएल प्लास्टिसाईजर्स लिमिटिड (यूनिट 1 और 11), नई दिल्ली	34.	कस्तूरी रेसिन एंड सिथेटिक्स, विजयवाडा
35.	पशुपति पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटिड, आंघ्र प्रदेश	36.	राईना रेसिन्स प्राईवेट लिमिटिड, तेलांगना
37.	स्पेक्ट्रा कोट्स , नेल्लोर	38.	श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश
39.	बंसल ट्रेडिंग कंपनी , नई दिल्ली	40.	नक ईकबाल (इंडिया), महाराष्ट्र
41.	महा भवानी केमिकल्स, राजस्थान	42.	नीलम एक्वा एंड स्पेशली केम प्राईवेट

			लिमिटिड, राजस्थान		
43.	मेघमणी डाईज एंड इंटरमीडिएट्स लिमिटिड, अहमदाबाद	44.	मर्क लिमिटिङ, महाराष्ट्र		
45.	ट्रोईक्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटिड, महाराष्ट्र	46.	जीविका स्मेककेम प्राईवेट लिमिटिड, महाराष्ट्र		
47.	गेलेक्सी सरफेक्टेंट्स लिमिटिड, महाराष्ट्र	48.	प्रीमियर इंटरप्राईजेस, पश्चिम बंगाल		
49.	आर. के. ट्रेडिंग, कटक, औडिषा	50.	कृष्णा ट्रेडर्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		
51.	एनेक्स केमिकल्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	52.	इंडियल प्लास्टिसाईजर्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली		

- (8) संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-
- इंडियन प्लास्टिसाईजर्स मेन्युफेक्चरर्स ऐसोसिएशन
- मेसर्ज केएलजे पुलास्टिसाईजर्स लिमिटिड
- मेसर्ज रचना पुलास्टिसाईजर्स
- मेसर्ज पायल पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटिड
- पायल पोलिप्लास्ट्स प्राईवेट लिमिटिड.
- मेसर्ज दीपक नाईट्राईट लिमिटिड
- मेसर्ज अमर इंडस्ट्रियल सर्विसिज
- (9) जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकडे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था।
- (10) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृतान्त को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था।
- (11) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत तथा बिक्री की लागत का आकलन, सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (12) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। ऐसी सूचना को जो कि प्रकृति से गोपनीय है अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिसे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, इस मौजूदा निर्णय में उसके अगोपनीय वृतान्त सारांश के साथ रूप में ***गोपनीय माना गया है जो कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का परिचायक है और प्राधिकारी द्वारा उसे नियमों के अंतर्गत ऐसा विचारित किया गया है।
- (13) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 13.08.2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों तथा सार्वजनिक सुनवाई के

- बाद प्रस्तुत किए गए लिखित निवेदनों का जितना संभव हो सका है और प्रासंगिक समझा गया है, साक्ष्य के समर्थन से उतना निदान इस प्रकटन विवरण में कर दिया गया है।
- (14) नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 8 फरवरी, 2016 को जारी किए गए प्रकटन विवरण के माध्यम से इस मामले के अत्यावश्यक तथ्यों को प्रकट कर दिया है । निम्नलिखित पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और उनकी टिप्पणियों पर जितना प्रासंगिक समझा गया है, विचार किया गया है।
 - क. घरेलू उद्योग की ओर से मै0 टीपीएम कन्सलटेंट्स।
 - ख. पी टी पैट्रो ऑक्सो नुसांतरा, इंडोनेशिया और सोजित एशिया प्रा.लि., मै0 एल्ब्योरोनी और एस ए बी आई सी, सऊदी अरबिया, मै0 परस्ट्रोर्प ऑक्सो एबी, स्वीडन की ओर से मै0 लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन।
 - ग. ऑक्सिया जीएमबीएच और पैट्रोकैम मिडल ईस्ट एफजैडई की ओर से मै0 ईपीएल
 - घ. मै0 बीएएसएफ पैट्रोनास कैमिकल्स, मलेशिया।
 - ङ. दीपक नाइट्राइट लि0 की ओर से मै0 विश्वदीप एंड कंपनी।
 - च. इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसो0 और मै0 केएलजैड प्लास्टिसाइजर्स, पायल पोलीप्लास्ट, पायल पैट्रोकैम, पीसीएल ऑयल एंड साल्वेंट्स, ललिता कैम. रचना प्लास्टिसाइजर्स की ओर से मै0 एथिना लॉ एसोसिएट्स।
 - छ. नई दिल्ली में यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधिमंडल।
 - ज. विदेश व्यापार महानिदेशालय, इंडोनेशिया सरकार।
- (15) सहभागी घरेलू उत्पादक के साथ-साथ प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों का सत्यापन, जितना आवशयक समझा गया है और वृयवहार्य हो सका है, किया गया है।
- (16) जब कभी भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना है और जहां तक आवश्यक समझा गया है, उचित निर्धारण करने के लिए "उपलब्ध उत्तम आंकडों" का प्रयोग किया है।
- (17) यह जांच अप्रैल, 2013 से जून, 2014 (जांच अविध) तक की गई है। तथापि, क्षिति की जांच अविध में वर्ष 2010 –11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अविध (पीओआई) भी शामिल है।
- (18) जहां कहीं भी निर्यातकों के देशों/क्षेत्रों में लेनदेन के मूल्यों का परिवर्तन करना आवश्यक था, वहां सहयोगी निर्यातकों द्वारा उनसे संबंधित प्रश्नाविलयों के उत्तरों में यथा सूचित संबद्ध दैनिक अथवा भारित औसत विनमय दरों को अपनाया गया है। तथापि, भारतीय रुपयों में अन्य परिवर्तन करने के प्रयोजनार्थ जांच अविध (अप्रैल, 2013 जून, 2014) के लिए अपनाई गई भारित औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.77 रुपए है, जो कि उक्त अविध के लिए सीमा शुल्क के आंकडों के अनुसार है।
- (19) प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने नियमावली के नियम 17 के अनुसार इस जांच को पूरा करने के लिए इसकी समयाविध को 19 फरवरी, 2016 तक बढ़ा दिया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

- 5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद, "2-एथिल हेक्सानॉल" है। 2-एथिल हेक्सानॉल (जिसे संक्षेप में "2-ईएच" कहा जाता है), मूल आर्गेनिक रसायन है। यह गंध युक्त एक मोटा अल्कोहल, स्पष्ट, मोबाईल, न्यूटरल तरल पदार्थ होता है। 2-ईएच का विलयन करने, सुस्वाद और सुगंधमय बनाने जैसे अनेक अनुप्रयोगों के लिए व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से इमोलियन्टस और प्लास्टिसाईजर्स जैसे अन्य रासायनिकों के उत्पादन के लिए एक पूर्वगामी उपयोग के रूप में भी किया जाता है। 2-एथिल हेक्सानॉल का मुख्य अनुप्रयोग, कम वाण्यशीलता के ईस्टर्स का विनिर्माण करने में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भाग डीआई-(2-एथिल हेक्सल) पेथेलेट (डीओपी अथवा डीईएचपी) होता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 29051620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथािप, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्य नहीं है।
- 6. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं, उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रिक्तया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों जैसी विशेषताओं के साथ घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के समान हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग, उनके पारस्परिक प्रतिस्थापन के रूप में कर सकते हैं और कर रहे हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा उसके समान वस्तु के बारे में कोई तर्क-वितर्क नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि आयातित वस्तुएं और घरेलू रूप से निर्मित की जा रही संबद्ध वस्तुएं, तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए इन्हें पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तुएं" माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसका दर्जा

7. दि आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटिड द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है। इसलिए याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "घरेलू दर्जे" की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है तथा वह पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" बनता है। उसके घरेलू उद्योग होने के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क-वितर्क नहीं किया है।

घ. नामित देश, आयातों की मात्रा और न्यूनतम सीमाएं

- 8. यह जांच यूरोपीय यूनियन (ईयू), इंडोनेशिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सऊदी राज्य, चीनी ताइपेई तथा संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) से आरोपित पाटित आयातों के विरूद्ध शुरू की गई थी। 2-एथिल हेक्सानॉल नामक उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ के उप शीर्ष संख्या 29051620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्रमुख मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के आयात कांडला बन्दरगाह से होते हैं। लेकिन कांडला बन्दरगाह के आयातों से संबंधित डीजीसीआई एंड एस के आंकडों में व्यापक अंतर विद्यमान है। वर्ष 2010-11 को छोङ कर क्षति अवधि के लिए कांडला बन्दरगाह से प्राप्त किए गए आंकडे, डीजीसीआई एंड एस के आंकडों में सूचित किए गए आयातों की मात्रा से बहुताधिक हैं। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि डीजीसीआई एंड एस के आंकडों में कांडला बन्दरगाह के समग्र आयात कारोबार को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- 9. घरेलू उद्योग के तर्कों के आलोक में डीजीसीआई एंड एस और कांडला बन्दरगाह के प्राधिकारियों से प्राप्त किए गए आंकडों तथा प्रतिवादी निर्यातकों के कारोबार के आंकडों की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा स्वयं दिए गए उत्तरों के अनुसार कांडला बन्दरगाह से अत्यधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के आयात हुए हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से डीजीसीआई एंड एस के आंकडों में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए संबद्ध

वस्तुओं के आयातों की मात्रा की जांच करने के लिए जितना संभव हुआ है, इन समग्र आंकडों का समाधान किया गया है। इस निमित्त प्रयुक्त किए आंकडों को हितबद्ध पक्षकारों क लाभार्थ एक सार्वजनिक फोल्डर में भी रखा गया है।

- 10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदनों में यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को उन्हें आयात आंकड़ों की सॉफ्ट प्रतियों के साथ कारोबार को अभिज्ञात करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और समाधान किए गए विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयुक्त किये गये समग्र आंकड़े सार्वजनिक फोल्डर पर रखे गए थे और ये हितबद्ध पक्षकारों को उनकी जांच और टिप्पणियों के लिए उपलब्ध थे। इसलिए, पक्षकारों के ये निवेदन निराधार हैं।
- 11. उपरोक्त आयात के आंकडों के अनुसार संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा, नीचे तालिका में निर्दिष्ट की गई है। इन आंकडों के अनुसार कुल आयातों में प्रत्येक संबद्ध देश/क्षेत्र का हिस्सा, न्यूनतम स्तर से अधिक पाया गया है।

देश/मात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	जांच	जांच अवधि	जांच अवधि
(मी.टन)					अवधि	वार्षिकीकृत	में आयात में अंशदान
संबद्ध देश	1		I	1	1		
यूरोपीय यूनियन	10439	21427	17967	26248	39477	31582	28.91%
इंडोनेशिया	0	0	3900	16386	29549	23639	21.64%
कोरिया जन.							
गण.	171	0	2954	6413	6413	5130	4.70%
मलेशिया	4748	8506	17441	21954	26691	21353	19.55%
सऊदी अरब	13598	2602	12308	14208	17756	14205	13.00%
ताईवान	0	0	3019	6499	6499	5199	4.76%
संयुक्त राज्य							
अमरीका	1180	2039	0	4632	4632	3706	3.39%
उप योग	30137	34574	57588	96340	131017	104814	95.94%
अन्य देश	3146	2491	2116	2384	5540	4432	4.06%
कुल	33283	37065	59704	98724	136557	109246	100.00%

12. अन्य देशों से आयात न्यूनतम हैं। अन्य देशों से संचयी आयात भी संबद्ध देशों के आयातों से 7% से कम है, जबिक जांच अविध के दौरान किए गए कुल आयातों में संबद्ध देशों के आयात लगभग 96 % बनते हैं।

ङ. इस जांच में हितबद्ध पक्षकार

13. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों और अन्य निवेदनों के आधार पर तथा उपरोक्त पैरा-4 के उप-पैरा (6) और उप-पैरा (8) में सूचीबद्ध आयातकों को इस जांच में नामित देशों की सरकारों के साथ और भारत में घरेलू उद्योग को हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है। किसी भी अन्य पक्षकार ने प्राधिकारी के निर्णय का खंडन नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी उपर्युक्त स्थिति की संपुष्टि करते हैं।

च. हितबद्ध पक्षकारों के विविध निवेदन

14. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने निवेदनों में इस जांच के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिनमें घरेलू उद्योग के पाटन और क्षित के दावे भी शामिल हैं। जबिक पाटन और क्षित का निर्धारण करने से संबंधित मुद्दों का निदान, इस अंतिम निर्णय में उनसे संबंधित खंडों में किया गया है, फिर भी उठाए गए सामान्य प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों का निदान, नीचे किया गया है।

च. 1 गोपनीयता के दावे से संबंधित मुद्दे

(क) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 15. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रकटन पश्चात् विवरण सहित विविध निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:-
 - (क) यह कि याचिकादाता द्वारा डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयातों के ऐसे आंकडों की सॉफ्ट प्रति हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिन पर उसने विश्वास किया है, क्योंकि ऐसी सूचना की गोपनीयता रखने का कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता है।
 - (ख) यह कि प्रपत्र 4 क में उल्लिखित मूल्यह्रास, ब्याज पर व्यय, निबल अचल परिसम्पितयां, कार्यशील पूंजी, नियोजित पूंजी, निवेश, निबल मूल्य और विस्तार के लिए पूंजी निवेश जैसे प्राचलों की सूचना, सूचीबद्ध रूप में प्रदान नहीं की गई है।
 - (ग) यह कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए भी सामान्य मूल्य संरचित किया गया है और याचिका में सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए मुख्य कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का कोई प्रमाण और आंकडें प्रदान नहीं किए गए हैं।
 - (घ) यह कि लागत के प्रपत्र का सूचीबद्ध वृतान्त प्रदान नहीं किया गया है।
 - (ङ) यह कि क्षिति मार्जिन की सीमा और क्षिति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त क्रिया-विधि का प्रकटन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने अपनाई गई प्रतिलाभ की दर और आधार (क्या सकल अचल परिसम्पितियों अथवा निबल अचल परिसम्पितियों का प्रयोग किया गया है) का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने क्षितिरहित कीमत का निर्धारण करने में 270 दिनों के लिए क्रेडिट की लागत पर विचार करने के आधार का प्रकटन भी नहीं किया है, जबिक ऐसा करने की विधि में अनुमित नहीं है।
 - (च) यह कि याचिकादाता का संयंत्र जांच अवधि के किसी भी समय बंद हो गया था और उसने कच्चे माल की अनुपलब्धता से संबंधित घोर अडचनों का भी सामना किया था। याचिकादाता ने इन अंतरभूत कारकों का प्रकटन नहीं किया है और उसने इसका भी उल्लेख नहीं किया है कि संयंत्र के बंद होने की अवधि में उसने क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए व्यय का कैसे हिसाब लगाया था।
 - (छ) यह कि विश्वास की गई ऐसी सूचना पर तब तक प्रभावशाली निवेदन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है।

(ख) घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे तर्कों का खंडन किया है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि जितना संभव हो सका है, उसने दावा की गई गोपनीयता की सूचना का सार्थक संक्षिप्त विवरण सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध करा दिया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने अगोपनीय आधार पर प्रदत्त की गई ऐसी

सूचना को प्रदान करने की असमर्थता के लिए वैध कारणों का भी उल्लेख किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि निर्यातकों और आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है और इस प्रकार उन्होंने घरेलू उद्योग को कोई भी संरचनात्मक टिप्पणी देने से असमर्थ बनाए रखा है।

(ग) प्राधिकारी के विचार

- 17. प्राधिकारी ने जितना व्यवहार्य हो सका है, हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है। ऐसी सूचना की गोपनीयता को जो कि गोपनीय प्रकृति की है अथवा व्यवसाय की संवेदनशीलता के कारण जहां कहीं भी ऐसी गोपनीयता आवश्यक है, वहां प्राधिकारी की सुसंगत पद्धतियों के अनुसार उसे बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
- 18. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विश्वास किए गए आयात के आंकडों को सार्वजनिक फोल्डर में रखा गया है तथा उन्हें हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसलिए इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां वैध नहीं हैं।

च. 2 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

- 19. मेसर्ज एसएबीआईसी और एल्बायरोनी, सऊदी अरब के प्रतिनिधि, मेसर्ज लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरण तथा मेसर्ज पीटी पीओएन, इंडोनेशिया, मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच के प्रतिनिधि, मेसर्ज ईएलपी और मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट, सिंगापुर, मेसर्ज दीपक नाईट्राईट लिमिटिड के प्रतिनिधि मेसर्ज विश्वाद्वीप एंड कंपनी, इंडियन प्लास्टिसाईजर्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएट्स और आयातकों के प्रतिनिधि मेसर्ज एथिना लॉ एसोसिएट्स तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिनमें बीएएसएफ पेट्रोन्स, मलेशिया, व्यापार महानिदेशालय, यूरोपीय यूनियन (ईयू) और मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमआईटीआई) शामिल है, ने अपने संबंधित निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ इस जांच की शुरुआत करने तथा इस जांच के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित सामान्य निवेदन किए हैं:-
 - यह कि प्राधिकारी को स्वत: इस तथ्य से संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि पाटन और क्षित होने तथा नियम 5 के अनुसार जांच की शुरुआत को यथोचित मानने के लिए कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग, प्रमाणों की समग्रता, पर्याप्तता और सत्यता के परीक्षणों से संबंधित नियम 5 (1) और (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है, जैसा कि नियमावली में उल्लिखित ऐसा दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है।
 - यह कि जांच की शुरुआत करना और परवर्ती जांच करना गैर-कानूनी है, क्योंकि घरेलू उद्योग अधिनियम और नियमावली के विभिन्न उपबंधों को पूरा करने में विफल होने के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटन करने में भी विफल रहा है, क्योंकि उसका संयंत्र बंद था और कच्चा माल अनुपलब्ध था।
 - यह कि जांच की शुरुआत, एडीए के अनुच्छेद 12 और नियमावली के पैरा 6 में उल्लिखित मानकों को पूरा नहीं
 करती है, क्योंकि इसका कोई कारण बताए बिना कि मानक क्यों नहीं लागू होते हैं, आंकडों के संग्रहण की
 अविध को बारह महीनों से अधिक बढा दिया गया है। इस प्रकार बढाई गई जांच अविध में विशिष्ट परिस्थितियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
 - यह कि संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना ही याचिकादाता ने समस्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जो कि विधि में अनुमत्त नहीं है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने निर्यात कीमत के समायोजन के ब्यौरे प्रकट नहीं किए हैं और उसका प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है।
 - यह कि याचिकादाता द्वारा दावा किए गए संयंत्र के बंद होने से संबंधित लागत, अत्यधिक क्रेडिट लागत और प्रतिलाभ की दर से क्षति-रहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण संदेहासुपद प्रतीत होता है।

यह कि याचिकादाता ने क्षिति और कारणात्मक संबंध होने के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। यि याचिकादाता को कोई क्षित हुई है, तो ऐसा उसके अंतरभूत कारणों से हुआ है तथा कारणात्मक संबंध विद्यमान होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण जांच अविध के दौरान याचिकादाता का संयंत्र लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। इसलिए प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या पाटित आयातों के कारण अथवा अनुय कारणवश याचिकादाता को आर्थिक क्षिति हुई है।

च. 3 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे

- 20. घरेलू उद्योग ने एसोसिएशन और उपभोक्ताओं की ओर से किए गए निवेदनों का प्रतिवाद किया है और यह खंडन किया है कि एसोसिएशन और उपभोक्ताओं की भूमिका, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने मात्र तक सीमित नहीं हो सकती है। एसोसिएशन और उपभोक्ताओं का यह दायित्व होता है कि वे प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन ने वर्तमान जांच के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर अपनी टिप्पणियां देने के सिवाए कोई अन्य सूचना प्रदान नहीं की है।
- 21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिका के साथ संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है और यह पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं है, यह निवेदन किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच की शुरुआत करने के यथोचित होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट होने की आवश्यकता है।

च. 4 प्राधिकारी के विचार

- 22. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने के समय याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यता और पर्याप्तता तथा याचिका में क्षिति के दावों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों को नोट कर लिया है।
- जहां तक याचिका में निहित सूचना की सत्यता और पर्याप्तता तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच करने का 23. संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकादाता के पास यथा उपलबध तथा याचिकादाता द्वारा प्रसत्त प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर आयात के आंकडों, पाटन और क्षति मार्जिन के प्राक्कलनों और क्षति की सूचना के बारे में समस्त सूचना की विधिवत् जांच की गई है, तथा इस तथ्य पर संतुष्ट होने के बाद कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध विद्यमान हैं और इनकी आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत की है। जांच की शुरूआत करने के समय उपलब्ध सूचना, सभी पहलुओं से अथवा संपूर्ण नहीं हो सकती है । जांच की शुरूआत करने के चरण में परम आवश्यक यह है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में प्रदान की गई सूचना पर्याप्त होनी चाहिए । पाटन-रोधी जांच में आंकडों का संग्रहण करने की सतत प्रक्रिया और तब तक जांच करना निहित होता है, जब तक कि इस संबंध में अंतिम निर्धारण नहीं कर लिया जाता है। इसलिए आंकडों की असंगतता और अपर्याप्तता, यदि कोई है, के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया मुद्दे का समाधान, जांच की कार्रवाई के समय विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त आंकडों के आधार पर किया गया है। इस तर्क के संबंध में कि पर्याप्त कारण के बिना, जांच अवधि को 12 महीनों से अधिक समय के लिए बढा दिया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि को केवल 12 महीनों तक सीमित रखने की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है । मामले की वासुतविक स्थिति में प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत करने से निकटसुथ समय अवधि को ध्यान में रखते हुए आंकडों के संग्रहण की अवधि के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसलिए प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं।

- 24. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के बारे में कि जांच अविध के दौरान याचिकादाता उत्पादन में घाटा होने और संयंत्र के बंद होने के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देने में विफल रहा है और उसने समग्र क्षित के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी ठहराया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में जांच अविध में उत्पादन में घाटा होने के बारे में विस्तृत सूचना उसके कारणों के साथ निहित है। उक्त याचिका में याचिकादाता ने यह भी उल्लेख किया है कि उसने क्षिति मार्जिन का आकलन करने के लिए खर्च हुई कुल लागत में से निष्क्रिय समय की लागत को बाहर रखा है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं।
- 25. कारोबार-वार आयात आंकडों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्वास किए गए कारोबार-वार आयात के आंकडे सार्वजिनक फाईल में रखे गए थे और उन्हें हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
- 26. जहां तक पाटन का निर्धारण करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से सहभागी निर्यातकों से प्राप्त प्रश्नाविलयों के उत्तरों ने पाटन के बारे में घरेलू उद्योग के दावों को सिद्ध कर दिया है। तथापि, अंतिम रूप से निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ निर्यातकों द्वारा उनकी प्रश्नाविलयों के उत्तरों से प्राप्त हुए आंकडों का उपयोग किया गया है और इसलिए विभिन्न समायोजन आदि के बारे में याचिका में पूरी सूचना निर्दिष्ट नहीं होने के कारण निर्यातकों और आयातकों के हितों को किसी भी तरीके से संकट में नहीं डाला गया है।
- 27. इस जांच में एसोसिएशनों और प्रयोक्ताओं की भूमिका के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपत्तियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन पक्षकारों ने किसी भी प्रश्नावली का उत्तर दिए बिना जांच के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए ऐसे पक्षकारों के लिए प्रश्नावली का कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं और टिप्पणियों पर उतना ही विचार किया गया है, जितना प्रासंगिक समझा गया है और साक्ष्य से समर्थित है।
- 28. हितबद्ध पक्षकारों ने इंडोनेशिया सरकार और यूरोपीय कमीशन सहित अपनी प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों में उपरोक्त मुद्दों पर अधिकतर अपने संबंधित दृढ मत को दोहराया है। क्षति और क्षति मार्जिन के दावे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान इस अंतिम निर्णय में तत्संबंधी खंडों में किया गया है तथा संक्षिप्तता बनाए रखने के प्रयोजन से उनुहें यहां नहीं दोहराया जा रहा है।

छ. पाटन का निर्धारण

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटन-रोधी जांच शुरू करने से संबंधित निर्यातक की प्रशुनाविलयों के उत्तर प्रस्तृत किए हैं :-

(क)	मेसर्ज पीटी पेट्रो ओक्सो नूसन्तरा, इंडोनेशिया (पीटी पीओएन)
(ख)	मेसर्ज सोजिटज एशिया पेसिफिक प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर (सोजिटज)
(ग)	मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कोर्पोरेशन, सऊदी अरब (एसएबीआईसी)
(ঘ)	मेसर्ज एल-जुबैली फर्टेलाईजर्स कंपनी, सऊदी अरब (एल्बायरोनी)
(ভ)	मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच, जर्मनी (ओक्सिया)
(च)	मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई
(छ)	मेसर्ज बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (बीपीसी)
(ज)	मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य

(झ)	मेसर्ज एलजी केम लिमिटिड, कोरिया जनवादी गणराज्य (एलजी केम)
(অ)	मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका
(ट)	मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका

- 30. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न निवेदनों में यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में पाटन की मात्रा और सीमा के बारे में पर्याप्त और सही सूचना/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकादाता का संयंत्र वर्ष के लगभग 50 प्रतिशत समय के लिए बंद पड़ा हुआ था, प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए याचिकादाता की लागतों और परिवर्तन कारकों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उचित तुलना करने के लिए यह अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
- 31. इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातक, जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने प्रश्नावली के अपने उत्तर भी प्रस्तुत किए हैं, इसलिए सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमत का निर्धारण, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (6 क) के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान है कि ऐसे उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा बना कर रखे गए रिकार्डों के आधार पर ऐसे उत्पादक अथवा निर्यातक के संबंध में पाटन के मार्जिन का निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- 32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय घरेलू उद्योग ने अपने पास उचित रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर पाटन के प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रदान किए थे और प्राधिकारी ने संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटन के विद्यमान होने के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर यह जांच शुरू की थी। जहां तक सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए याचिकादाता की लागत को स्वीकार करने का संबंध है, प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लागत, संयंत्र के बंद होने के कारण प्रभावित हुई थी और इसलिए किसी प्रकार का निर्धारण करने के लिए वास्तविक लागत को स्वीकार नहीं किया गया है। उत्पादनके उपयुक्त स्तर पर लागत को सामान्य बनाया गया है।
- 33. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नाविलयों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिनका उपयोग उत्तर के पूर्ण होने की सीमा तक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया गया है और उनका विधिवत प्रलेखन किया गया है। जांच शुरूआत करने के प्रति उत्तर नहीं देने वाले असहयोगी निर्यातकों और देशों के लिए विभिन्न तत्वों का निर्धारण करने के लिए जितना संभव हो सका है, सहयोगी निर्यातकों के आंकडों का उपयोग, उपलब्ध उत्तम तथ्यों के रूप में किया गया है और इस प्रकार जैसा कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तर्क दिया है, सामान्य मूल्य की संरचना के कारण होने वाले संभावित विकार को दूर किया गया है।
- 34. उपरोक्त उत्पादकों और निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की गई थी और उसकी प्रारंभिक जांच के आधार पर उनसे अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों की यथा संभव जांच की गई है और सत्यापित आंकडों का उपयोग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

छ. 1 यूरोपीय यूनियन

35. आयात के आंकडों के अनुसार यूरोपीय यूनियन से 39477 मी.टन संबद्ध वस्तुओं के आयात किए गए हैं। यूरोपीय यूनियन से केवल एक उत्पादन कर्ता निर्यातक नामत: मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(क) मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच, यूरोपीय यूनियन

- 36. मेसर्ज ओक्सिया जीएमबीएच ने जिसकी मूल कंपनी ओमन ऑयल कंपनी एस.ए.ओ.सी., मुसकाट है, यूरोपीय यूनियन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। यह कंपनी प्रोपीलीन गैस और सिन गैस से ओक्सो-अल्कोहल का उत्पादन करती है। प्रोपीलीन की अधिप्राप्ति, वैश्चिक नफाटा/आशोधित कीमत से संबद्ध वैश्विक संविदाओं के माध्यम से व्यापारिक बाजार से की जाती है। ओक्सो-अल्कोहल अर्थात सिन गैस के उत्पादन के लिए अन्य विनिर्माता ब्लॉक को बाह्य स्रोत मेसर्ज {***} से प्राप्त किया जाता है, जिसका संयंत्र दीर्घावधिक करार के अंतर्गत ओक्सिया के फेक्टरी परिसर के भीतर अवस्थित है।
- 37. ओक्सिया जर्मनी के घरेलू बाजार यूरोपीय यूनियन में अन्य क्षेत्रों में संबद्ध वस्तुओं को बेचता है, जो कि एक मात्र यूरोपीय बाजार है और साथ ही यह यूनियन के बाहर विभिन्न देशों को भी निर्यात करता है जिनमें भारत भी शामिल है। जांच अविध के दौरान ओक्सिया ने तीन मध्यवर्ती कंपनियों नामत: मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई, मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई एक वितरक के रूप में कार्य करता है तथा मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका, फुटकर विक्रेताओं के रूप में कार्य करते हैं। इन सभी सत्वों ने अपनी संबंधित प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया था, ओक्सिया और उसके वितरकों/पुनर्विक्रेताओं से अनुपूरक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त हो गई है। ओक्सिया जीएमबीएच द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों का यथा संभव सत्यापन, जर्मनी में उनके संयंत्र और कार्यालय में मौके पर जांच करके किया गया है। समय की कमी के कारण वितरकों/पुनर्विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों को सत्यापित नहीं किया जा सका है। तथापि, इस निर्धारण के लिए ओक्सिया के सत्यापित आंकडों तथा उपरोक्त अनुसार वितरकों/पुनर्विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के साथ किया गया है।

सामान्य मूल्य : ओक्सिया

- 38. ओक्सिया ने यूरोपीय यूनियन में अपने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए परिशिष्ठ -1 में अपनी घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रदान किए हैं। परिशिष्ठ -1 के अनुसार जांच अविध के दौरान ओक्सिया ने यूरोपीय यूनियन में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुएं बेची हैं। केवल {***} मी.टन को ही ड्रमों में बेचा गया है और बाकी को बल्क रूप में बेचा गया है। इसलिए उचित तुलना करने के प्रयोजनार्थ घरेलू बाजार में केवल बल्क बिक्रियों पर ही विचार किया गया है।
- 39. विभिन्न देशों में विभिन्न असंबद्ध ग्राहकों को विभिन्न क्रेडिट अविध में एफओबी/एफसीए/सीपीटी/डीडीपी की शर्तों पर वस्तुएं बेची गई हैं। तदुनसार ओक्सिया ने घरेलू बाजार में कार्यगत बिक्री कीमत का आक्कलन करने के लिए घरेलू बिक्रियों के साथ लागू होने वाले समायोजन समायोजन निर्दिष्ट किया है। परिशिष्ठ-ख में यथा सूचित सत्यापित विनिर्माण की लागत और बिक्री के आधार पर सूचना मंगाई गई थी और बल्क रूप में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्धारण किया गया है, जो कि {यूरो***/मी.टन} है। ऑक्सिया ने लागत के परिकलन पर प्रतिवाद किया है और यह तर्क दिया है कि लागत का निर्धारण जर्मन के जीएएपी के अनुसार कंपनी द्वारा अनुलक्षित लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा सूचित समायोजन स्पष्ट रूप से जर्मन जीएएपी में प्रदान किए

गए हैं और उनकी संपुष्टि प्राधिकृत सरकारी लेखाकार द्वारा की गई है। इसलिए प्राधिकारी को जर्मन जीएएपी के अनुसार कंपरी द्वारा अनुरक्षित लागत को सत्यापन रिपोर्ट में कोई कारण बताए बिना अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए। प्राधिकारी को उनके द्वारा अनुरक्षित लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का पुन: परिकलन करना चाहिए।

- 40. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की लागत का निर्धारण यथा सत्यापित कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार लागत के विभिन्न तत्वों पर विचार करने के बाद किया गया है। तथापि, कुछ नकारात्मक आंकड़े जैसे कि आय से संबंधित बिक्रियों और आय से संबंधित परिसंपत्तियों, जिनको को अन्य व्यय में शामिल किया गया है, को हटा दिया गया है क्योंकि उनके फलस्वरूप परिव्यय में कटौती हो रही थी और वे वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करते थे क्योंकि इसी सिद्धांत का अनुपालन घरेलू उद्योग की एनआईपी का निर्धारण करने के लिए भी किया गया है।
- 41. ओक्सिया ने जहां कहीं भी वास्तविक रूप से लागू होता है, वहां अंतर्र्देशीय भाडे और बीमे के लिए समायोजन करने का दावा किया है। साथ ही कंपनी ने कुछ किल्पत परिकलन के आधार पर की ईयू {***} /मी. टन की दर से हैंडलिंग व्ययों का भी दावा किया है। तथापि, ऐसे दावे अधिकतर आर्डर के संसाधन व्यय के लिए होते हैं और इसका कुछ भाग ही सामग्री की हैंडलिंग के कार्यगत व्यय अर्थात् नदी के घाट पर लाई गई वस्तुओं के लिए पंपिंग और पाईपलाईन की लागत से सीधा संबंधित होता है। कंपनी ने दावा किया है कि समान रूप से निर्यात कारोबार सिहत सभी कारोबार के लिए ऐसा किल्पत समायोजन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कार्यगत कीमतों का आकलन करने के लिए आर्डर के संसाधन व्यय, समायोजन के लिए वैध दावे नहीं हैं। चूंकि अंतर-यूरोपीय यूनियन की घरेलू बिक्रियों के साथ-साथ निर्यात बिक्रियां अधिकतर नदी के घाट पर होती हैं, सभी प्रकार की तुलना नदी घाट के स्तर पर करने का प्रस्तावित है और इसलिए पंपिंग और पाईप लाईनों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए उनको समायोजित नहीं किया गया है।
- 42. उपरोक्त के अतिरिक्त ओक्सिया ने घरेलू बिक्रियों पर आपूर्ति पश्चात क्रेडिट लागत के समायोजन का भी दावा किया है क्योंकि ये विभिन्न क्रेडिट अवधि के हैं। जांच अवधि के दौरान लागू एलआईबीओआर + विस्तार के आधार पर परिकलित क्रेडिट व्यय, ऐसे समायोजन पर लागू किया गया है ताकि उचित तुलना करने के प्रयोजनार्थ नदी घाट-गत कीमतों का आकृकलन किया जा सके।

रो लेबिल्स	मात्रा का योग (मी.टन)	कुल बीजक मूल्य (यूरो)	कुल समायोजन (यूरो)	निबल मूल्य का योग (यूरो)	निबल मूल्य का योग (यूएसडी)	सामान्य मूल्य यूएस\$/एमटी
कुल बल्क बिक्रियां	***	***	***	***	***	***
लाभप्रद बिक्रियां	***	***	***	***	***	***

निर्यात कीमत: मेसर्ज पेट्रोकम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई, मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से ओक्सिया

43. ओक्सिया ने तीन असंबद्घ वितरकों/पुनर्विक्रेताओं नामत: मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, दुबई, मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से भारत में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए थे। इन सभी सत्वों ने अपनी संबंधित प्रश्नाविलयों के उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। जांच अविध के दौरान भारत में केवल एक किस्म के उत्पाद अर्थात् 50020050-2-ई एथिलएक्सनॉल (बल्क में) का निर्यात किया गया है। सभी कारोबार एफओबी की शर्त पर किए गए

- हैं। एलसी/टीटी के आधार पर भुगतान किया गया है जो कि वितरकों/पुनर्विक्रेताओं के लिए 60 से 90 दिनों तक की भिन्न क्रेडिट अवधि है। वितरकों/पुनर्विक्रेताओं ने ऐसी वस्तुओं को इन्हीं शर्तों पर भारत में उपभोक्ताओं को पुन: बेचा है।
- 44. आंतरिक परिवहन परिवहन और बीमा पर होने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है और उसे कार्यगत कीमतें प्राप्त करने के लिए सत्यापित किया गया है। ऐसे निर्यात संयंत्र के साथ-साथ नदी घाट से किए गए हैं। चूंकि अंतरा-यूरोपीय यूनियन की घरेलू बिक्रियां भी नदी घाट से की गई हैं, नदी घाट के स्तर पर सभी तुलनाएं की गई हैं और इसलिए पाईपलाईन के रख-रखाव और पंपिंग लागत के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।
- 45. ओक्सिया ने एलसी पर परक्रामण किया है और क्रेडिट अवधि सत्यापित होने के बाद टीटी का भुगतान किया है। क्रेडिट की दिनों की संख्या और जांच अवधि के दौरान लागू एलआईबीओआर + विस्तार के आधार पर क्रेडिट लागत का परिकलन किया गया है, तािक निर्यात बिक्री कीमतों को समायोजित किया जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त एलसी पर परक्रामण करने पर हुए बैंक व्यय को भी समायोजित किया गया है तािक नदी घाट के स्तर पर निबल निर्यात कीमत का आक्कलन किया जा सके। तदनुसार ओक्सिया के नदी घाट गत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

रो लेबिल्स	मात्रा का योग (मी.टन)	कुल बीजक मूल्य (यूरो)	कुल समायोजन (यूरो)	निबल मूल्य का योग (यूरो)	निबल मूल्य का योग (यूएसडी)	सामान्य मूल्य यूएस\$/एम टी
50020050-2- एथिलएक्सनॉल	***	***	***	***	***	***
आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन	***	***	***	***	***	***
पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई	***	***	***	***	***	***
विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड	***	***	***	***	***	***
कुल योग	***	***	***	***	***	***

पाटन मार्जिन : ओक्सिया

46. इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना उसी स्तर पर निवल निर्यात कीमत के साथ की गई है ताकि पाटित मार्जिन तय किया जा सके, जो कि निम्नानुसार है :-

रो लेबिल्स	मात्रा का योग	निबल ईपी यूएस\$/मी.ट	निबल मूल्य यूएस\$/ मी.ट.	पाटन मार्जिन यूएस\$/ मी.ट.	पाटन मार्जि न %	पाटन मार्जिन की सीमा
आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन	***	***	***	***		
पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई	***	***	***	***		
विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड	***	***	***	***		
कुल योग	***	***	***	***	***%	25-35%

(ख) यूरोपीय यूनियन से सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक

47. यूरोपीय यूनियन में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, सहयोगी निर्यातकों के आंकडों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस\$/मी.ट	निबल ईपी यूएस\$/मी. ट.	पाटन मार्जिन यूएस\$/मी. ट.	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***	30- 40%

छ. 2 मलेशिया

48. आयात आंकडों के अनुसार जांच अवधि के दौरान मलेशिया से 2669 मी. टन संबंध वस्तुओं के आयात किए गए थे। मलेशिया में केवल एक निर्यातक, नामत: मेसर्ज बीएएसएफ, पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी ने मलेशिया से उत्पादक और निर्यातक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(क) बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (बीपीसी) – उत्पादक और निर्यातक

- 49. बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (बीपीसी) मलेशिया आधारित एक ऐसा संयुक्त उद्यम है, जो कि बीएएसएफ एसई, जर्मनी और पेट्रोलियम नेशनल बरहाड (पेट्रोनास), मलेशिया के बीच उसकी सहायक कंपनी पेट्रोनास केमिकल्स ग्रुप (पीसीजी) के अंतर्गत स्थापित है। बीपीसी प्राकृति गैस और प्रोपीलीन से संबद्ध वस्तुएं निर्मित करती है। प्रोपीलीन के प्रमुख भाग की अधिप्राप्ति, पेट्रोनास, मलेशिया से ऐसे सूत्र के आधार पर दीर्घावधिक कीमत प्रबंधन के अंतर्गत पाईपलाईन के माध्यम से की जाती है, जिसमें यूएस गल्फ सीएफआर संविदा कीमत, यूरोपीय सीएफआर संविदा कीमत और दक्षिण पूर्व क्षेत्र सीएफआर स्पॉट कीमत के मिश्रण सहित संविदा की शर्त पर भाडे का समायोजन करना शामिल है और ऐसी दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। कंपनी इसी प्रकार की शर्तों पर मित्सुई एंड कंपनी लिमिटिड से भी प्रोपीलीन की अधिप्राप्ति करती है। विभिन्न क्षेत्रों पर लागू सरकार की विनियमित कीमत पर प्राकृतिक गैस की अधिप्राप्ति पेट्रोनास से भी की जाती है। दोनों प्रकार का कच्चा माल पाईपलाईन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इसे सीधे रिएक्टर पर आवेशित किया जाता है।
- 50. बीपीसी सीधे घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजारों में वस्तुएं बेचती है, जिसमें भारत भी शामिल है। बीपीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर उसे अतिरिक्त सूचना प्रेषित करने को कहा गया था, जो कि उसने प्रस्तुत कर दी है। बीपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को भी यथा आवश्यक मलेशिया में मौके पर जांच करके सत्यापित किया गया है। तदनुसार सत्यापित आंकडों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

सामान्य मूल्य : बीपीसी

- 51. बीपीसी ने जांच अवधि के दौरान {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के कुल मूल्य के {***} कारोबार की तुलना में घरेलू बाजार में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की थी । सभी बिक्रियां सीधे असंबद्ध अंत प्रयोक्ताओं को की गई थीं। उत्पादक की उत्पादन लागत का निर्धारण, सत्यापित लागत आंकडों के आधार पर किया गया था तथा {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर/मी.टन के रूप में उत्पादक से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्रियों के कारोबार, संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों की उपरोक्त सत्यापित लागत के आधार पर सामान्य व्यापारिक परीक्षण के अध्यधीन था।
- 52. निर्यातक ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदनों में बिक्रियों की लागत का निर्धारण करने का खंडन किया है और साथ ही यह उल्लेख किया है कि ऐसे निर्धारण और सामान्य व्यापार परीक्षण के दौरान कुछ असंगतियां हुई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्रियों की लागत का निर्धारण उत्पादक के सभी सत्यापित लेखाकरण के आंकड़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। तथापि, सामान्य मूल्य के परिकलन में हुई गलतियों को आशोधित कर दिया गया है और यह पाया गया है घरेलू बिक्रियों की {***} % लाभप्रद बिक्रियां तथा सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया लाभप्रद पायी गई हैं। इसलिए इस उत्पादन करने वाले निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्रियों के कारोबार पर विचार किया गया है।
- 53. वस्तुओं की बिक्री संबद्ध घरेलू ग्राहकों को वितरण के आधार पर बेचा गया था और इनकी आपूर्तियां टेंकरों (आईएसओ टैंकों)में की गई थीं। घरेलू ग्राहकों की अधिकतर बीजक मासिक आधार पर थीं और बीजक के महीने के दूसरे महीने के अंत तक भुगतान राशि प्राप्त की गई थी। इसलिए इनमें कोई क्रेडिट व्यय नहीं किया गया है। समायोजन के लिए घरेलू कारोबार में केवल अंतरदेशीय भाडा व्यय तथा बैंक प्रभार और पैकेजिंग शामिल हैं, तािक कार्य-गत की मतें तय की जा सकें।
- 54. इन वास्तविक व्यय के अतिरिक्त कंपनी ने बीजक के {***} % की दर से घरेलू बिक्री कीमतों में व्यापारिक समायोजन के स्तर का भी दावा इस आधार पर किया है कि घरेलू बिक्रियां सीधे अंत प्रयोक्ताओं को की जाती हैं,

जबिक भारत में निर्यात बिक्रियों में बीएएसएफ, भारत को {***} % का कमीशन देना निहित होता है, जो कि उनके बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करती है। तथापि, यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता था कि इसका घरेलू बाजार की कीमतों अथवा निर्यात बाजार पर कैसे प्रभाव पडता है तथा इसलिए यह कीमत की तुलना क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार बीपीसी का कार्य-गत सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

बीएएसएफ	मात्रा का योग (मी.टन)	कुल बीजक मूल्य (यूरो)	कुल समायोजन (यूरो)	निबल मूल्य का योग यूएस \$	निबल मूल् य यूएस \$/मी.टन
समस्त बिक्रियां	***	***	***	***	***
लाभप्रद बिक्रियां	***	***	***	***	***

निर्यात कीमत : बीपीसी

- 55. जांच अवधि के दौरान कंपनी ने {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के कुल मूल्य के {***} कारोबार की तुलना में भारत में असंबद्ध ग्राहकों को {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। ऐसी बिक्रियां, भारत में सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की जाती हैं, जो कि उनको बल्क में खरीदते हैं। ऐसे कारोबार के बारे में वार्ता बीएएसएफ, भारत द्वारा की जाती है और उसके बदले में बीएएसएफ, भारत को प्रत्येक कारोबार के लिए बीजक मूल्य के {***} % कमीशन का भुगतान किया जाता है। निर्यात बिक्रियों के ऐसे कारोबार, सीआईएफ शर्तों पर किए गए थे। बन्दरगाह के प्राधिकारी द्वारा बना कर रखी गई पाईप लाईन और जेटी द्वारा वस्तुओं को सीधे समुद्री जहाज में पंप किया जाता है जिसके लिए प्रयोक्ता शुल्क प्रभारित किया जाता है तथा इसे बन्दरगाह के प्राधिकारी के प्रभारों में शामिल किया जाता है। बन्दरगाह के प्राधिकारी के प्रभारों के प्रभारों/पाईप लाईन प्रभारों, पर्यवेक्षक प्रभारों, सीमाशुल्क क्लीयरेंस प्रभारों, नौवहन एजेंट के प्रभारों आदि के रूप में अन्य व्यय और समुद्री भाडे के समायोजन के बारे में सामूहिक रूप से सूचित किया गया था, क्योंकि अंतरदेशीय प्रभारों को दस्तावेजों के साथ-साथ प्रणाली से सत्यापित किया गया था। कंपनी समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों और सीमाशुल्क आदि पर भी खर्च करती है जिसे अन्य व्यय के रूप में सामूहिक रूप से सूचित किया गया है।
- 56. भारत में निर्यात बिक्रियां या तो एलसी अथवा डीए की शर्तों पर की जाती है जिनकी क्रेडिट अविध 60 दिनों की होती है, जिसके लिए केएलआईबीओआर + 1.75 % के विस्तार के आधार पर समायोजन किया गया है। कुछ कारोबार के लिए अतिरिक्त क्रेडिट अविध को बीपीसी ने एलआईबीओआर की दरों पर ब्याज के भुगतान के साथ 180 दिनों तक बढ़ा दिया है। इसलिए ब्याज के भुगतान के साथ बढ़ाई गई क्रेडिट की अविध के लिए कार्य-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत तय करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। तदनुसार तय की गई निबल कार्य-गत निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

मात्रा का योग मी.टन	निबल बीजक मूल्य का योग	कुल समायोजन का योग यूएस \$	निबल मूल् य यूएस \$	ईपी यूएस \$/ मी.टन
***	***	***	***	***

पाटन मार्जिन : बीपीसी

57. कार्य-गत स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना, निबल कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है ताकि पाटन मार्जिन तय किया जा सके जो कि निम्नानुसार है :-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
बीपीसी	बीपीसी	***	***	***	***%	0-10%

(ख) मलेशिया से सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक

58. मलेशिया में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, सहयोगी निर्यातक के आंकडों को ध्यान में रख कर, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	20-30%

छ. 3 दक्षिण कोरिया

59. आयात के आंकडों के अनुसार जांच अवधि के दौरान कोरिया जनवादी गणराज्य से 6413 मी.टन संबद्ध वस्तुओं के आयात किए गए थे। केवल मेसर्ज एलजी केम, कोरिया ने कोरिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(क) एलजी केम लिमिटिड, कोरिया जनवादी गणराज्य

- 60. एलजी केम लिमिटिड, कोरिया जिसने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, ने मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया और मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं के पुनर्विकेता के रूप में पृथक प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत किए हैं, के माध्यम से भारत में निर्यात किए थे।
- 61. एलजी केम प्रोपीलीन और सिन गैस से निर्मित सामान्य ब्यूटिल एल्डेहाईड बल्क से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। एलजी केम का अपना निजी नाप्था क्रेकर है, जो कि प्रोपीलीन का उत्पादन करने के लिए पहले उसी परिसर में अवस्थित था, जिसे अब 2 ईएच/ब्यूटानोल, एक्रेलिक एसिड और आईपीए का उत्पादन करने के लिए

लागत आधार पर ओक्सो अल्कोहल परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है । नाप्था की अधिप्राप्ति अन्य ऑयल कंपनी से की जाती है, जो कि समीप अवस्थित है और साथ ही विशेष मात्रा में इसका आयात भी किया जाता है । समीप अवस्थित ऑयल कंपनी से वेक्यूम गैस की अधिप्राप्ति भी की जाती है । मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन नामक अपने एक निर्यातक के साथ कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों की जितना व्यवहार्य था, स्थल पर जांच की गई थी और ऐसे सत्यापित आंकडों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है ।

सामान्य मूल्य: एलजी केम

- 62. एलजी केम घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुएं बेचती है और सामान्य मूल्य का दावा, गृह बाजार में विक्रियों के आधार पर किया गया है। जांच अविध के दौरान एलजी केम ने {***} कारोबार की तुलना में {***} मी. टन संबद्ध वस्तुओं को सीधे असंबद्ध अंत प्रयोक्ता के साथ-साथ वितरकों को बेचा है। ऐसी घरेलू बिक्रियां बल्क और ड्रमों में पैक दोनों रूप में की गई हैं, जो कि कुल बिक्रियों का {*** %} है। भारत में केवल बल्क में निर्यात किए गए हैं। इसलिए उचित तुलना करने के लिए घरेलू बाजार में की गई केवल बल्क बिक्रियों पर विचार किया गया है। घरेलू बिक्रियां, निर्माण और बिक्री की सत्यापित लागत के आधार पर सामान्य व्यापारिक परीक्षण प्रक्रिया के अध्यधीन थीं। घरेलू बाजार में {*** %} बल्क बिक्रियों को लाभप्रद पाया गया था। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया गया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में सीधे अंत प्रयोक्ताओं और वितरकों को वस्तुएं बेची हैं। भारत में निर्यात बिक्रियां केवल पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से की गई हैं। गृह बाजार में वितरकों/पुनर्विक्रेताओं को बेची गई मात्रा अधिक है। चूंकि गृह बाजार में अंत प्रयोक्ताओं और वितरकों/पुनर्विक्रेताओं की कीमतों के बीच व्यापक अंतर विद्यमान है, इसलिए कीमतों की उचित तुलना करने के प्रयोजन से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए वितरकों/पुनर्विक्रेताओं की कीमतों के साथ-साथ वितरकों/पुनर्विक्रेताओं को की गई निर्यात बिक्रियों पर विचार किया गया है।
- 63. घरेलू बिक्री कीमतों को सभी सीधी बिक्री व्ययों के लिए समायोजित किया गया है, जैसे कि जहां कहीं भी लागू होता है, परिवहन और पैकेजिंग व्यय तथा क्रेडिट व्यय ताकि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निबल कार्यगत कीमतें तय की जा सकें। तदनुसार एलजी केम के लिए स्थानीय वितरकों/पुनर्विक्रेताओं को लाभप्रद बिक्रियों के आधार पर निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य निम्नानुसार है:-

रो लेबिल्स	मात्रा का योग मी.टन	निबल बीजक मूल्य का योग केआरडब्ल्यू	कारखाना-गत का योग आरडब्ल्यू	कारखानागत का योग यूएस \$	कीमत यूएस \$/ मी.टन
कुल बल्क बिक्रियां	***	***	***	***	***
लाभप्रद बिक्रियां	***	***	***	***	***
अंत प्रयोक्ता	***	***	***	***	***
स्थानीय वितरक	***	***	***	***	***

निर्यात कीमत : एलजी केम के साथ मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया

- 64. जांच अविध के दौरान एलजी केम ने {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के कुल मूल्य के {***} कारोबार की तुलना में भारत में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। ऐसे निर्यातों में से केवल {***} कारोबार की संबद्ध वस्तुएं जो कि {***} मी.टन थी, मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से बेची गई थीं और शेष मात्रा मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया के माध्यम से बेची गई थी। एलजी केम ने संबंधित व्यापारियों/निर्यातकों को कोरिया में बन्दरगाह पर एफओबी की शर्त पर वस्तुएं बेची हैं तथा उसने बन्दरगाह तक होने सभी व्यय का वहन किया है। कंपनी ने निरीक्षण शुल्क, अंतरदेशीय भाडे, हैंडलिंग प्रभार, क्रेडिट व्यय, बैंक प्रभार और सीमा शुल्क के एजेंट के शुल्क, जहां कहीं भी लागू होता है, का समायोजन करने की सूचना प्रदान की है। संयंत्र से सीधे बन्दरगाह पर पम्प से प्रवाहित प्रेषणों के लिए कंपनी ने पंपिंग की लागत का वहन किया है, जिसे निर्यात कीमत में समायोजन करने के लिए शामिल किया गया है।
- 65. कंपनी ने जांच अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए कुल निर्यातों और कुल दावों पर आधारित निर्यात पर उसको प्राप्त हुई वापसी की राशि के लिए सकारात्मक समायोजन किए जाने का भी दावा किया है। तथापि, कंपनी भारत में किए गए निर्यातों के लिए वापस प्राप्त हुई राशि के दावों के लिए समर्थक दस्तावेज नहीं प्रदान कर सकी है और ऐसे दावे का आधार नहीं बता सकी है। इसलिए प्राप्त हुई वापसी धनराशि के समायोजन के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार एलजी केम और उसके निर्यातकों के लिए तय की गई कार्यगत निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

बिक्रियों के माध्यम	मात्रा का योग कि.ग्रा. में	निबल बीजक मूल्य का योग केआरडब्ल्यू	डीबीके केडब्ल्यूएन को स्वीकृत किए बिना निबल कार्य-गत का योग	निबल कार्य- गत का योग यूएस \$	निबल निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन
एएल2ईएचबी	***	***	***	***	***
हुंडाई कोर्पोरेशन	***	***	***	***	***
विन्मार	***	***	***	***	***
कुल योग	***	***	***	***	***

पाटन मार्जिन : एलजी केम के साथ मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड, संयुक्त राज्य अमरीका और मेसर्ज हुंडाई कोर्पोरेशन, कोरिया

66. कार्य-गत स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना, निबल कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है ताकि पाटन मार्जिन तय किया जा सके जो कि निम्नानुसार:

रो लेबिल्स	मात्रा का योग कि.ग्रा. में	निबल बीजक मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
एएल2ईएचबी	***	***	***	***		
हुंडाई कोर्पोरेशन	***	***	***	***		

विन्मार	***	***	***	***			Ì
कुल योग	***	***	***	***	***%	0-10%	

(ख) कोरिया जनवादी गणराज्य में सभी अन्य निर्यातक

67. कोरिया जनवादी गणराज्य में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, सहयोगी निर्यातक के आंकडों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	10-20%

68. न एल जी कैम और न ही कोरिया जनवादी गणराज्य से किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और इसलिए कोरिया जनवादी गणराज्य के संबंध में निर्धारण पर कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है। इसलिए इस निर्धारण की संपुष्टि की जाती है।

छ. 4 इंडोनेशिया

69. आयात आंकडों के अनुसार जांच अविध के दौरान इंडोनेशिया से 25,763 मी.टन संबद्ध वस्तुओं के आयात किए गए थे। मेसर्ज पी टी पेट्रो ओक्सो नुसान्तरा (पीओएन) ने, जो कि इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। जांच अविध के दौरान इस उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यात सीधे भारत को किए थे और साथ ही उसने इनके निर्यात, मेसर्ज सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर के माध्यम से भी किए थे। संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक के रूप में मेसर्ज सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर ने भी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इन दोनों पक्षकारों की उनके पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए जांच की गई है।

(क) पीटी, पेट्रो ओक्सो नूसान्तरा (पीटी पीओएन)

70. मेसर्ज पीटी, पेट्रो ओक्सो नूसान्तरा (पीटी पीओएन) जो कि इंडोनेशिया में सरकारी क्षेत्र का एक संयुक्त उद्यम है, इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख उत्पादक है और यह इंडोनेशिया में अपने से संबंधित निचले स्तर तक के उत्पादकों को वस्तुओं की आपूर्ति करती है तथा भारत सिहत विभिन्न देशों को निर्यात करती है । इसका मुख्य कच्चा माल प्रोपीलीन है, जो आयातित किया जाता है अथवा देश में ही असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से संविदात्मक शर्तों या स्थल पर भुगतान करने पर खरीदा जाता है तथा टेंकर समुद्री जहाजों से आयातित किया जाता है । प्राकृति गैस की अधिप्राप्ति सरकारी स्वामित्वाधीन कंपनी के साथ-साथ निजी स्रोत से की जाती है । मेसर्ज पीटी पीओएन और सोजिटज एशिया द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों को यथा संभव और यथा आवश्यक उनके परिसरों में स्थल पर जांच करने से सत्यापित किया गया था तथा इस उत्पादक और निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण, सत्यापित आंकडों के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नानुसार है ।

सामान्य मूल्य : पीटी पीओएन

- 71. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज पीटी पीओएन ने {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के कुल मूल्य के {***} कारोबार की तुलना में घरेलू बाजार में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं को बेचा था। जांच अवधि के दौरान कंपनी की समग्र घरेलू बिक्रियां, इंडोनेशिया में उसकी दो संबद्ध कंपनियों, नामत: मेसर्ज {***} और मेसर्ज {***} को की गई हैं। कंपनी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ये दोनों कंपनियां संबद्ध वस्तुओं का उपयोग, प्लास्टिकसाईजर्स (डिओक्टाईल प्थालेट) जैसे अन्य उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए करती हैं। यह बताया गया है कि संबंधित क्रेता, ऐसी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करती हैं और वे किसी अन्य कंपनी को इन वस्तुओं की पुन: बिक्री नहीं करती हैं तथा इसलिए घरेलू बाजार में इन संबंधित पक्षकारों की पुन:बिक्री की कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। चूंकि क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध स्थापित होने के कारण घरेलू बिक्रियां प्रभावित होती हैं तथा घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं होती है, इसलिए निकट स्थित तृतीय देश में पीटी पीओएन के निर्यात कारोबार की भी जांच की गई है।
- 72. मेसर्ज पीटी पीओएन ने तृतीय देश के बाजारों में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं को बेचा था जिनमें से {*** %} वस्तुओं को चीन में बेचा गया था। चीन में ऐसे निर्यात बहुत कीमत पर किए गए थे और चीन के एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण उसे बाजार में ऐसी कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तृतीय देश नहीं माना गया है। जांच अविध के दौरान पीटी पीओएन ने चीन के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया को भी {***} मी.टन संबद्ध वस्तुएं बेची हैं। हालांकि कंपनी के तृतीय देश को किए गए कुल निर्यात की तुलना में आस्ट्रेलिया को बेची गई वस्तुओं का प्रतिशत तुच्छ मात्र है, लेकिन भारत को किए गए निर्यात की तुलना में उसकी मात्रा अधिक है। आस्ट्रेलिया के एक बाजार-अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण प्राधिकारी का, अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आस्ट्रेलिया को तृतीय देश के निर्यात के रूप में अपनाए जाने का प्रस्ताव है।
- 73. पीटी पीओएन ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदनों में यह तर्क दिया है कि उनकी घरेलू बिक्रियों पर उसके सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड में उपलब्ध किसी भी प्रमाण से ऐसा पता नहीं चलता है कि पी टी पीओएन की घरेलू बाजार में उससे संबद्ध कंपनियों को बिक्रियां की गई हैं जोकि उसके पास ही स्थित हैं। इसके विकल्प के रूप में पीटी पीओएन के उत्पादन की लागत पर उसके सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उसे विधिवत सत्यापित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि यदि प्राधिकारी तृतीय देश को पीटी पीओएन की बिक्रियों पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहते हैं तो चीन को उसके निर्यात पर भी ऐसा निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि चीन को किए गए निर्यात उत्पादन की लागत से अधिक हैं। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य को किए गए निर्यातों को गलत तरीके से ध्यान में नहीं रखा है। यह तर्क दिया गया है कि आस्ट्रेलिया को किए गए निर्यात उसके चीन जनवादी गणराज्य को किए गए निर्यातों की तुलना में नगण्य हैं और इसलिए वे तुलनात्मक कीमत के परिचायक नहीं हैं और वे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के पर्याप्तता परीक्षण को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि ये बिक्रियां भारत में किए गए निर्यातों के 5 प्रतिशत से कम हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आस्ट्रेलिया को किए गए निर्यात बल्क रूप में नहीं हैं, इसलिए वे भारतीय बिक्रियों के तुलनीय नहीं हैं।
- 74. पीटी पीओएन ने यह भी निवेदन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय आस्ट्रेलिया के सभी निर्यात कारोबारों को ध्यान में नहीं रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केम आस्ट्रेलिया प्रा0िल0 को किए गए चार कारोबार जोकि वास्तिवक रूप में आस्ट्रेलिया को भेजे गए थे, को गलती से सिंगापुर और चीन को किए गए निर्यातों के रूप में ले लिया गया है। यदि इन सभी कारोबारों को पीटी पीओएन के लिए पाटन मार्जिन के रूप में माना जाता है तो ये न्यूनतम होंगे अथवा शुन्य होंगे।
- 75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चूंकि पीटी पीओएन को संबद्ध वस्तुओं की समग्र घरेलू बिक्रियां, इंडोनेशिया में संबंधित पक्षकारों से संबंधित है, जोकि बदले में उन्हें निचले स्तर के उत्पादन के लिए प्रयुक्त करती हैं, इसलिए इंडोनेशिया में पुनर्बिक्री की कीमत से उनकी संरचना करके सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए यह कोई साधन के रूप में उपलब्ध नहीं थीं। इंडोनेशिया में ऐसी कोई अन्य घरेलू बिक्री नहीं की गई थी जोकि ऐसा निर्धारण करने के लिए एक आधार प्रस्तुत कर सकती थी। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, सामान्य मूल्य का निर्धारण

करने के लिए ए डी ए के अनुच्छेद 2.2 में एक अनुक्रम तंत्र उपलब्ध है। इसलिए पहला विकल्प यह है कि कंपनी को तृतीय देश के निर्यात पर उत्पादक के उत्पादन की लागत पर आधारित सामान्य मूल्य की संरचना के दूसरे विकल्प पर विचार करने से पहले कंपनी को तृतीय देश के निर्यातों पर विचार किया जाए। इसलिए, ऐसा निर्धारण करने के लिए तृतीय देश की बिक्रियों की जांच की गई थी। चूंकि इस उत्पादक निर्यातक ने तृतीय देश को अत्यधिक निर्यात किए थे, सर्वाधिक निर्यात चीन को किये गए हैं, जोकि गैर बाजार अर्थव्यवस्था में कार्य करता है। इसलिए चीन को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त तृतीय देश के रूप में नहीं अपनाया गया है, क्योंकि उस देश में बिक्री कीमत में देश में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशा द्वारा प्रभावित होने की संभावना है।

- 76. निर्यातक के इन तर्कों के संबंध में कि आस्ट्रेलिया को किए गए निर्यात पर्याप्तता के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 2.2 के नीचे दी गई पाद टिप्पणी में प्राधिकारी को यह लोचशीलता और विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि वे कम अनुपात को स्वीकार कर सकते हैं। यहां प्रमाण से ऐसा पता चलता है कि ऐसा कम अनुपात पर्याप्त मात्रा से कम नहीं है ताकि उचित तुलना की जा सके। इसलिए, आस्ट्रेलिया को किए गए निर्यात की मात्रा पर विचार करते हुए उसे सामान्य मूल्य का निर्धारण और उसकी सार्थक तुलना करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।
- 77. प्राधिकारी ने निर्यातक के इन निवेदनों की भी जांच की है कि आस्ट्रेलिया को किए गए कुछ कारोबार को गलती से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाहर रखा गया है। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने देशों के नाम के साथ तृतीय देश के कारोबारों के आंकड़े प्रस्तुत किए थे जिन्हें उन्हें भेजा गया था/निर्यात किया गया था, जिससे पता चलता है कि आस्ट्रेलिया के साथ 8 कारोबार किए गए थे। प्रकटन पश्चात उन्होंने यह सूचित किया है कि आस्ट्रेलिया को 4 और कारोबार किए गए थे जिनके आधार पर निर्यात करने वाले देश को उनके उत्तर में सिंगापुर और चीन दर्शाया गया है। अब उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसे कारोबार आस्ट्रेलिया को किए गए थे, इस अंतिम चरण में इन कारोबारों के बीजक प्रस्तुत किए हैं। तथापि, इन बीजकों की जांच करने पर ऐसा पता चलता है कि हालांकि जिस देश से भाड़े के संघटक संबंधित हैं, वे असामान्य रूप से अन्य कारोबारों की तुलना में अधिक हैं जोकि निवल कीमतों को अन्य कारोबारों की तुलना से कम बनाते हैं। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इन कारोबारों तथा समायोजन के दावों की इस अंतिम चरण में जांच की जा सके। इसलिए प्राधिकारी इस चरण में इस उत्पादक/निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इन कारोबारों को स्वीकार नहीं करने के लिए प्रतिबंधित हैं।
- 78. पीटी पीओएन ने आगे यह तर्क दिया है कि आस्ट्रेलिया को उनके निर्यात बल्क में नहीं हैं और इसलिए भारत को किए गए निर्यातों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि, बीजकों की जांच करने से ऐसा पता चलता है कि ये वस्तुएं इसो-टैंकों और फ्लैक्सी बोरों में भेजी गई हैं जोकि बिक्रियों के रूप में बल्क है और न कि इन्हें ड्रमों में भेजा गया है जिन्हें पैक की हुई वस्तुएं माना जाता है। इसलिए इस संबंध में निर्यातक के तर्क वैध नहीं हैं।
- 79. तद्नुसार,आस्ट्रेलिया को तृतीय देश की बिक्रियों के कारोबार सत्यापित लागत के संदर्भ में सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के अध्यधीन थे, जो कि {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर/मी.टन निर्धारित किए गए हैं। इन सभी बिक्रियों का लाभप्रद पाया गया है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसे समग्र कारोबार पर विचार किया गया है। निर्यात बिक्रियां, 90 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ सीएफआर/सीआईएफ शर्तों पर हैं। कार्य-गत सामान्य मूल्य तय करने लिए समुद्री भाडा, बीमा, जेटी प्रभार, पर्यवेक्षक शुल्क और बन्दरगाह हैंडलिंग प्रभार और क्रेडिट व्यय के लिए समग्र कार्य-गत व्यय को समायोजित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

तृतीय देश के निर्यात	मात्रा का योग	निबल मूल्य का योग	कीमत/सामान्य मूल्य
	(मी.टन)	यूएस\$	यूएस\$/मी.टन
आस्ट्रेलिया	***	***	***

निर्यात कीमत: निर्यातक के रूप में सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड (पीओएन) सहित पीटी पीओएन

- 80. जांच अवधि के दौरान पीटी, पीओएन ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, दो बिक्री माध्यमों (1) असंबद्ध व्यापारी नामत: मेसर्ज सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर और (2) सीधे असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को किए थे। मेसर्ज सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड, सिंगापुर जो कि मेसर्ज सोजिटज, जापान के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, वस्तुत: एक पूर्णतया व्यापारिक कंपनी है, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के ब्यौरे प्रदान करते हुए प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। पीटी पीओएन ने जांच अवधि के दौरान भारत को {***} मी.टन संबद्ध वस्तुएं निर्यात की थीं, जिनमें से {***} मी.टन संबद्ध वस्तुएं सोजिटज के माध्यम से निर्यात की गई थीं। शेष मात्रा का सीधे निर्यात किया गया था। सोजिटज एशिया की भारत में सोजिटज इंडिया प्राईवेट लिमिटिड नामक 100 प्रतिशत स्वामित्वाधीन कंपनी है। तथापि, सोजिटज इंडिया भारत में संबद्ध वस्तुओं का बेचने का कार्य नहीं करती है। सोजिटज एशिया, सिंगापुर, पीटी पीओएन से संबद्ध वस्तुओं को खरीदने के बाद उनका सीधा निर्यात करती है।
- 81. पीटी पीओएन सीधे अथवा सोजिटज के माध्यम से सीआईएफ/सीएफआर शर्तों पर भारत को संबद्ध वस्तुएं बेचती है। भुगतान की शर्तें टीटी होती हैं, जिनकी 90 दिनों तक की क्रेडिट अविध में अंतर होता है। सोजिटज के माध्यम से की जाने वाली बिक्रियों के लिए सोजिटज एलसी के आधार पर सीआईएफ/सीएफआर शर्तों पर भारतीय ग्राहकों के लिए पृथक बीजक प्रस्तुत करती है, जिसकी भिन्न क्रेडिट अविध 60 से 180 दिनों तक की होती है।
- 82. भारत में निर्यात बिक्रियां बल्क में की जाती हैं और पीटी पीओएन ने (1) समुद्री भाडे, (विदेशी बीमा), (3) क्रेडिट लागत, (4) बैंक प्रभार, (5) पर्यवेक्षक शुल्क, (6) जेटी प्रभार और (7) बन्दरगाह हैंडलिंग, सीमा शुल्क, दलाल के शुल्क आदि पर हुए व्यय के ब्यौरे प्रदान किए हैं, ताकि कारखाना-गत कीमत तय की जा सके। तदनुसार निर्धारित की गई पीआएन की निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

उत्पाद	माध्यम	मात्रा का योग (मी.टन)	कुल बीजक मूल्य का योग (यूरो)	कुल समायोजन का योग (संशोधित) यूएस \$	निबल मूल्य का योग यूएस \$	निबल मूल्य यूएस\$/मी.टन
2 ईएच	सीधे सोजिटज एशिया	***	***	***	***	***
	प्राईवेट लिमिटिड कुल		***	***	***	***

पाटन मार्जिन : निर्यातक के रूप में सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड (पीओएन) सहित पीटी पीओएन

83. पाटन मार्जिन तय करने के लिए कार्य-गत स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना भारत में निबल कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

माध्यम	मात्रा का योग (मी.टन)	निर्यात कीमत यूएस\$/ मी.टन	निबल मूल्य यूएस\$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस\$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
सीधे	***	***	***			
सोजिटज एशिया प्राईवेट लिमिटिड	***	***	***			
कुल	***	***	***	***	***%	0-10 %

(ख) इंडोनेशिया में सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक

84. इंडोनेशिया में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, सहयोगी निर्यातक के आंकडों को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	10-20%

छ. 5 सऊदी अरब

- 85. आयात आंकडों के अनुसार जांच अविध के दौरान सऊदी अरब से 17,673 मी.टन संबद्ध वस्तुओं के आयात किए गए थे। मेसर्ज एल जुबैल फर्टालाईजर्स कंपनी (एल्बेयरोनी), सऊदी अरब ने, सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। उसने जांच अविध के दौरान भारत को ऐसे निर्यात, मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कोर्पोरेशन (एसएबीआईसी) के माध्यम से किए थे। इन दोनों कंपनियों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
- 86. इन दोनों उत्पादक-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को स्थल पर जांच करके सत्यापित नहीं किया जा सका है। तथापि, इन उत्तरों की जांच की गई थी और प्रत्युत्तर देने वाले पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

- 87. एल्बेयरोनी सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक है। एल्बेयरोनी ने अपने उत्तर में यह सूचित किया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोपीलीन एक प्रमुख कच्चा माल है, जिसे वह अपनी संबंधित कंपनी मेसर्ज अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेमिया") से दीर्घावधिक आपूर्ति करार के अंतर्गत खरीदती है, जिसके तहत पेट्रोकेमिया ने एल्बेयरोनी को प्रोपीलीन का उत्पादन करने के लिए अपनी ओलेफिन्स विनिर्माण यूनिट के एक भाग का उपयोग करने की अनुमित दी है, जिसके लिए एल्बेयरोनी संयंत्र की पूंजीगत लागत के एक अंश का भुगतान करती है।
- 88. कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि वह सऊदी अरब में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को नहीं बेचती है तथा उसके द्वारा विनिर्मित समग्र मात्रा का निर्यात किया जाता है। एसएबीआईसी और मेसर्ज ताईवान फर्टलाईजर्स कंपनी लिमिटिड (टीएफसी) के समग्र उत्पादन को एल्बेयरोनी बेचती है। ताईवान फर्टलाईजर्स कंपनी लिमिटिड (टीएफसी) पहले चीन में 2 ईएच का विपणन करती थी। वर्ष 2013 से एसएबीआईसी विश्वभर में 2 ईएच उत्पादों के लिए एक मात्र विपणनकर्ता है। एसएबीआईसी में सऊदी अरब सरकार की 70 % शेयरधारिता है। एल्बेयरोनी द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की एसएबीआईसी एक मात्र निर्यातक है और वह संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है।
- 89. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है :-
- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :
- 90. चूंकि कोई घरेलू बिक्रियां नहीं होती हैं, इसलिए प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक से कहा गया था कि वह उपरोक्त उद्धृत धारा 9 क (1) (ग) के दूसरे परन्तुक के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त तृतीय देश का चयन करने के लिए तृतीय देशों को अपनी निर्यात बिक्रियों के कारोबार-वार ब्यौरे प्रदान करें। एक उपयुक्त तृतीय देश का चयन करने के लिए प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदत्त तृतीय देशों को अपनी निर्यात बिक्रियों के कारोबार-वार के आंकडों की जांच की गई है। इस संबंध में या तो करार अथवा नियमावली में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण उपयुक्त तृतीय देश का चयन करने के लिए आयातों के देश में सामान्य आर्थिक दशाओं के सिद्धांतों, उक्त देश में उत्पाद विकास और आयातों की मात्रा को मागदर्शी माना गया है। चीन में निर्यात की सर्वाधिक मात्रा होती है, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में प्रचालन नहीं करता है। दूसरी निर्यात की सर्वाधिक मात्रा पाकिस्तान में होती है, जिसमें जांच अवधि के दौरान {***} मी.टन निर्यात आयात किया गया है। निर्यात की मात्रा अत्यधिक है। इसलिए पाकिस्तान को उपयुक्त तृतीय देश के रूप में चयनित किया गया है तथा सऊदी अरब से इस प्रतिवादी निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाकिस्तान को एल्बेयरोनी/एसएबीआईसी की निर्यात बिक्रियों के कारोबार पर विचार किया गया है।

91.घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि सऊदी अरब के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका एक अधिक उपयुक्त तृतीय देश है। इसी कारणवश पाकिस्तान में विचाराधीन उत्पाद की मांग संयुक्त राज्य अमरीका में विचाराधीन उत्पाद की मांग से काफी कम है। चूंकि मांग स्वत: ही कम है, इसलिए पाकिस्तान में उसकी प्रचलित कीमतें उत्पाद की कीमत को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेंगी। इसके अतिरिक्त जबिक संयुक्त राज्य अमरीका में विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक ग्राहक हैं, इसलिए पाकिस्तान में विचाराधीन उत्पाद के ग्राहकों की संख्या बहुत सीमित है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में ग्राहकों की सीमित संख्या होने के कारण

कीमतों में कुछ प्रकार की विकृतियां होने की संभावना है। इसलिए सउदी अरब के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सउदी अरब से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी निवेदन किया है कि प्रकटन विवरण में संबंधित कंपनी से अरबिया पैट्रो कैमिकल कंपनी, एल बेयरोनी से संबंधित कंपनी को प्रोपलीन के मूल्यांकन और अरेबिया पैट्रो कैमिकल कंपनी अथवा अल-बेयरोनी के स्वामित्व जैसे मुद्दों पर पूर्णतया कोई उल्लेख नहीं है।

- 92. दूसरी ओर उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदनों में यह तर्क दिया है कि चूंकि उन्होंने चीन को संबद्ध वस्तुओं के पर्याप्त निर्यात किए हैं, इसलिए अल ब्योरोनी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन को उनके तृतीय देश के निर्यातों के आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त के बावजूद उत्पादन की अल ब्योरोनी की लागत पर उनका सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। चूंकि उसका आसानी से सत्यापन किया जा सकता है और यह अधिक विश्वसनीय है। यह भी तर्क दिया गया है कि तृतीय देश को कारखानागत कीमतों का निर्धारण करने के लिए कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है जैसा कि भारत को किए गए निर्यातों के मामले में किया गया है।
- 93. निर्यातक के इन तर्कों के संबंध में कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उनके उत्पादन की निजी लागत पर विचार किया जाना चाहिए अथवा चीन को उपयुक्त तृतीय देश के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडीए के अनुच्छेद 2.2 में एक अंतनिर्मित अनुक्रम तंत्र है और दूसरा विकल्प इस्तेमाल करने से पहले प्रथम विकल्प को प्रयुक्त किए जाने की संभावना का पता लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, पहले विकल्प के रूप में ऐसा निर्धारण करने के लिए तृतीय देश की बिक्रियों की जांच की गई थी। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका सहित अनेक देशों को संबद्ध वस्तुओं के सउदी अरब के निर्यात किए गए थे। चीन को किए गए ऐसे निर्यातों की सर्वाधिक मात्रा है जोकि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं के अंतर्गत कार्य करता है। इसलिए चीन को निर्धारण के लिए उपयुक्त तृतीय देश के रूप में नहीं अपनाया गया है क्योंकि उस देश को बिक्री की कीमत उस देश में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशा से प्रभावित होने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमरीका को किए गए निर्यातों की मात्रा कम थी और अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों में अत्यधिक निर्यात किए गए हैं जोकि संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातों की तुलना में अत्यधिक हैं। इसलिए, पाकिस्तान को जिसमें कि बाजार अर्थव्यवस्था की श्रेणी में अत्यधिक मात्रा में निर्यात किए गए हैं, उपयुक्त तृतीय देश के रूप में अपनाया गया है और कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सभी लागू समायोजन की अनुमति दी गई है। इसलिए कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।
- 94. जहां तक अल ब्योरोनी की उत्पादन की लागत और प्रोपलीन की लागत का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत का निर्धारण, प्राधिकारी की सुसंगत पद्धतियों के अनुसार लागत के सभी तत्वों को ध्यान में रखकर के किया गया है।
- 95. पाकिस्तान को और स्वतंत्र केताओं को निर्यात अधिक मात्रा में किए जाते हैं। ऐसी बिक्रियां अनन्तिम आधार पर एसएबीआईसी के माध्यम से की जाती हैं। निर्यात करने के बाद एसएबीआईसी, समस्त बिक्री व्यय और विपणन शुल्क को हिसाब में लेने के बाद निबल वापसी राशि के रूप में एल्बेयरोनी को धनराशि प्रत्यावर्तित करती है। एल्बेयरोनी अंतरदेशीय भाडे और पर्यवेक्षक शुल्क के लिए भी कुछ व्यय करती है। उत्तर में निर्दिष्ट क्रेडिट अविध के बाद एसएबीआईसी से निबल वापसी होती है। एल्बेयरोनी द्वारा पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के बीच व्यापक अंतर होता है, जो कि प्रत्येक महीने के लिए भिन्न होता है। इसलिए उचित तुलना करने के लिए मासिक सामान्य मूल्य का निर्धारण, कंपनी द्वारा प्रदत्त उत्पादन की लागत के संदर्भ में व्यापारिक परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया के लिए तृतीय देश की बिक्रियों को अधीन रखने तथा अंतरदेशी भाडे की लागत, पर्यवेक्षक के शुल्क तथा एसएबीआईसी से प्राप्त हुई निबल वापसी राशि में से एल्बेयरोनी द्वारा व्यय की गई क्रेडिट लागत का समायोजन करने के बाद किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का किया गया निर्धारण निम्नानुसार है:-

बिक्री मात्रा का योग (मी.टन)	एल्बेयरोनी को अदा किए गए नेटबैक मूल्य का योग यूएस \$		कीमत यूएस \$/ मी.टन	एल् बेयरोनी के अन्य व्यय	मासिक निबल मूल्य का भारित औसत यूएस \$/ मी.टन
***	***	***	***	***	***

निर्यात कीमत: एसएबीआईसी में माध्यम से एल्बेयरोनी

सऊदी अरब से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जांच अवधि के दौरान एल्बेयरोनी ने एसएबीआईसी के माध्यम से भारत में {***} मी.टन संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए गए हैं। एसएबीआईसी ने भारत में एसएबीआईसी इंडिया प्राईवेट लिमिटिड नामक एक कंपनी बनाई है, जो कि एसएबीआईसी और एसएबीआईसी इंडिया के बीच हुए करार के अनुसार बिक्री में सहायता देने के लिए कमीशन प्रापृत करती है। एसएबीआईसी ग्राहकों से बिक्री के आर्डर प्रापत करती है और एलबेयरोनी को उसकी प्रदानगी करने का निर्देश देती है। एलुबेयरोनी अनन्तिम कीमत पर एसएबीआईसी को एक बीजक देती है। एसएबीआईसी ग्राहकों को एक बीजक देती है । बिक्रियों के बाद कीमत में किए जाने वाले संशोधन का समाययोज, ग्राहकों को डेबिट अथवा क्रेडिट नोट के माध्यम से किया जाता है । एसएबीआईसी ग्राहकों से प्रभारित की जाने वाली अंतिम कीमत में से बाजार श्ल्क और अन्य संबंधित व्यय को घटाती है और इस प्रकार अधिशेष राशि का भुगतान एल्बेयरोनी को किया जाता है । सुथल पर होने वाले कारोबार और सीआईएफ के आधार पर ग्राहकों के साथ बात-चीत की जाती है। समुद्री भाडे, विदेशी बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, और विपणन शुल्क आदि पर हुए व्यय के लिए समायोजन यह देखने के लिए किया गया है कि कया एसएबीआईसी द्वारा एलुबेयरोनी को अदा की गई निबल वापसी राशि में सभी वृयय और उचित उचित लाभ को शामिल किया गया है। एलबेयरोनी क्रेडिट अवधि के बाद एसएबीआईसी से निवल वापसी राशि का भगतान प्रापत करती है और साथ ही वह कुछ वृयय भी करती है । इसलिए एसएबीआईसी द्वारा एलुबेयरोनी को अदा की गई निबल वापसी राशि में से अंतर्देशीय परिवहन और पर्यवेक्षक शुलुक के साथ-साथ एसएबीआईसी की क्रेडिट लागत जैसे एलुबेयरोनी के वयय को घटाया गया है, ताकि निबल कारखाना-गत कीमत तय की जा सके।

97. कीमतों में व्याप्त अत्यधिक अंतर के कारण निर्यात कीमत का निर्धारण, मासिक आधार पर किया गया है, जो कि निमृनानुसार है:-

मूल्य				
मात्रा का योग (मी.टन)	एसएबीआईसी से नेटबैक मूल्य का योग (यूएस \$)	एल्बेयरोनी के कुल व्यय का योग	एल् बेयरोनी द्वारा निबल वसूली का योग	
***	***	***	***	***

पाटन मार्जिन : एसएबीआईसी के साथ एल्बेयरोनी

98. उपरोक्त उत्पादक और निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए गए निबल कार्य-गत सामान्य मूल्य की तुलना कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन यूएस \$/मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
एल्बेयरोनी	एसएबीआईसी	***	***%	न्यूनतम

(ख) सऊदी अरब में सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक

99. यह नोट किया जाता है कि सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक उत्पादक एल्बेयरोनी है और उससे संबद्ध सत्व एसएबीआईसी द्वारा वस्तुओं के निर्यात किए गए हैं। इसलिए सऊदी अरब से अन्य निर्यातकों के लिए बाकी पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।

छ. 6 संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस मामले में प्रश्नावली के कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में अवस्थित मेसर्ज विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड और मेसर्ज आईसीसी केमिकल कोर्पोरेशन कोर्पोरेशन ने अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के अपने निर्यात के बारे में अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य अथवा निर्यात कीमत के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई सूचना प्रदान नहीं की है। उपरोक्त परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमरीका के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है।

सामान्य मूल्य : संयुक्त राज्य अमरीका

101. संयुक्त राज्य अमरीका से उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन लागत के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी करार के अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

"जांच शुरू किए जाने के यथाशीघ्र बाद जांच प्राधिकारियों को किसी भी हितबद्ध पक्षकार से अपेक्षित सूचना को व्यापक रूप से विनिश्चित करने चाहिए और ऐसे तरीके को निर्दिष्ट करना चाहिए, जिसमें हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना को अपने उत्तर में संरचित करना है। साथ ही प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षकार को इसकी जानकारी है कि यदि उचित समय के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध उन तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच की शुरूआत करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र में निहित हैं"।

102. इसलिए प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया जाए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अविध के दौरान सऊदी अरब से अत्यिधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का संयुक्त राज्य अमरीका में आयात किया गया है और सऊदी अरब से संयुक्त राज्य अमरीका तक की भारित औसत बिक्री कीमत उपलब्ध है। चूंकि ऐसी आशा की जाती है कि घरेलू बाजार में वस्तुएं उन कीमतों पर प्रवेश करती हैं, इसलिए इस सूचना का उपयोग, संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्य मूल्य का

अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध उत्तम तथ्यों के रूप में किया गया है। तदनुसार संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्य मूल्य निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

सऊदी अरब से संयुक्त	त राज्य अमरीका				
मात्रा	मूल्य	आयात कीमत	सामान्य मूल्य		
मी. टन में	यूएस \$	यूएस \$/मी.टन	यूएस \$/मी.टन		
***	***	***	***		

निर्यात कीमत: संयुक्त राज्य अमरीका

103. संयुक्त राज्य अमरीका से निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस के आंकडों में यथा सूचित आयातों की भारित औसत सीआईएफ कीमत में भाडे, भार, हैंडलिंग व्यय आदि के लिए समायोजन करने के बाद उपलब्ध उत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है, ताकि कार्य-गत कीमत तय की जा सके जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
आयात की मात्रा	मी. टन	4,632
आयात का मूल्य	लाख रूपए	4,101
सीआईएफ निर्यात कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	88.55
समुद्री भाडा (128 यूएस \$ प्रति मी. टन)	रूपए/कि.ग्रा.	7.79
समुद्री बीमा @ 0.5%	रूपए/कि.ग्रा.	0.44
एफओबी कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	80.31
कमीशन @ 3%	रूपए/कि.ग्रा.	2.41
0.5% की दर से बैंक प्रभार	रूपए/कि.ग्रा.	0.40
0.5% की दर से बन्दरगह के व्यय	रूपए/कि.ग्रा.	0.40
0.5% की दर से संभालने के प्रभार	रूपए/कि.ग्रा.	0.40
निबल निर्यात कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	76.70
विनिमय दर	आईएनआर/यूएस \$	60.77
निबल निर्यात कीमत	यूएस \$/क्रि.ग्रा.	1.262

पाटन मार्जिन: संयुक्त राज्य अमरीका

104. निबल कार्य-गत सामान्य मूल्य की तुलना कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है, ताकि संयुक्त राज्य अमरीका में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सके, जो कि निम्नानुसार है :-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	1262.13	***	***%	15-25%

105. उपरोक्त अनुसार, पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रिया प्रणाली के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए प्राधिकारी उपरोक्त निर्धारण की संपुष्टि करते हैं ।

छ. 7 चीनी ताइपेई

106. प्राधिकारी को चीनी ताइपेई में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में चीनी ताइपेई के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है।

सामान्य मूल्य : चीनी ताइपेई

107. चीनी ताइपेई के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग नहीं प्राप्त होने अथवा चीनी ताइपेई में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत संबंधी सूचना/साक्ष्य सार्वजिनक रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में चीनी ताइपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारण, ऊपर उद्धधृत करार के अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधान के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सीमा शुल्क संबंधी आंकडों को प्राप्त करने का प्रयास किया था ताकि तृतीय देश के निर्यात/आयात कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अन्य देशों को/से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों अथवा आयातों का विश्लेषण किया जा सके। तथापि, चूंकि उत्पाद के लिए सुव्यवस्थित टैरिफ शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए निर्धारण करने के लिए प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी के पास यही विकल्प उपलब्ध है कि चीनी ताइपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारण, या तो उचित कीमत जोडने के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त लागत और कीमतों संबंधी सूचना के आधार अथवा उपलब्ध अन्य उत्तम तथ्यों के आधार पर किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्वी एशिया नामत: कोरिया में संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक और निर्यातक ने ही प्रश्नावली के पूरे उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उसकी अपनी घरेलू बिक्री कीमतों शामिल हैं। चीनी ताइपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध उत्तम तथ्यों के रूप में इस सूचना को अपनाया गया है। तदनुसार चीनी ताइपेई में कार्य-गत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जो कि {***} संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

निर्यात कीमत: चीनी ताइपेई

108. चीनी ताइपेई से निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस के आंकडों में यथा सूचित आयातों की भारित औसत सीआईएफ कीमत में भाडे, भार, हैंडलिंग व्यय आदि के लिए समायोजन करने के बाद उपलब्ध उत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है, ताकि कार्य-गत कीमत तय की जा सके, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
आयात की मात्रा	मी. टन	6,499
आयात का मूल्य	लाख रूपए	6,149
सीआईएफ निर्यात कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	94.61
	रूपए/कि.ग्रा.	2.98
समुद्री भाडा (128 यूएस \$ प्रति मी. टन)		
समुद्री बीमा @ 0.5%	रूपए/कि.ग्रा.	0.47
एफओबी कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	91.16
कमीशन @ 3%	रूपए/कि.ग्रा.	2.73
बैंक प्रभार @ 0.5%	रूपए/कि.ग्रा.	0.46
पत्तन व्यय @ 0.5%	रूपए/कि.ग्रा.	0.46
संभालने के प्रभार @ 0.5%	रूपए/कि.ग्रा.	0.46
निबल निर्यात कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	87.06
विनिमय दर	आईएनआर/यूएस \$	60.77
निबल निर्यात कीमत	यूएस \$/क्रि.ग्रा.	1.433

पाटन मार्जिन : चीनी ताइपेई

109. निर्धारित निबल कार्य-गत सामान्य मूल्य की तुलना, कार्य-गत निर्यात कीमत से की गई है, ताकि चीनी ताइपेई में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सके, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	5-15%

110. उपरोक्त अनुसार, पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रिया प्रणाली के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए प्राधिकारी उपरोक्त निर्धारण की संपुष्टि करते हैं।

छ. 8 पाटन मार्जिन तालिका: सभी संबद्ध देश

111. उपरोक्त जांच के आधार पर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और सभी अन्य पक्षकारों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक	निर्यातक	निबल मूल्य यूएस \$/ मी.टन	निर्यात कीमत यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन यूएस \$/ मी.टन	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा
यूरोपीय यूनियन						
जर्मनी	आईसीसी केमिकल्स कोर्पोरेशन	***	***	***		
	पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई	***	***	***		
	विन्मार इंटरनेशनल लिमिटिड	***	***	***		
	समग्र	***	***	***	***%	25-35%
यूरोपीय यूनियन	- सभी अन्य					
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	30-40%
मलेशिया						
बीपीसी	बीपीसी	***	***	***	***%	0-10%
मलेशिया - सर्भ	ो अन्य					
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	20-30%
दक्षिण कोरिया						
एलजी केम	हुंडाई कोर्पोरेशन	***	***	(***)		
एलजी केम	विन्मार	***	***	***		
एलजी केम	समग्र	***	***	***	***%	0-10%

	T				T	
दक्षिण कोरिया - सभी अन्य						
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	10-20%
इंडोनेशिया						
पीटी पीओएन	सीधी बिक्रियां	***	***	***		
	सोजिटजे एशिया प्राईवेट लिमिटिड	***	***	***		
	समग्र	***	***	***	***%	0-10%
इंडोनेशिया – स	भी अन्य					
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	10-20%
सऊदी अरब						
एल_बेरोनी	एसएबीआईसी	***	***	***	***%	न्यूनतम
	1					
संयुक्त राज्य अमरीका – सभी निर्यातक						
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	15-25%
चीनी ताइपेई – सभी निर्यातक						
कोई भी	कोई भी	***	***	***	***%	5-15%

112. संबद्ध वस्तुओं के लिए इस प्रकार से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन विशेष है और यह सऊदी अरब के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं को छोड कर, न्यूनतम से अधिक है । यह सऊदी अरब से निर्यातित वस्तुओं का पाटन मार्जिन न्यूनतम पाया गया है । इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 14 (ख) के अनुसार सऊदी अरब कि खिलाफ जांच समाप्त कर दी है । तदनुसार शेष देशों/क्षेत्रों नामत: यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य और चीनी ताइपेई के संबंध में क्षति और कारणात्मक संबंध होने की आगे जांच की गई है । इसके आगे संबद्ध देशों/क्षेत्रों की शब्दावली का प्रयोग, केवल इन देशों के लिए किया जाएगा । 113. सऊदी अरब के उत्पादक/निर्यातक के प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि चूंकि सऊदी अरब में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम पाया गया है इसलिए सऊदी अरब के खिलाफ इस जांच को इस संबंध में प्रकटन विवरण जारी किए बिना एक पृथक सार्वजनिक नोटिस जारी करके समाप्त कर दिया जाना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों, विशेषकर घरेलू उद्योग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में

रखते हुए अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना एक देश के खिलाफ जांच को समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

ज. घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण

ज. 1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

- 114. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 (3) में ऐसी व्यवस्था है कि यदि एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों की एक साथ पाटन-रोधी जांच की जाती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि यह निर्धारित होता है कि -
 - (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध हुआ पाटन का मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक होता है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा, समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत है अथवा जहां किसी एक देश के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, तो वहां समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक होने के लिए आयातों को संचयी माना जाएगा और
 - (ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच तुलना करने की दशाओं के आलोक में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्याकन करना उपयुक्त है।
- 115. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि एक से अधिक देशों से निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं को पाटित कर रहे हैं और ऐसे प्रत्येक संबद्ध देश/क्षेत्र में पाटन का मार्जिन, उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है। उपरोक्त देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसलिए आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही समान वसतुओं से सीधे प्रतिसपर्द्धा करते हैं।
- 116. प्रतिवादी निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि आयातित उत्पादों और घरेलू समान उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्द्धा होने की स्थिति के अतिरिक्त आयातित वस्तुओं के बीच पारस्पिरक प्रतिस्पर्द्धा होने की स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- 2 (3) में उल्लिखित प्रावधान का अनुसरण किया जा सके, जैसा कि प्राधिकारी की पद्धित रही है । एएसईएएन-इंडिया एफटीए और इंडिया-मलेशिया सीईपीए के कारण लागू होने वाले शुल्क, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया, ताईवान और सऊदी अरब जैसे अन्य लक्षित देशों की तुलना में मलेशिया और इंडोनेशिया के आयातों के लिए भिन्न हैं । टैरिफ दरों में भिन्नता होने के फलस्वरूप संबद्ध देशों के दो सेटों से आयातों की स्थिति मुख्यतया भिन्न होती है । शुल्क की प्राथमिकता मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातों की अनुमित देती है, जो कि यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया और सऊदी अरब से आयातों की तुलना में अधिक दर से आयात करने को प्रोत्साहित करते हैं । इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक रूप से शुल्कों के अधीन होने वाले देशों से आयातों के हिस्से में 27 % (16% से 43 % तक) की वृद्धि हुई है, जबिक इसकी तुलना में प्राथमिक रूप से शुल्कों के अधीन नहीं होने वाले देशों के आयातों में विशेष रूप से गिरावट आई है, जो कि 27 % (84 % से 57 % तक) घट गए है ।
- 117. इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब अधिकतर इस तथ्य से बाहर हो गए हैं कि केवल वे दो ही ऐसे संबद्ध देश/क्षेत्र हैं, जिन्हें एफटीए से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जांच अवधि के दौरान उनके आयात के हिस्से में विशेषरूप से गिरावट आई है। तदनुसार मौजूदा जांच में संबद्ध देशों के साथ यूरोपीय यूनियन से आयातों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की दशाएं तुलनीय नहीं हैं।
- 118. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त तर्क का कोई आधार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि नियमावली के अनुसार तीन शर्तें विनिश्चित करनी अपेक्षित होती हैं और इन सभी को पूरा किया गया है। चूंकि निर्दिष्ट

प्राधिकारी आयातों की पहुंच कीमत कीमत पर विचार करता है, इसलिए सीमा शुल्क के विभिन्न स्तर के होने के बावजूद आयातों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है। ग्राहक आयात की पहुंच कीमत पर विचार करते हैं और इसलिए लागू किया जाने वाला सीमा शुल्क लगाया जाता है। यदि सीमा शुल्क के स्तर भिन्न हैं, तो उनसे ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि आयात परस्पर रूप से प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं। याचिकादाता ने होल्डर टोप्से के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें दो विभिन्न सीमा शुल्कों के साथ दो अलग एचएस संहिताओं के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की क्षति मार्जिन की विभिन्न मात्रा निर्धारित करने के निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय की संपृष्टि की गई है।

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरूआत यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब,चीनी ताइपेई और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन के खिलाफ की गई है। विगत खंड में पाटन के मार्जिन के निर्धारण से ऐसा पता चलता है कि ऊपर उल्लिखित देशों में सऊदी अरब को छोड़ कर जहां पाटन मार्जिन न्यूनतम है और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 14 (ख) के अनुसार इस देश के खिलाफ जांच समाप्त कर दी गई है, बाकी प्रत्येक देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन का मार्जिन, ऊपर निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक है। अन्य संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक है। हितबद्ध पक्षकारों ने एफटीए के अंतर्गत कुछ देशों के खिलाफ ऐसे विभिन्न शुल्कों का मुद्दा उठाया है, जिनके कारण इस जांच में अन्य नामित देशों की तुलना में उन देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि इससे ऐसा पता चलता है कि आयात परस्परिक रूप से प्रतिस्पर्द्धी नहीं और इसलिए इस मामले में क्षति का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि ऐसे कुछ देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जो कि प्राथमिकता वाले शुल्कों से लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्होंने ऐसी सीआईएफ कीमत सीमा और पहुंच मूल्य को बढ़ा दिया है, जिन पर संबद्ध देशों से वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, जिससे ऐसा पता चलता है कि भारतीय बाजार में इन स्रोतों से आयातों के बीच परस्परिक प्रतिस्पर्द्धी हो रही है, सिलए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से होने वाले आयातों के बीच कोई परस्परिक प्रतिस्पर्द्धी नहीं हो रही है, सही प्रतीत नहीं होता है।

120. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से होने वाले आयात, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। घरेलू उत्पादक और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से निर्यातक उसी श्रेणी के ग्राहकों को समान उत्पाद बेचते हैं तथा दोनों समान बजार में प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। ग्राहकों द्वारा दोनों की वस्तुओं का उपयोग, परस्पर रूप से बदल कर किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह निर्णय है कि आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है और तदनुसार क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच करने के लिए सभी पाटित स्रोतों से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया गया है।

ज. 2 जांच के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

(क) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिनमें प्रतिवादी उत्पादक और संबद्ध देशों और क्षेत्रों से निर्यातक, आयतक और भारतीय प्रयोक्ता उद्योग की एसोसिएशनें तथा कुछेक संबद्ध देशों और क्षेत्रों की सरकारें भी शामिल हैं, ने अपने से संबंधित निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-
 - यह कि जब मांग और आपूर्ति के बीच इतना अधिक अंतर व्याप्त है, तो याचिकादाता ने जांच अविध में काफी समय तक कच्चे माल की आपूर्ति के मुद्दों के कारण अपने संयंत्र को बंद रखा हुआ था और बाद में याचिकादाता ने पाटन के कारण क्षित होने का दावा किया है, जो कि युक्ति संगत नहीं है। चूंकि जांच अविध में काफी समय तक कच्चे माल की आपूर्ति के मुद्दों के कारण घरेलू उद्योग प्रचालन में नहीं था, प्रयोक्ता के पास आयात करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए जबिक

जांच अवधि के दौरान याचिकादाता का संयंत्र न्यूनतम 212 दिनों से ले कर 455 दिनों तक बंद पडा हुआ था, उसको कथित पाटित आयातों के कारण आर्थिक हानि होने की संपुष्टि, अभिज्ञात और सुवीकार किए गए अनुय कारणों से की आवश्यकता है।

- यह कि घरेलू उद्योग ने जांच अविध से संबंधित प्रपत्र-4 "क" में कार्य-निष्पादन शीर्ष के अंतर्गत "यिद कोई निष्क्रिय समय नहीं है" नामक एक अतिरिक्त कॉलम जोड दिया है और ऐसी किसी कार्य-प्रणाली का प्रकटन नहीं किया है जिसके द्वारा याचिकादाता ने ऐसे आंकडे प्राप्त किए गए हैं। याचिकादाता ने "काल्पिनक क्षति होने" का मामला बनाया है। इस प्रकार याचिका में गंभीर और दूर नहीं की जा सकने वाली असंगतियां हैं। उत्पादन में क्षति होने के कारण समायोजन करने का दावा गैर-कानूनी अथवा तथ्य पर आधारित नहीं है। जहां तक कि याचिकादाता ने अपनाई गई विस्तृत कार्य-प्रणालियों के व्यापक विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- यह कि प्रपत्र-4 "क" में "यदि कोई निष्क्रिय समय नहीं है" नामक कॉलम में तय करने की कार्य-प्रणाली का प्रकटन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी अधिनियम और नियमावली में "आर्थिक क्षति" सार का उल्लेख है और न कि "काल्पनिक क्षति" का ।
- यह कि क्रेडिट दर का निर्धारण करने वाली आईसीआरए नामक कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान उसके प्रमुख कच्चा माल, प्रोपीलीन के आपूर्ति में व्यवधान होन के कारण एपीएल की लाभप्रदता और ऋण संरक्षण मापन के प्रत्याशित कमजोर हो जाने को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2013 में आवेदक की क्रेडिट रेटिंग को संशोधित और कम किया था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि एचपीसीएल से सुस्थिर आपूर्तियों के पुनरांरभ होने की समय-सीमा के बारे में अनिश्चिंतता बनी रहने के कारण दीर्घावधिक रेटिंग की स्थित निरंतर नकारातुमक बनी रहेगी।
- यह िक मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षित और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इसिलए यह समग्र जांच प्रारंभ से ही व्यर्थ है और इसे तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए।
- यह कि अनेक देशों के संबंध में आयातों की कीमत में कटौती होना नकारात्मक है, जिससे स्पष्ट होता है कि कारणात्मक संबंध नहीं है। अधिकतर देशों का क्षिति मार्जिन नकारात्मक है। घरेलू उद्योग द्वारा क्रेडिट लागत का समायोजन करने का दावा निराधार है। सकारात्मक कीमत कटौती संरचित करने के लिए याचिकादाता का पहुंच मूल्य और निबल बिक्रियों की वसूली गढी हुई है। प्राधिकारी को ऐसे निराधार और मनगढंत दावों को तुरत खारिज कर देना चाहिए।
- यह कि प्रोपीलीन जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रमुख कच्चा माल है, की मांग में गिरावट आने की प्रवृति का स्पष्ट पता चलता है और यह वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लगभग 2% तक पहुंच जाएगी। इससे ऐसा पता चलता है कि प्रमुख प्रोपीलीन विनिर्माता, इसे पोलीप्रोफीलीन में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि वे अपनी केप्टिव खपत में प्रोपीलीन का ही उपयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में 2-एथिल हेक्सानोल कच्चे माल का स्रोत अनुपलब्ध हो जाएगा अथवा कम उपलब्ध होगा, इसलिए 2-ईएच का आयात किया जाना अत्यावश्यक है।
- यह कि 2-ईएच की तुलना में पोलीप्रोफीलीन की लाभप्रदता लगभग 50 % तक अधिक है, जो कि 100 संयुक्त अमरीकी डालर/मी.टन है। इससे रिफॉइनर्स की 2-ईएच का विनिर्माण करने की अपेक्षा पोलीप्रोफीलीन का अधिक विनिर्माण करने की प्रवृति का पता चलता है।
- यह कि एचपीएल, एपीएल को प्रोपीलीन का एक मात्र आपूर्तिकर्ता है। प्रोपीलीन गैस के रूप में होती है, जिसको सीधे पाईपलाईन के माध्यम से प्रवाहित किया जा सकता है। यदि एपसीएल अथवा आईपीएल का संयंत्र प्रभावित होता है, तो ओक्सो-अल्काहोल्स (2-ईएच) के कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। किसी भी संगठन के लिए कच्चे माल के लिए मुख्यतया 2

- अथवा उससे अधिक आपूर्तिकर्ता होने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ओक्सो-अल्काहोल्स (2-ईएच) के कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है।
- यह कि यदि एचपीएल का इरादा पोलीप्रोफीलीन का विनिर्माण करने का होता है तो ऐसी स्थिति में क्या अन्य स्रोत एपीएल भारतीय बाजार में 2-ईएच की आपूर्ति कर सकेगा ? ऐसी स्थिति में 2-ईएच के सभी प्रयोक्ताओं को विवश्तः अपने संयंत्रों को बंद करना पड जाएगा।
- यह कि संबद्ध वस्तुओं के दीपक नाईट्राईट लिमिटिड जैसे कुछ ग्राहक, एथिल ऐक्सानोल (2-ईएच) से 2-एथिलहेक्सिल नाईट्रेट (2-ईसीएच) नामक सिटेने इम्प्रूवर विनिर्मित करते हैं, जिसका उपयोग रिफाईनरों द्वारा डीजल की ओक्टेन संख्या को बढाने के लिए किया जाता है। सिटेने इम्प्रूवर के ग्राहक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रिफाईनरियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इनके साथ ही निजी क्षेत्र में भी रिफाईनरियां हैं, जैसे कि रिलायन्स, ईस्सार, एचएमईएल और शैल। ऐसे ग्राहकों के साथ आपूर्ति की संविदाएं, सामान्यतया नियत कीमत की शर्त पर होती हैं, जिनमें इन ग्राहकों को आपूर्तियों में विलंब होने अथवा कोई आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में मौद्रिक मूल्य, काली सूची में शामिल करने और अन्य परिणामी कानूनी कार्रवाई करने जैसे दण्डात्मक प्रावधान निहित होते हैं। इसलिए घरेलू उद्याग द्वारा आपूर्तियों में रूकावट डालने से उनके उत्पादन और वाणिज्यिक हित प्रभावित होते हैं।
- यह कि याचिकादाता की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट के संबद्ध उद्धधृण स्वयं यह सिद्ध करते हैं कि कंपनी ने एचपीसीएल के पीआरयू के शुरू होने के बाद किए गए विस्तार से 1.5 महीने अर्थात् जुलाई-अगस्त, 2013 तक की अविध के लिए निर्धारित क्षमता में से का 110% प्रचालन क्षमता का उपयोग किया है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा जांच अविध के दौरान 39 % क्षमता का उपयोग करने का दावा अत्यिधिक त्रुटिपूर्ण है।
- यह कि याचिकादाता ने प्रत्यक्षत: कोई ग्राहक नहीं गंवाया है, क्योंिक उसने 100% से अधिक क्षमता उपयोग किया है और समग्र जांच अविध के दौरान उसका उत्पादन-बिक्री अनुपात 100% के निकटस्थ अथवा उससे अधिक रहा है। आयातों ने बाजार का हिस्सा मात्र लिया है, क्योंिक याचिकादाता अपर्याप्त क्षमता होने के कारण आपूर्ति नहीं कर सका था।
- यह कि क्षति अविध के दौरान संबद्ध देशों से पहुंच आयात कीमत में 11.6 % तक की वृद्धि हुई है, जो कि क्षति अविध में याचिकादाता द्वारा की गई कीमत वृद्धि से (8%) अधिक है।
- यह कि आवेदक को मात्रा प्रभाव (उत्पादन, बिक्रियों की मात्रा और क्षमता उपयोग) अथवा कीमत प्रभाव (नकारात्मक कीमत कटौती होने) के रूप में कोई क्षित नहीं हुई है। प्राधिकारी को पहुंच मूल्य, निबल बिक्री कीमत के गैर-कानूनी परिकलन और परिणामी संशोधित कीमत कटौती निर्धारण को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- यह कि माननीय ईएसटीएटी ने आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटिड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी -2006 (201) ई.एल.टी. 481 (ट्रिब्यूनल) के मामले में पहले क्षित और कारणात्मक संबंध के प्रमाण नहीं होने के आधार पर शुल्क के आदेश को रद्द कर दिया था। इसलिए प्राधिकारी को इस मामले को समाप्त कर दिए जाने और जब संयंत्र चल रहा था, नई जांच अवधि पर विचार करते हुए, नए मामले की शुरूआत करने की आवश्यकता है।
- यह कि जांच अविध के दौरान भारत की मांग 1,18,000 मी. टन थी, जब कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 48,000 मी.टन मात्र को पूरा करने की थी। घरेलू मांग के 2-5 गुणा अधिक होने की स्थिति में घरेलू उत्पादन के घरेलू प्रयोक्ता संबद्ध देशों से आयातों पर निर्भर करते हैं।

- यह कि 104 % की दर से क्षमता प्रचालन का उपयोग करने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अनुय कारणों से प्रभाव पड़ रहा है।
- यह कि आंतरिक कारणवश अधिक और अनिश्चित लागत, संबद्ध देशों से आयात होने के लिए जिम्मेदार हैं। याचिकादाता की विनिर्मित प्रति यूनिट विद्युत और भाप की खपत के बीच तुलना करने से वर्ष 2013-14 में अकुशलता के कारण उनमें वृद्धि पर्याप्त होने का स्पष्ट पता चलता है, जिसके फलस्वरूप तथा मुख्य कच्चा माल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्यतया प्रचालन बंद हो गया तथा बाद में पुन:शुरू हो गया।
- यह कि प्राधिकारी को याचिकादाता द्वारा लिए गए ऋण पर विचार करना चाहिए और क्षित रहित कीमत का निर्धारण करते समय केवल ऐसे ऋण को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि संबद्ध उत्पाद से संबंधित हैं अथवा उसका भाग है।
- यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षिति रिहत कीमत का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-3
 में निर्धारित सिद्धांतों को सख्ती से लागू करना चाहिए। घरेलू उद्योग का सकल अचल परिसम्पितयों
 पर अत्यधिक 26% प्रतिलाभ का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) घरेलू उद्योग के विचार

- 122. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न निवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त तर्क दिए हैं :-
 - यह कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन और खपत के के पिरप्रेक्ष्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा संबद्ध देशों से ऐसे आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं।
 - यह कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में हास कर रहे हैं और कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को रोक रहे हैं, जो कि पाटन नहीं होने की स्थिति में होती।
 - यह कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, माल सूचियों,
 बाजार के हिस्से, लाभ, निवेश पर प्रति लाभ, नकदी प्रवाह के रूप में तेजी से गिरावट आई है और ये नकारात्मक सुतर पर पहुंच गया है।
 - यह कि उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन उप-अनुकूलतम था। उसकी बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आने से उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है। तथापि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में ऐसी गिरावट आने का आंशिक कारण पाटित आयात हैं और आंशिक कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता है।
 - यह कि संबद्ध देशों से आयातों का पाटन मार्जिन अत्यधिक है तथा आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को अत्यधिक प्रभावित कर रही है, जिसके फलस्वरूप कीमत में ह्रास हो रहा है। प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।
 - यह कि भारत में बैंकों द्वारा पेश की जा रही ब्याज दर पर विचार करते हुए, ऐसे आयातक जो कि
 निर्यातकों से दीर्घावधिक ऋणों का लाभ उठा रहे थे, अब काफी कम दर पर ऋण प्राप्त कर रहे हैं, इस
 प्रकार वे घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में अत्यधिक सस्ते आयात कर रहे हैं। आयातों को
 प्राथमिकता देने का यह भी एक कारण है। इसलिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली और
 आयातों की पहुंच कीमत में तदनुसार उपयुक्त समायोजन किया जाना चाहिए।
 - यह कि जांच अवधि के दौरान कुछ समय के लिए अलाभप्रद कीमतें होने और कच्चे माल की आपूर्ति की कमी होने के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जांच अवधि के दौरान कुछ समय के लिए उत्पादन में कमी अन्य कारकों से हुई थी, याचिकादाता ने पाटित

आयातों के कारण क्षति तय करने के प्रयोजनार्थ निष्क्रिय समय लागत के लिए आवश्यक समायोजन किया है। ऐसा देखा जा सकता है कि याचिकादाता द्वारा जांच अवधि के दौरान सामान्य उत्पादन प्राप्त करने पर भी उसकी बिक्री कीमत, उत्पादन की लागत से कम है।

- यह कि प्राधिकारी या तो (क) उस अवधि को समाप्त कर दें, जिसमें समग्र क्षिति आंकडों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र बंद पड़ा हुआ था और उसके बाद घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करें अथवा (ख) घरेलू उद्योग के ऐसे कार्य-निष्पादन पर विचार करें, जो कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र को नुक्सान नहीं होने के कारण होता।
- यह कि एपीएल ओक्सों अल्कोहल्स यूनिट में अद्यतन और विश्व में उपलब्ध उच्च क्षमता युक्त श्रेष्ठ प्रोद्योगिकी स्थापित है। इसने अप्रत्याशित स्थिति को छोड कर, सुसंगत आधार पर उत्पादन के उच्च स्तर पर प्रचालन प्रमाणित किए हैं।
- यह कि वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, जबिक उसके संयंत्र
 की प्रचालन क्षमता 104% तक थी, जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उत्पाद के पाटन से घरेलू
 उद्योग को क्षिति हुई है।
- यह कि जांच अवधि के दौरान जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक पाटन सीमित था, क्षित अवधि अप्रैल, 2010 से जून, 2014 तक है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षित अवधि में हुए कार्य-निष्पादन पर विचार करते हुए यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को कोई क्षित हुई है।
- यह कि घरेलू उद्योग को पाटन-रोधी विधि के अंतर्गत राहत की मांग करने के लिए एक कानूनी पूर्वापेक्षा के रूप में देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने की स्थिति में स्थापित होने की आवश्यकता है। यह न केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी के दोहराए गए निर्णय हैं, बल्कि सीईएसटीएटी का {डीएसएम इंडेमित्शु लिमिटिड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2000 (119) ईएलटी 308 के मामले में} भी निर्णय है।
- यह कि 2-ईएचए की राष्ट्र की मांग की तुलना में एपीएल की उत्पादन क्षमता लगभग 35% है। मांग-पूर्ति में व्याप्त इस अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो कि तब तक निरंतर जारी रहेंगे, जब तक कि देश में इसकी अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित नहीं हो जाती हैं।
- यह कि घरेलू उद्योग द्वारा सूचित की गईं बिक्री कीमतें, ग्राहकों को आयातित उत्पाद की कीमतों पर आधारित हैं। तथापि, ग्राहकों द्वारा विदेशी आपूर्ति कर्ताओं को आर्डर देने और भारत में वस्तुओं के आने के बीच अत्यधिक समय लगता है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल कर देता है।
- यह कि चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित आयात कीमत पर निर्भर करती है, याचिकादाता का यह निवेदन है कि कीमत में कटौती का निर्धारण, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयात की पहुंच कीमत के साथ करके नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय प्राधिकारी को उसकी उस कीमत के साथ तुलना करनी चाहिए जिस पर ग्राहकों द्वारा घरेलू उद्योग और निर्यातकों को आर्डर दिए गए हैं। याचिकादाता ने इस संबंध में बिक्री की तारीख के मुद्दे का हवाला दिया है, जिसमें विश्वभर में व्यापक जांच की गई है।
- यह कि चूंकि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित आयात कीमत के आधार पर अपनी कीमत पर वार्ता करता है, कीमत में कटौती का निर्धारण वैकल्पिक रूप से ट्रेड जर्नलों में उल्लिखित कीमत को अपना कर किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट पता चलेगा कि कीमत में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है।

- यह कि यदि एसोसिएशन का यह तर्क है कि प्राधिकारी को निष्क्रिय समय लागत को अलग नहीं करना चाहिए था, प्राधिकारी तदनुसार आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी दोनों स्थितियों से पता चलेगा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति से अधिक क्षति हुई है।
- यह कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षित हुई है। यह स्वीकार किया जाता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित के तीन कारण हैं (क) देश में उत्पाद का पाटन, (ख) ऐसे कुछ समय तक जब तक कि घरेलू उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, उत्पाद का उत्पादन करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता तथा (ग) घरेलू उद्योग का जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक की अविध के दौरान कच्चे माल की उपलब्धता होने के बावजूद भी देश में अत्यधिक पाटन होने के कारण उत्पादन शुरू नहीं करने का निर्णय लेना, जिनके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक अनुचित कीमत उपलब्ध हुई थीं।
- यह कि क्षमता उपयोग का उचित स्तर प्राप्त करने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को अभी तक वित्तीय घाटा हो रहा है। जांच अवधि पश्चात घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय घाटे, नियोजित पूंजी पर प्रतिकूल प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में उसकी कीमत पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है, जो कि स्पष्टतया पाटन के कारण है।
- यह कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सीईएसटीएटी के निर्णय का हवाला देने मात्र से ऐसा पता चलता है कि प्राधिकारी को क्षित के विभिन्न कारकों की जांच करनी चाहिए। निर्णय से ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि इस कारण मात्र से कि घरेलू उद्योग को कुछ अन्य कारक प्रभावित कर रहे हैं, प्राधिकारी मामले में आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। नियमावली में "एक" कारणात्मक संबंध होने पर विचार करने का प्रावधान निहित है तथा न कि "विशेष" कारणात्मक संबंध होने पर विचार करना। इस संबंध में "विशेष" के स्थान पर "एक" को स्थापित करने का अत्यधिक महत्व है और इसका विश्व व्यापार संगठन के निर्णय द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब ऐसी कोई रेस ज्यूडिकेटा विद्यमान नहीं है कि (क) पाटन को क्षिति का एक मात्र कारण होने की आवश्यकता है, (ख) ऐसे अन्य कारक भी हो सकते हैं, जो कि उस समय घरेलू उद्योग को क्षिति पहुंचा रहे हों और (ग) अन्य कारकों के विद्यमान होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्राधिकारी जांच को समाप्त कर देंगे।
- यह कि उत्पादन संयंत्र में विद्युत की खपत के अंतिरिक्त विभिन्न प्रचालनों में कंपनी क्षरा विद्युत की खपत की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न प्रशासनिक सुविधाओं में खपत की गई विद्युत के तत्व शामिल हैं। संयंत्र में प्रयोज्यताओं की लागत सामान्य और उचित है तथा उसमें कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि हिबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है।
- यह कि विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन करने का विकल्प अपनाए जाने के कारण का यह तथ्य है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए विश्व बाजार की क्षमताएं, विचाराधीन उत्पाद की मांग से काफी अधिक हैं। इस प्रकार जबकि एसोसिएशन भारत में मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर पर विचार कर रही है, एसोसिएशन, अपने सदस्यों को सुज्ञात इस तथ्य को सुविधा पूर्वक छिपा रही है कि विश्व बाजार में उत्पाद अत्यधिक रूप से बेशी पडा हुआ है।
- यह कि ईएचए की जब से स्थापना हुई है तक से ही उसके उत्पादन से स्पष्ट पता चलता है कि
 याचिकादाता द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का कोई अनिश्चित पेटर्न नहीं है । वास्तव में
 याचिकादाता ने सुसंगत रूप से उत्पाद का उत्पादन किया है और अपनी क्षमताओं के अनुसार उसकी
 बिक्री की है तथा कभी-कभी उसने अपनी क्षमताओं से भी अधिक बिक्री की है।
- यह कि केवल 2 से 3 महीनों तक की अल्पाविध के लिए प्रोपीलीन की आपूर्ति में विघटन था, जो कि अप्रत्याशित स्थिति (आग लग जाने) के कारण था। उत्पादन की सीमान्त लागत से काफी अधिक अलाभप्रद बिक्री कीमतें होने के कारण, लंबी अविध तक संयंत्र बंद पडा हुआ था।

- यह कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धधृत आईसीआरए की रिपोर्ट, कम क्षमता उपयोग और अलाभप्रद बिक्री कीमतों के कारण कंपनी को हुए घाटों से उत्पन्न उसकी सकल वित्तीय स्थिति पर आधारित है।
- यह कि प्रोपीलीन विशेष रूप से ऐसा उत्पाद है, जो कि ऑयल रिफाईनिंग कंपनियों और/अथवा हाईड्रोकार्बन (जो कि अधिकतर नफाथा/प्राकृतिक गैस होती है) यूनिटों द्वारा निर्मित किया जाता है। सामान्यतया प्रोपीलीन ऐसी उत्पाद मद नहीं है और अधिकतर रिफाईनरी की प्रोपीलीन का उपयोग, पोलोप्रोपीलीन के लिए आर्थिक पैमाने की कमी होने के कारण पोलोप्रोपीलीन से भिन्न निचले स्तर के उत्पादों के लिए किया जाता है। ओक्सो अल्कोहल एक ऐसा उत्पाद है। ऐसे विशिष्ट उत्पाद के ऐसे एकल स्रोत पर आधारित परियोजनाएं, उद्योग में असमान्य नहीं हैं।
- यह कि जांच की शुरूआत किए जाने के बाद याचिकादाता ने डीजीसीआई एंड एस से कारोबार-वार आंकडे प्राप्त किए हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि प्रकाशित और कारोबार-वार आंकडों की बीच कोई वास्तविक अंतर व्याप्त नहीं है।
- यह कि वर्ष 2012-13 में उच्च स्तर का क्षमता उपयोग करने के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षिति हुई
 थी । वर्ष 2015-16 में अत्यधिक उत्पादन करने पर भी घरेलू उद्योग को निरंतर वित्तीय घाटे हुए
 हैं, जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसको संबद्ध देशों से पाटन के कारण क्षिति हुई है ।
- यह कि उत्पादन नहीं किए जाने के समय हुए विभिन्न व्यय को पहले से ही अलग किया गया है। याचिकादाता को आश्चर्य होता है कि ऐसे व्यय को अलग रखे जाने पर भी आंकडे अभी घाटा क्यों दर्शा रहे हैं। संयंत्र के बंद होने की अविध में हुए व्यय को अलग रखने के बावजूद लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में नकारात्मक वृद्धि से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रतिकूल प्रभाव पडा है।
- यह कि जब कि "उत्पादन नहीं होने" की अविध के दौरान कर्मचारियों की छंटनी नहीं की गई है, इस अविध के दौरान उनको अदा किए गए वेतन को, घरेलू उद्योग के लाभ का निर्धारण करने में शामिल नहीं किया गया है।
- यह कि कंपनी की स्थिति बहुत अनिश्चित है और एक मात्र आशा यह है कि कंपनी को अब संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संरक्षण प्राप्त हुआ है।
- यह कि विदेशी उत्पादकों द्वारा आयातकों को विशेष ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, जो कि सीधे घरेलू बिक्रियों को गैर-अर्थक्षम बना रहे हैं, क्योंकि याचिकादाता, ग्राहकों को किसी भी प्रकार का ऋण देने में असमर्थ है। दूसरी ओर याचिकादाता, सरकारी क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटिड से नकदी के आधार पर प्रोपीलीन खरीद रहा है। इसके फलस्वरूप याचिकादाता की कीमतों पर 3% का न्यूनतम प्रभाव पड रहा है, जो कि उसके प्रचालनों के लिए बहुत अधिक है। इसलिए आयात कीमतों को विधिवत् समायोजित किया जाना चाहिए ताकि उचित तुलना करने के लिए निर्यातकों द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋण संबंधी लाभ को निष्प्रभावित किया जा सके।
- यह कि जब कि आयातों पर तकनीकी रूप से वीएटी लगता है, व्यवहारिक रूप से आयातक ऐसी लागत का वहन नहीं करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा की गई सभी आपूर्तियों पर सीएसटी लगता है जिसके फलस्वरूप कीमतों में 2 % का हो जाता है। चूंकि ऐसे कर और प्रभार सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, सभी व्यवसायिक उद्यमों को इनका अनुपालन करने की आवश्यकता है।
- यह कि ऐसे अधिकतर आयात कांडला बन्दरगाह पर किए जाते हैं, जो कि इन उत्पादों के प्रमुख ग्राहकों से लगभग 250-300 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि इसका विरोध किया गया है, घरेलू उद्योग को अपने तैयार उत्पाद को लगभग 1000 किलोमीटर तक ले जाना पडता है, जबकि

कच्चे माल की अधिप्राप्ति, पाईपलाईन के माध्यम से अहाते पर ही कर ली जाती है, जिस पर कोई लागत व्यय नहीं होती है। भारतीय विनिर्माता क्षेत्र के लिए यह अनुचित है कि तैयार उत्पाद पर भाडे की लागत को अस्वीकार्य लागत मद के रूप में माना जाए और कच्चे माल के भाडे की लागत को उत्पाद की लागत का ही अंश माना जाए। यदि परिकलन करने का उद्देश्य "घरेलू उद्योग को क्षति" है, तो क्षति को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को ध्यान में रखने के बाद इसका परिकलन किया जाना चाहिए।

 यह कि एनआईपी का निर्धारण करने के लिए निदेशालय द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के फलस्वरूप अत्यधिक कम मात्रा में पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच

- 123. प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति प्रकार की होने तथा कारणात्मक संबंध के प्राचलों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का नोट किया है और उनकी चिन्ताओं का समाधान इस विश्लेषण के परवर्ती पैराओं में कर दिया है। क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में सामान्य मुद्दों की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है:
- 124. बढाई गई जांच अविध के दौरान संयंत्र के बंद होने के कारण उसको स्वयं हुई क्षिति और काराणात्मक संबंध नहीं होने के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से ऐसा पता चला है कि जांच अविध (15 महीनों की अविध) के दौरान 263 दिनों तक संयंत्र बंद पडा हुआ था। व्यापक जांच करने से ऐसा पता चलता है कि आग लगने और कुल 231 दिनों की अविध के लिए एचपीएल में अन्य अनुरक्षण मुद्दों के कारण प्रोपीलीन की आपूर्ति बाधित थी। हालांकि शेष अविध में प्रोपीलीन उपलब्ध थी, आईपीएल 2-ईएच की अलाभप्रद कीमतों के कारण उसको उठाने में विफल रही थी तथा एपीएल की उत्पादन सुविधा उक्त अविध के दौरान बंद पडी हुई थी।
- 125. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चा माल का एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। जांच से ऐसा पता चला है कि संबद्ध वस्तुओं के अधिकतर उत्पादन एकक ऐसे अहाते के प्रोपीलीन के उत्पादकों से संबंधित हैं और इसलिए कच्चे माल को प्राप्त करने का संपर्क सूत्र, जिस तरीके से याचिकादाता प्रचालन करता है, इस उत्पाद के लिए असमान्य नहीं है। जहां तक उत्पादन में कमी होने और उत्पादन की लागत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का संबंध है, इस मुद्दे का समाधान, उपयुक्त लागत का पता लगा करके और ऐसी लागत को उत्पादन और बिक्रियों की लागत के साथ नहीं मिला करके किया गया है, ताकि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षित के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने के लिए संयंत्र के बंद होने के कारण हुई क्षित के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जाए। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों की ऐसी चिंता का समाधान पर्याप्त रूप से कर दिया गया है।
- 126. एपीएल के मासिक उत्पादन और बिक्रियों के आंकडों की आगे जांच करने से ऐसा पता चला है कि एपीएल ने कुछ महीनों तक अपनी स्थापित प्रचालन क्षमता से अधिक उपयोग किया है। लेकिन उन महीनों में वस्तुओं की बिक्री वसूली से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों की तुलना में उनकी कीमतों के मानकीकृत होने के कारण उनकी लागत भी वसूल नहीं की जा सकी है। इस प्रकार इससे घरेलू उद्योग के इस तर्क की विश्वसनीयता बडी है कि अलाभप्रद कीमतें होने के कारण प्रोपीलीन के उपलब्ध होने पर भी उसे संयंत्र बंद करने के लिए बाध्य होना पडा है।
- 127. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि रिफाईनरियां प्रोपीलीन के बदले पोलीप्रोपीलीन का विनिर्माण करने की ओर विशेष रूप से प्रवृत हो रही हैं और इस प्रकार 2-ईएच के उत्पादन के लिए प्रोपीलीन की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा सभी वैश्विक उत्पादकों के लिए सही हो सकता है और इसलिए अकेले याचिकादाता घरेलू उद्योग को नियमावली के अनुसार अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से संरक्षण देने से मनाही नहीं की जा सकती है।

- 128. कुछेक प्रयोक्ताओं की इस चिंता के संबंध में कि उनके अंत प्रयोक्ताओं के साथ उनकी संविदाएं विलंबित प्रदानिगयों के लिए दंडों के साथ नियत कीमत की शर्तों पर हैं और घरेलू उत्पादक से आपूर्तियों के व्यवधान से उनके प्रचालन प्रभावित होते हैं तथा इसलिए उन्हें आयातों पर निर्भर होना पडता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क तंत्र का उद्देश्य अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के कारण बाजार में उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर करना और घरेलू बाजार में सभी व्यापारियों को समान कार्य क्षेत्र मृजित करना है। इसलिए घरेलू आपूर्ति में व्यवधान पड जाने पर इन प्रयोक्ताओं के लिए आयात का विकल्प बंद नहीं होजाता है। यह संबद्घ वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के हित में होगा कि आयातों पर पूर्णतया निर्भर रहने के बजाए उनके लिए घरेलू बाजार में अर्थक्षम और कुशल उत्पादक विद्यमान हो।
- 129. क्षति और कारणात्मक संपर्क होने के प्रमाण की कमी के आधार पर लगाए गए पूर्व शुल्क को समाप्त करने के सीईएसटीएटी के पूर्व निर्णय के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह एक पृथक जांच थी और उस मामले में सीईएसटीएटी का आदेश, उस समय विद्यमान स्थिति के वास्तविक सांचे पर आधारित था तथा उस निर्णय में प्राधिकारी द्वारा उस समय के कारकों की जांच की गई थी, इसलिए उसका इस जांच से कोई संबंध नहीं है। सीईएसटीएटी का पूर्व निर्णय किसी भी तरीके से प्राधिकारी को इस समय विद्यमान स्थिति के वास्तविक सांचे में नई जांच करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। प्राधिकारी ने इस जांच में अंतिम निर्णय लेने के लिए मौजूदा जांच अविध के दौरान विद्यमान क्षति और कारणात्मक संबंधों से जुडे कारकों की सार्थकपूर्ण नई जांच की है। इसलिए इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे तर्क युक्ति संगत नहीं हैं।
- 130. हितबद्ध पक्षकारों के इन निवेदनों के संबंध में कि प्राधिकारी को क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार निवेशपर अधिक प्रतिलाभ की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के दावों की ओर ध्यान दिए बिना, एनआईपी का निर्धारण करने के लिए समस्त जांच में नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है।
- 131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्री कीमतों और आयात कीमतों में अनेक समायोजन किए जाने का अनुरोध किया है ।
- 132. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि सामग्री की आपूर्ति पर घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए विशिष्ट घरेलू करों का समायोजन किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्य-गत घरेलू बिक्री कीमतों, सभी स्थानीय करों और प्रभारों की तुलना, आयात के पहुंच मूल्य से की गई है और स्थानीय प्रभारों के कारण और समायोजन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 133. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि भाडे में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण घरेलू बिक्रियों और आयातों की कीमत तुलना में भाडे की लागत को समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक विशेष स्तर पर सभी प्रकार की तुलना की जाती है। घरेलू उद्योग की कार्य-गत कीमतों की तुलना, प्रवेश बिन्दु पर आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की जाती है, क्योंकि कीमत की तुलन क्षमता के प्रयोजनार्थ उन पर व्यापार के उसी स्तर पर विचार किया जाता है। उत्पादकों और ग्राहकों की भौगोलिकीय अवस्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार वस्तुओं का सुगमता से परिवहन आदि शामिल हैं। इसी प्रकार आयातक एक विशिष्ट बन्दरगाह के माध्यम से वस्तुओं के आयात करना चाहेंगे जो कि उसमें निहित संभार तंत्र पर निर्भर करता है। यह विभिन्न व्यवसायिकों के वाणिज्यिक निर्णय होते हैं और कीमत की तुलनीय क्षमता के लिए इन कारकों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- 134. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि निर्यातकों द्वारा आयातकों को दी गई ऋण सुविधा के कारण तुलनीय क्षमता विकृत होती है और ऐसे ऋण का समायोजन किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच करने से ऐसा पता चला है कि निर्यातक आयातकों को दो किस्मों के ऋण प्रदान करते हैं, जिनमें से पहला ऋण 60-90 दिनों (कभी-कभी 180 दिनों तक) के लिए सामान्य निशुल्क उपयोग और दूसरा ऋण कुछ मामलों में एलआईबीओआर दरों पर ब्याज

का भुगतान करने पर 120 से 180 दिनों तक की अतिरिक्त ऋण अविध है, जबिक घरेलू उद्योग नकदी के आधार पर वस्तुओं की बिक्री करता है। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग के तर्क की जांच की गई है। सामान्यत्या निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्रियों के लिए स्थानीय मुद्रा में और निर्यात बिक्रियों के लिए विदेशी मुद्रा में नामित अल्पाविधक ऋण लागतों के आधार पर तय की गई सैद्धांतिक ऋण लागत को बीजक कीमतों से घटाया जाता है, तािक तुलना के लिए कार्य-गत कीमतें तय की जा सकें, क्योंकि यह एक ऐसा कारक होता है, जो कि घरेलू और विदेशी मुद्रा, ब्याज दरों और साथ ही ऋण की अविध में अंतर होने के कारण कीमत की तुलनीय क्षमता को प्रभावित करता है।

- 135. जहां तक भारत में घरेलू उद्योग की कार्य-गत निबल बिक्रियों की वसूली की तुलना करने का संबंध है, ऋण की अविध के बाद निर्यातक को आयातक द्वारा भुगताई गई आयातों की सीआईएफ कीमत को आयातक द्वारा लिए गए सैद्धांतिक ऋण के लिए समायोजित नहीं किया जाता है। ऐसा इस अवधारणा पर किया जाता है कि घरेलू उद्योग भी सामान्य व्यापारिक प्रथा अनुसार अपने ग्राहकों को कुछ ऋण अविध का लाभ प्रदान करता है। तथापि, कुछ मामलों में जैसा कि इस मामले में है, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की नकद बिक्री करता है, जबिक निर्यातक आयातकों को 270 दिनों तक की अविध के लिए ऋण प्रदान करते हैं और आयातक ऐसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। ऐसे ऋण में से कुछेक निशुल्क होते है और कुछेक का भुगतान एलआईबीओर की दरों पर किया जाता है, इसी प्रकार की शर्तों पर घरेलू ऋण की लागत बहुत अधिक होती है। इसलिए आयातक सस्ती दरों पर निर्यातकों से ऋण प्राप्त करके अत्यधिक ब्याज दर आर्बिट्रेज का लाभ उठाते हैं, जब कि भारत में घरेलू ऋण की लागत बहुत अधिक है। यह तर्क दिया गया है कि इससे आयात पर्याप्त रूप से सस्ते होते हैं और इस प्रकार ये कीमत प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आयातक देश के बाजार में कीमत की तुलनीय क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, विशेषतया उस स्थिति में जब कि घरेलू उद्योग वस्तुओं की बिक्री कोई ऋण लिए बिना करता है और ऐसी स्थिति में कीमतों में सामान्यतया छुट दी जाती है।
- 136. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया था कि ऋण लागत को हिसाब में रखने के लिए घरेलू बिक्री कीमतों अथवा आयातों के पहुंच मूल्य में इस प्रकार का कोई भी समायोजन, नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के सिद्धांतों को प्रभावित करेगा तथा नियमावली में संशोधन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-3 में केवल क्षति रहित कीमतों का निर्धारण करने के सिद्धांतों का उल्लेख है और वे क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए तुलना करने की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं हैं। इसलिए क्षति के प्रभाव का विश्लेषण करने अथवा क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए घरेलू कीमतों अथवा आयात कीमतों का किसी भी प्रकार का समायोजन, विधि के किसी भी प्रावधान से आहत नहीं होगा। इसके अपेक्षाकृत ऐसे समायोजन करने के सिद्धांत, करार और नियमावली से प्रकट होते हैं, जो ऐसे कारकों का समायोजन करने की अनुमित देते हैं, जिनसे कीमत की तुलनीय क्षमता प्रभावित होती है।
- 137. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में उसके द्वारा किए गए विभिन्न समायोजनों के अपने पूर्व तर्कों को दोहराया है और यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने याचिकादाता के (क) कंपनी को कच्चे माल और तैयार उत्पाद पर भाड़े की लागत पर खर्च करना होता है, (ख) किसी भी विनिर्माता को दो के बीच अनुकूलतम प्रयोग करना होता है, (ग) एन आई पी के भाग के रूप में कच्चे माल की भाड़े की लागत पर विचार किए बिना क्षिति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाड़े को शामिल करना स्वीकार कर दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्षितमार्जिन का निर्धारण करने के लिए लागत के रूप में तैयार उत्पाद की भाड़े की लागत पर विचार क्यों नहीं किया जाए। मात्र इस कारण से कि याचिकादाता ने कच्चे माल पर भाड़े की लागत से बचना चाहा है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को तैयार उत्पाद पर भाड़े की लागत स्वीकृत नहीं करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि ब्राजील क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए दो कार्य प्रणालियां अपनाता है- सीआईएफ आयात कीमत के साथ कारखानागत कीमत की तुलना करना और सुपुर्दगी कीमत की तुलना डीडीपी कीमतों के साथ करना। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों कार्य प्रणालियां उपयुक्त हैं और इन दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए ऋण की अवधि पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि कुछ मुद्दों पर

स्पष्टता की कमी है। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि ऋण के प्रभाव को, ''निर्यातक की लागत'' अथवा ''आयातक को लाभ'' के रूप में देखा जा सकता है । इसलिए ऐसे समायोजन की अनुमति दी जानी चाहिए।

- 138. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों का कुछ महत्व है, लेकिन फिर भी बढी हुई क्रेडिट अवधि और ब्याज दर आरबीट्रेज भी विनिमय दर के खतरे और लागत के खतरे भी अधिक होते हैं। जहां तक आयातित वस्तुओं के साथ तुलना करने के लिए भाड़े के समायोजन का संबंध है, जैसा पहले नोट किया गया है, प्राधिकारी की सुसंगत पद्धित के अनुसार विशेष स्तर पर सभी प्रकार की तुलना की गई हैं। इसलिए प्राधिकारी अपने इस विचार की संपृष्टि करते हैं कि कीमत की कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री होने का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ आयात कीमत/पहुंच मूल्य का निर्धारण संपूर्ण सूचना के बिना घरेलू बिक्रियों पर भाड़ा और प्रत्येक कारोबार के आधार पर निर्यात तथा प्राप्त किए गए ऋण की अवधि से जुड़े विभिन्न खतरों और उसकी अड़चनों के लिए किसी प्रकार का समायोजन करना उपयुक्त नहीं है।
- 139. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का समाधान, इस प्रकटन/अंतिम निर्णय में उनसे संबंधित भागों में किया गया है ।

ज. 3 क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

- 140. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में उसके संबद्ध भाग में ऐसा प्रावधान है कि संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारक और सूचक शामिल होंगे जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पडता है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।
- 141. जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक प्राचलों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है।

(क) पाटित आयातों के प्रभावों की मात्रा और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव

I. आयात की मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा

142. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में विशेष वृद्धि हुई है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, इसका निर्धारण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा यथा सूचित कारोबार-वार आयात आंकडों तथा कांडला बन्दरगाह से एकत्रित किए गए आंकडों का उपयोग किया गया है। इन आंकडों के अनुसार क्षति की जांच के दौरान संबद्ध वसुतुओं के आयात निमृनानुसार हैं:-

आयात की मात्रा	यूनिट	2010-	2011- 12	2012- 13	2013-14	जांच अवधि वार्घिकीकृत	जांच अवधि
पाटित आयात							
यूरोपीय यूनियन	मी.टन	10440	21429	17967	26248	31582	39477
इंडोनेशिया	मी.टन	0	0	3900	16386	23639	29549

कोरिया जन. गण.	मी.टन	171	0	2954	6413	5130	6413
मलेशिया	मी.टन	4748	8508	17441	21954	21353	26691
ताईवान	मी.टन	0	0	3019	6499	5199	6499
संयुक्त राज्य अमरीका	मी.टन	1180	2039	0	4632	3706	4632
	मी.टन						11326
कुल पाटित आयात		16539	31976	45280	82132	90609	1
प्रवृति	मी.टन	100	193	274	497	548	685
अन्य देश	मी.टन	16744	5093	14424	16592	18637	23296
प्रवृति	मी.टन	100	30	86	99	111	139
	मी.टन						13655
कुल प्रवृति		33283	37069	59704	98724	109246	7
	मी.टन	100	111	179	297	328	410

143. उपरोक्त आंकडो से पता चलता है कि क्षिति की जांच करने की अविध के दौरान वार्षिकीकृत आधार पर आयातों की कुल मात्रा में पूर्णरूपेण 3 गुणा वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में वार्षिकीकृत जांच अविध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में लगभग 5.5 गुणा वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों का हिस्**सा**

144. कुल आयातों में पाटित आयातों का हिस्स निम्नानुसार है :-

आयातों में बाजार का हिस्सा		2010- 11	2011- 12	2012- 13	2013- 14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
पाटित आयात							
यूरोपीय यूनियन	%	31%	58%	30%	27%	29%	29%
इंडोनेशिया	%	0%	0%	7%	17%	22%	22%
कोरिया जन. गण.	%	1%	0%	5%	6%	5%	5%
मलेशिया	%	14%	23%	29%	22%	20%	20%

ताईवान	%	0%	0%	5%	7%	5%	5%
संयुक्त राज्य अमरीका	%	4%	6%	0%	5%	3%	3%
उप योग	%	50%	86%	76%	83%	83%	83%
अन्य देश	%	50%	14%	24%	17%	17%	17%
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

145. उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों का हिस्सा, आधार वर्ष में कुल आयातों के लगभग 50 % से बढ़ कर जांच अविध में लगभग 83 % हो गया है, जिससे ऐसा पता चलता है कि आयात में अन्य देश के हिस्से का विशेष रूप से विस्थापन हो गया है।

III. मांग का मूल्यांकन/प्रत्यक्ष खपत

146. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का अनुमान, याचिकादाता की घरेलू बिक्रियों और समस्त स्रोतों से आयातों के योग के रूप में लगाया गया है, जो कि निम्नानुसार है : -

मांग	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि
					वार्षिकीकृत	15 महीने
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	35,922	49,401	47,642	20,304	25,381
संबद्ध देश	मी.टन	30,137	34,578	57,588	104,814	131,017
अन्य देश	मी.टन	3,146	2,491	2,116	4,432	5,540
मांग/खपत	मी.टन	69,206	86,470	107,347	129,550	161,937
प्रवृति		100	125	155	187	187

147. उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी मांग है और क्षित अविध के दौरान इनकी मांग में विशेष रूपए से वृद्धि हुई है। तथापि, जबिक आधार वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 87% की वृद्धि हुई है, फिर भी उसी अविध में पाटित आयातों में भी लगभग 550 % की वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2011-12 और 2012-13 में घरेलू उद्योग की बिक्री में अच्छी वृद्धि होने के बाद, उसमें विशेष रूप से गिरावट आई है। इस प्रकार पाटित आयातों में पूर्ण रूप से तथा घरेलू उत्पादन और मांग की दृष्टि से विशेष रूप से वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविकता यह है कि याचिकादाता की घरेलू बिक्रियों में मुख्य गिरावट आने का कारण जांच अविध के दौरान लंबे समय तक उसके संयंत्र का बंद पड़ा रहना था, जिसका आंशिक कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता होना और आंशिक रूप से उसके अन्य कारण थे, जिनमें अलाभप्रद कीमतें भी शामिल हैं, जैसा कि याचिकादाता ने दावा किया है।

(ख) पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

- 148. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में विशेष रूप से कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से विशेष सीमा तक कीमतों में हास हुआ है अथवा कीमतों में वृद्धि होने में रूकावट आई है, जो कि अन्यथा विशेष सीमा तक हो सकती थी।
- 149. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पडे प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत में ह्रास होने और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है।
- 150. जैसा कि उपरोक्त पैराओं में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री होने का विश्लेषण करने के लिए क्रेडिट लागत और परिवहन लागत के लिए क्रुछ समायोजन किए जाने चाहिए। तथापि, इनसे होने वाले अन्य खतरों और उनकी अडचनों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया है। इसलिए इस संगत में प्राधिकारी की सुसंगत पद्धित को अपनाया गया है।

(ग) पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभाव

151. कीमत कटौती का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का परिकलन करते समय सभी करों, छूटों, रिआयतों और कमीशन को घटाया गया है और पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने के लिए कार्य-गत स्तर पर बिक्री वसूली निर्धारित की गई है। तदनुसार संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभावों को तय किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

	0 20 0		2010-11	2011-	2012 12	
देश	कीमत कटौती का परिकलन	यूनिट	2010-11	12	2012-13	जांच अवधि
	घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	****	****	****
	प्रवृति		100	101	108	108
यूरोपीय		रू./मी.टन				
यूनियन	पहुंच मूल्य		89,426	87,455	95,918	95,247
		रू./मी.टन		(****)	(****)	(****)
	कीमत में कटौती		(****)			
	कीमत में कटौती का %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	सीमा	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)
		रू./मी.टन				
इंडोनेशिया	पहुंच मूल्य		0.00	0.00	95,392	95,704

		रू./मी.टन			(****)	(****)
	कीमत में कटौती		-	-		
	कीमत में कटौती का %	%	-	-	(****)	(****)
	सीमा	%			(0-10%)	(0-10%)
कोरिया जनवादी		रू./मी.टन				
गणराज्य	पहुंच मूल्य		85,279	-	1,01,472	96,932
		रू./मी.टन	(****)		(****)	(****)
	कीमत में कटौती			-		
	कीमत में कटौती का %	%	(****)	-	(****)	(****)
	सीमा	%	(0-10%)		(0-10%)	(0-10%)
		रू./मी.टन				
मलेशिया	पहुंच मूल्य		86,595	87,521	96,150	95,738
		रू./मी.टन	(****)	(****)	(****)	(****)
	कीमत में कटौती					
	कीमत में कटौती का %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	सीमा	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)
		रू./मी.टन				
ताईवान	पहुंच मूल्य		-	-	94,631	95,560
		रू./मी.टन			(****)	(****)
	कीमत में कटौती		-	-		
	कीमत में कटौती का %	%	-	-	(****)	(****)
	सीमा	%			(0-10%)	(0-10%)
		रू./मी.टन				
संयुक्त राज्य अमरीका	पहुंच मूल्य		71,570	88,759	-	96,341
		रू./मी.टन		(****)		(****)
	कीमत में कटौती		***		-	
	कीमत में कटौती का %	%	***	(****)	-	(****)
	सीमा	%	15-25%	(0-10%)		(0-10%)

<u>.</u>		रू./मी.टन				
समस्त सबद्ध देश	पहुंच मूल्य		87,297	87,555	96,239	95,640
		रू./मी.टन	(****)	(****)	(****)	(****)
	कीमत में कटौती					
	कीमत में कटौती का %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	सीमा	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)

152. उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि जांच अविध के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हुई है। तथापि, कीमत में कटौती होना ऐसी स्थिति में प्रासंगिक नहीं होता है, जब कि घरेलू कीमतों में पहले से ही ह्रास अथवा उनमें विशेष रूप से न्यूनीकरण हो रहा हो। इसलिए उपरोक्त अनुसार कीमत में कटौती के अतिरिक्त कीमत में ह्रास अथवा न्यूनीकरण, यदि कोई है, की भी जांच की गई है। घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि कीमत में कटौती मुख्यत: इसलिए नकारात्मक है क्योंकि निर्यातकों द्वारा अत्यिधक ऋण दिए गए हैं।

(ख) कीमत दबाव/ स्थिरता

153. जैसा कि उपर नोट किया गया है, पाटित आयातों का कीमत दबाव/ स्थिरता प्रभावों की भी जांच यह देखने के लिए कि गई है कि पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक दबाव अथवा स्थिरता आई है। घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों की कीमत दबाव प्रभाव का परीक्षण करने के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और पाटित आयातों का अवतरित मूल्य से किया गया है। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों को नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता का उत्पादन एकक जांच की अवधि के दौरान एक विस्तारित समयावधि के लिए बंद कर दिया गया था और इस कारण से इसकी लागत उत्पादन घाटे के कारण बहुत अधिक प्रभावित हो जायेगी। इसलिए उत्पादन की लागत का समायोजन उत्पादन में इस प्रकार के घाटे से किया गया है और जांच की अवधि की समायोजित लागत (यह मानते हुए कि उत्पादन घाटा नहीं हुआ था और उससे संबंधित निष्क्रिय लागत नहीं थी) पर विचार कीमत दबाव और स्थिरता की जांच के लिए किया गया है।

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि	समायोजित लागत के साथ जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./ किग्रा.	****	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100.00	106.86	119.90	140.33	133.87
बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	****	****	***	***
प्रवृत्ति		100.00	101.12	108.15	107.68	107.68
अवतरित मूल्य	रु./ किग्रा.	87.30	87.56	96.24	95.64	95.64
प्रवृत्ति		100.00	100.30	110.24	109.56	109.56

- 154. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्पादन की लागत धीरे धीरे बढ़ती रही है और यह 2012-13 से बहुत अधिक और पुन: जांच की अविध में भी जांच की अविध के दौरान उत्पादन घाटे के लिए लागत का समायोजन करने के बाद बहुत अधिक बढ़ गयी है। जबिक जांच की अविध के दौरान निष्क्रिय लागत और उत्पादन घाटे के लिए लागतों का समायोजन करने के बाद समायोजित लागत आधार वर्ष की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक थी, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में लगभग 7 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी के निर्धारण के लिए विचारित जांच की अविध के दौरान सामान्य लागत भी आधार वर्ष की तुलना 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उसी अविध के दौरान मूल कच्चा माल अर्थात प्रोपिलिन की कीमतों का विश्लेषण आधार वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि दर्शाता है। आयातों का भारित औसत अवतरित मूल्य में उसी अविध के दौरान लगभग 9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को अत्यिधिक पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण अपने बाजार को बनाये रखने के लिए मूल्यों को कम रखने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- 155. घरेलू उद्योग जांच की अवधि में कुछ समय तक आंशिक रूप से एकमात्र आपूर्तिकर्ता अर्थात एच पी सी एल से कच्चे माल की कमी के कारण और आंशिक रूप से एक विस्तारित अवधि के लिए अलाभप्रद कीमतों के कारण सामान्य उत्पादन प्राप्त नहीं कर सका। उपुर्यक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि यदि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में सामान्य उत्पादन प्राप्त करने में सफल भी हो जाता तो लागत बिक्री मूल्यों, जिन पर वे उसी बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के प्रभावों के कारण घरेलू बाजार में बेच पाता, से बहुत अधिक होता। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि एचपीसीएल से आपूर्ति शुरू होने के बाद भी संयंत्र के बंद होने से घाटे कम होते क्योंकि ये कीमतें लाभप्रद नहीं थीं। इस कारण से घरेलू उद्योग की कीमतें उस सीमा तक बाजार हिस्से को बनाये रखने के लिए स्थिर प्रतीत होती है कि वे इस अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री कर सकते थे और वह कीमत में ऋणात्मक कटौती के कारणों का उल्लेख करता है।

(ग) पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव

156. कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव की जांच करने के उद्देश्य से संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से आयातों की अवतरित कीमतों की तुलना इस नियमावली के अनुबंध-।।। में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांच की अविध के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की हानि रहित बिक्री कीमत से की गई है। पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री मार्जिन नीचे दिया गया है :

देश	एनआईपी रु./ किग्रा.	अवतरित मूल्य रु./ किग्रा.	कम कीमत पर बिक्री रु./ किग्रा.	कम कीमत पर बिक्री का %	रैंज
ई. यू.	***	95.25	***	***	0-10%
इंडोनेशिया	***	95.70	****	***	0-10%
कोरिया गण राज्य	***	96.93	****	****	0-10%
मलेशिया	***	95.74	***	***	5-15%
ताइवान	***	95.56	***	***	0-10%
यू. एस. ए.	****	96.34	***	***	0-10%

157. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की हानि रहित कीमतों से कम है यद्यपि कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन छोटे दायरे में है।

ज. 4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंडों की जांच

(क) क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

158. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के कुल 455 दिनों में से संयंत्र केवल 192 दिनों तक चालू रहा था। याचिकाकर्ता के रिकार्डों के अनुसार संयंत्र को उस संयंत्र में भीषण आग लगने तथा अनुरक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों के कारण एचपीसीएल से मूल कच्चा माल अर्थात प्रोपिलिन की उपलब्धता न होने के कारण बंद करना पड़ा था। कच्चे माल की आपूर्ति शुरू किए जाने के बाद भी और उस संयंत्र को पाटित आयातों की बढ़ी हुई मौजूदगी के कारण कम कीमत की स्थिति के कारण चालू किया गया और उत्पादन लगभग 118 दिनों तक अनियमित रूप से अस्थिगित किया गया, जिसके फलस्वरूप बहुत कम उत्पादन हुआ और क्षमता का उपयोग नहीं हो सका। इस कारण से उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री को यह मानते हुए दर्शाया है कि संयंत्र बंद नहीं किया गया था, हानि के एक कारक के रूप में संयंत्र को बंद करने को अलग रूप में देखा गया था और यह देखा गया कि क्या याचिकाकर्ता उस स्थिति में भारी मात्रा में उत्पादन और बिक्री कर पाता यदि संयंत्र को कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण बंद नहीं किया गया होता।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिक रूप में)	जांच की अवधि (वास्तविक)	जांच की अवधि (अनुमानित)
क्षमता	मी. ट.	44,000	48,000	48,000	48,000	60,000	60,000
उत्पादन	मी. ट.	36,126	48,967	49,775	18,570	23,212	40742
प्रवृत्ति		100	136	138	51	64	113
क्षमता उपयोग	%	82%	102%	104%	39%	39%	68%
प्रवृत्ति		100	124	126	47	47	83
घरेलू बिक्री	मी. ट.	35,922	49,401	47,642	20,304	25,381	44548
प्रवृत्ति		100	138	133	57	71	124
मांग/ खपत	मी. ट.	69,206	86,470	107,347	129,550	161,937	
प्रवृत्ति		100	125	155	187	187	

- 159. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जबिक 2011-12 में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के प्रत्युत्तर में लगभग 10 प्रतिशत क्षमता वृद्धि हुई थी, और याचिकाकर्ता को 2012-13 तक 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त हो रहा था, जांच की अविध में बहुत अधिक उत्पाद घाटा हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्षमता का बहुत कम उपयोग हुआ और बिक्री की मात्रा भी बहुत कम हुई।
- 160. इसके अलावा, उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते है कि यदि कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है और संयंत्र उन 192 दिनों तक चालू रखा जाता तब उत्पादन और क्षमता उपयोग क्रमश: 40742 मी. ट. और 68 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच

जाता जबिक इस उत्पाद के लिए मांग उसी अविध के दौरान अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस संयंत्र को शेष 118 दिनों तक कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा के कारण नहीं बल्कि पाटित आयातों के कारण अलाभप्रद कीमतों के कारण बंद किया गया था। जबिक लागतों में वृद्धि हुई थी, कीमतें पाटित आयातों की अत्यिधिक मात्रा के मौजूद रहने के कारण कम रही थी।

(ख) लाभप्रदता, लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रभाव पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

161. घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत और उससे संबंधित अन्य लागत तथा बिक्री कीमत का परीक्षण जांच की अविध के दौरान याचिकाकर्ता के उत्पादन घाटे के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखकर किया गया है। घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई				जांच की अवधि	
		2010-11	2011-12	2012-13	वार्षिक रूप में	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	****	***	****	***	***
प्रवृत्ति		100	106.85	119.90	133.86	133.86
बिक्री मूल्य	रु./ किग्रा.	***	****	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101.13	108.15	107.68	107.68
लाभ/ हानि	रु./ किग्रा.	***	****	***	(****)	(****)
प्रवृत्ति		100	61.50	27.10	-72.80	-72.52
नकद लाभ	रु./ किग्रा.	***	****	***	(****)	(****)
प्रवृत्ति		100	61.94	26.48	-69.57	-69.57
ब्याज से पूर्व लाभ	रु./ किग्रा.	***	****	***	(****)	(****)
प्रवृत्ति		100	56.99	31.14	-38.45	-38.45
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	****	***	(****)	(****)
प्रवृत्ति		100	82.61	43.48	-26.09	-26.09

162. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच की अविध में बिक्री कीमत में मामूली गिरावट को छोड़कर जांच की अविध में बिक्री की लागत और बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई। हालांकि बिक्री की कीमत में वृद्धि पाटित आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि के कारण कीमत में स्थिरता की वजह से लागत में वृद्धि की तुलना में कम थी और इस कारण से लाभप्रदता में कमी आई। नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में बहुत तेजी से गिरावट आई है और यह जांच की अविध में ऋणात्मक हो गया है। कुल लागत से निष्क्रिय समय के कारण किए गए लागत को अलग करने के बाद भी लाभप्रदता दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटन के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से इसमें बहुत अधिक गिरावट आई है।

(ग) बाजार हिस्से पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

163. भारतीय बाजार में विभिन्न भागीदारों का बाजार हिस्से में प्रवृत्तियां नीचे दर्शायी गई हैं :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि वार्षिक रूप में
घरेलू उद्योग	%	51.91%	57.13%	44.38%	15.67%
संबद्ध देश – आयात	%	23.90%	36.98%	42.18%	69.94%
अन्य देश - आयात	%	24.19%	5.89%	13.44%	14.39%
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

164. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का 2011-12 तक भारतीय बाजार में बहुत सबल स्थान था जब भारतीय मांग का 52 प्रतिशत पर इसका अधिकार था। उसके बाद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट आयी है जबिक पाटित आयातों ने उस स्थान को प्राप्त कर लिया। 2012-13 में भी जब यह उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहा था तब इसने पाटित आयातों के बाजार हिस्सा खो दिया था। हालांकि जांच की अविध में बाजार हिस्से में कमी का एक हिस्सा कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट के कारण उत्पादन में कमी के कारण हुई थी। उस कारण को हटा देने के बाद भी पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्से में कमी बहुत अधिक थी और यह वास्तविक था। इस तथ्य पर विचार करने के बाद भी कि कच्चे माल में आपूर्ति में बाधा अगर नहीं हुई होती और संयंत्र इस अविध के दौरान चालू रहता, अनुमानित बाजार हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत तक होता। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को जांच की अविध के दौरान पाटित आयातों से एक बहुत बड़ा बाजार हिस्से का नुकसान हुआ है।

(घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

165. याचिकाकर्ता कंपनी उसी उत्पादन श्रृंखला में अनेक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करता है। इस कारण से रोजगार पर संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयातों का प्रभाव हानि का एक बहुत अच्छा संकेतक नहीं हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन सहित विभिन्न कारणों से एक लंबी अविध तक इस अविध के दौरान उत्पादन स्थिगित रखा गया। अत: रोजगार और मजदूरी और उत्पादकता मानदंड इस मामले में हानि के संकेतकों के रूप में संगत नहीं हैं। तथापि, उसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
					वार्षिक रूप में
कंपनी के लिए कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	****	****
प्रवृत्ति		100	102	121	120
वेतन एवं मजदूरी	रु. लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	116	144	129
उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी	रु./ किग्रा.	****	***	****	***
प्रवृत्ति		100	86	105	252
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	133	114	43

166. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 2011-12 में क्षमता में वृद्धि और उत्पादन की मात्रा के अनुरूप, 2012-13 में रोजगार के स्तर और मजदूरी में वृद्धि हुई और हानि की अविध के प्रथम 3 वर्षों के दौरान प्रति इकाई मजदूरी लागत लगभग स्थिर रही है। परंतु उत्पादन में बहुत अधिक घाटे के कारण, जांच की अविध में उत्पादन में प्रति इकाई मजदूरी लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जहां तक उत्पादकता का प्रश्न है, प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2011-12 में बहुत अधिक थी, जब इस इकाई ने 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया। जांच की अविध में उत्पादकता में इस अविध के दौरान कम उत्पादन के कारण बहुत अधिक गिरावट आई है।

(ङ) विकास पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

167. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के साथ यह उद्योग 2012-13 तक विकास के मार्ग पर था। परंतु जांच की अविध के दौरान सभी वास्तिवक और द्वितीय मानदंड अत्यधिक विपरीत प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। बिक्री, उत्पादन, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश और आय और नकदी के प्रवाह के संबंध में विकास जांच की अविध के दौरान बहुत अधिक ऋणात्मक रही है।

विकास	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि वार्षिक रूप में
उत्पादन	वाई/ वाई	-	36%	2%	-63%
घरेलू बिक्री	वाई/ वाई	-	38%	-4%	-57%
बिक्री की लागत	वाई/ वाई	-	7%	12%	17%
विक्रय मूल्य	वाई/ वाई	-	1%	7%	0%
लाभ/ (हानि)	वाई/ वाई	-	-38%	-56%	-532%
निवेश पर आय	वाई/ वाई	-	-4%	-9%	-23%

(च) माल सूची पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

168. घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति दर्शाती है कि इस देश में अच्छी मांग के बावजूद याचिकाकर्ता का औसत माल भंडार 2012-13 में उचित कीमत पर घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री करने में असमर्थ रहने के कारण और पाटित आयातों के कीमत दबाव के स्पष्ट कारण से जांच की अविध में वृद्धि हुई है।

भंडार (मात्रा)	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि वार्षिक रूप में
प्रारंभिक	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	146	48	526
अंतिम	मी. ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	33	362	28
औसत	मी. ट.	***	***	***	****
प्रवृत्ति		100	79	234	231

(छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

169. प्रारंभिक जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं जो अनेक डाउन स्ट्रीम उत्पाद जैसे प्लास्टीसाइजर हैं, के लिए भारत में अच्छी मांग है। हालांकि घरेलू क्षमता मांग का लगभग 40 प्रतिशत है। इस कारण से आयात घरेलू कीमतों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से पाटित आयात प्रारंभ में घरेलू मांग का लगभग 30 प्रतिशत था जो मांग का लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ये आयात पाटित कीमतों पर और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम पर होते हैं, जिससे कीमत पर बहुत अधिक दबाव हो जाता है और घरेलू उद्योग के लिए कीमतें अलाभप्रद हो जाती हैं।

(ज) पूंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता

170. याचिकाकर्ता ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से क्षमता में वृद्धि करने के लिए 2010-11 में निवेश किया है। 2012-13 तक अच्छे कार्य निष्पादन की अविध के बाद, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पाटित आयातों के प्रभाव सिहत विभिन्न कारणों से बदतर हो गया। घरेलू उद्योग के लाभ में वित्तीय घाटे की स्थिति के कारण बहुत अधिक गिरावट आई है। इस कारण से इस उद्योग के आगे विस्तार करने अथवा क्षमता में वृद्धि करने की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होता है।

(झ) पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

171. घरेलू उद्योग की संभावित हानि के एक संकेतक के रूप में पाटन मार्जिन यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों/ क्षेत्रों में से प्रत्येक से हानि का मार्जिन सामान्य से अधिक और अत्यधिक है।

ज. 5 हानि के संबंध में निष्कर्ष

172. उपुर्यक्त जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से आयात पाटित कीमत पर अत्यधिक मात्रा में भारतीय बाजार में हो रहा है। आयात की मात्रा और वह कीमत जिस पर उनका निर्यात संबद्ध देशों से किया जा रहा है, से घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसे उत्पादन में गिरावट में दर्शाया है (यदि आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन घाटे को शामिल भी कर लिया जाये) और वित्तीय कार्य निष्पादन में बहुत अधिक गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप जांच की अविध में घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर आय, और बहुत अधिक सीमा तक नकद लाभ के मामले में बहुत अधिक गिरावट आई है। अत: प्राधिकारी यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव प्रतिकूल रहा है और उद्योग को बहुत अधिक हानि हुई है।

ज.6 हानि मार्जिन

173. घरेलू उद्योग की हानि रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। विभिन्न देशों से आयातों का अवतरित कीमत की तुलना संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से आयात किए गए संबद्ध पाटित वस्तुओं के हानि के मार्जिन के निर्धारण के लिए इस प्रकार से निर्धारित हानि रहित कीमत से की गई है। ये आंकड़े दर्शाते है कि संबद्ध देशों/ क्षेत्रों में से अधिकांश से आयातों की अवतरित कीमत घरेलू उद्योग के लिए परिकलित हानि रहित कीमतों से बहुत कम है।

उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी यू. एस. \$/ मी. ट.	अवतरित मूल्य यू. एस. \$/ मी. ट.	आई. एम. यू. एस. \$/ मी. ट.	आई. एम. %	आई. एम. रैंज
यूरोपीय यूनिय	न					
जर्मनी	आईसीसी केमिकल्स कॉरपोरेशन	****	****	***		
	पेट्रोकेम मिडल ईस्ट फर्टि.	****	****	****		
	विनमार इंटरनेशनल लिमि.	****	****	****		
	समग्र	****	****	****	****%	0-10%
ई.यू. अन्य स	मी नी					
कोई भी	कोई भी	****	***	****	****%	0-10%
मलेशिया						
बीपीसी	बीपीसी	****	****	****	****%	0-10%
अन्य सभी (म	नेशिया)					
कोई भी	कोई भी	****	***	****	****%	0-10%
दक्षिण कोरिया						
एल जी केम	हुंडई कॉरपोरेशन	****	****	****		
एल जी केम	विनमार	****	***	****		
एल जी केम	समग्र	****	****	****	(****%)	नकारात्मक
अन्य सभी दि	क्षेण कोरिया					
कोई भी	कोई भी	***	***	****	****%	0-10%
इण्डोनेशिया						
पीटी पीओएन	सीधे विक्री	***	***	***		
	सोजिटद्यज एशिया प्रा. लिमि.	****	****	****		
	समग्र	****	****	****	****%	0-10%
इण्डोनेशिया ः	प्रन् य सभी					
कोई भी	कोई भी	****	****	****	****%	0-10%

संयुक्त राज्य	अमेरिका के सभी निर्यातक					
कोई भी	कोई भी	****	****	****	****%	0-10%
चाईना ताइपेई						
कोई भी कोई भी		****	****	****	****%	0-10%

झ. कारणात्मक संबंध और आरोपहीनता विश्लेषण

174. उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हुई है तथा जैसा कि पूर्व में रिकार्ड किया गया है हितबद्ध पक्षकारों ने ठोस तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई हानि, यदि कोई हो, उनके एकमात्र आपूर्तिकर्ता से मूल कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट सहित अन्य कारणों से हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटन हानि का एक मात्र कारण नहीं हो सकता। अन्य कारण भी सकते हैं जो साथ साथ घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहे हों। अन्य कारकों की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी इस जांच को समाप्त कर देंगे अथवा हानि और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध नहीं पायेंगे।

175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबिक घरेलू उद्योग को साथ साथ इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनेक कारकों के कारण हानि हो रही है, यह सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि क्या उनकी मात्रा और कीमत के प्रभावों के द्वारा पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर पाटित आयातों को अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई जा रही हानि का आरोप लगाये बिना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व भाग में जांच दर्शाती है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर मात्रा के मामले में बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाटित आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग के लिए कीमत को बहुत अधिक स्थिर रखना पड़ा है। अत: कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन घाटे के कारण हुई हानि को अलग करने के बाद भी घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही हानि और पाटित आयातों के बीच एक घनात्मक कारणात्मक संबंध है। ऐसा सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी ने इस बात को देखने के लिए अन्य अनिवार्य मानदंडों की जांच की है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक घरेलू उद्योग को हानि का कारण हैं, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित अनिवार्य कारकों की जांच उन कारकों के साथ साथ की गई है, जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नीचे किए गए अपने अनुरोध में सामने लाया गया है:

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमत

176. उपर्युक्त विश्लेषित आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा कुल आयातों की तुलना में तथा पाटित आयातों की तुलना में बहुत कम है।

						जांच की अवधि
विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	वार्षिक रूप में
पाटन आयात	मी. ट.	16539	31976	45280	82132	90609
प्रवृत्ति		100	193	274	497	548
अन्य देश	मी. ट.	16744	5093	14424	16592	18637
प्रवृत्ति		100	30	86	99	111
कुल	मी. ट.	33283	37069	59704	98724	109246
प्रवृत्ति		100	111	179	297	328

177. जबिक पाटित आयात में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 450 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अन्य अपाटित स्रोत्रों से आयात में आधार वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबिक मांग में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो यह दर्शाता है कि उनसे घरेलू उद्योग को हानि नहीं हो सकती थी।

(ii) मांग में कमी और/ अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

178. मांग और खपत की जांच दर्शाती है कि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी मांग है और किसी प्रतियोगी उत्पाद के लिए उपभोक्ता की पसंद में कोई बदलाव नहीं आया है। इस कारण से मांग वह कारक नहीं है जिसका घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

(iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है। संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं है और इन वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आयात और व्यापार किया जा रहा है। इसलिए भारत में व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं अथवा अनुचित प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग को हानि का कारण नहीं हो सकती थी।

(iv) प्रौद्योगिकी का विकास

180. उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और नही आने वाले समय में ये परिवर्तन होना संभावित है। संबद्ध देशों में प्रतिवादी उत्पादक भी वैसी ही प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राद्योगिकी को घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले एक कारक के रूप में उल्लेख करते हुए कोई तर्क नहीं दिया गया है।

(v) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

181. घरेलू उद्योग ने समग्र हानि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। अत: निर्यातक कार्य निष्पादन याचिकाकर्ता को होने वाली हानि का कारण नहीं हो सकता है।

(vi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दे

- 182. इन अनिवार्य आरोपहीनता कारकों के अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को मूल कच्चे माल की इसके एकमात्र आपूर्तिकर्ता अर्थात मैसर्स एचपीसीएल से अनुपलब्धता के कारण जांच की अविध के दौरान एक विस्तारित अविध तक संयंत्र को बंद रखने के कारण घरेलू उद्योग को हुई हानि के बारे में इस मामले से संगत अन्य कारकों का समाधान करना चाहिए। प्राधिकारी ने पहले नोट किया था कि जांच की अविध के दौरान विशाखापटनम के पास स्थित याचिकाकर्ता का उत्पादन इकाई 2013-14 और 2014-15 की पहली तिमाही की अविध को शामिल करते हुए जांच की अविध के 15 महीनों में से 263 दिनों तक बंद रही। इन 263 दिनों में से यह संयंत्र एचपीसीएल से उस संयंत्र में भीषण आग के कारण आपूर्ति में रुकावट के कारण 145 दिनों तक बंद रहा। शेष 118 दिन उत्पादन को याचिकाकर्ता द्वारा आकर्षक ऋण शर्तों पर बहुत अधिक बढ़ी हुई मात्रा में लागत से बहुत कम मूल्य पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण लागत वसूलने के लिए उचित मूल्य पर भी उस बाजार में उत्पाद की बिक्री करने में समर्थ न होने के कारण अनियमित अंतराल पर बंद रखना पड़ा।
- 183. जैसा पूर्व में नोट किया गया है, संभावित उत्पादन, बिक्री और लागत, यदि उत्पादन में कच्चे माल के कारण नुकसान नहीं हुआ होता, तय किया गया है और यह नोट किया गया है कि यदि उत्पादन में बाधा नहीं भी हुई होती तब याचिकाकर्ता को कीमत के मानदंडों के कारण पाटित आयातों की वजह से बहुत अधिक हानि हुई होती। वास्तव में यदि याचिकाकर्ता ने इस अविध के कारण उत्पादन किया होता और उत्पादन की इसकी लागत से कम मूल्य पर घरेलू बाजार में इसे बेचा होता तो घाटा अधिक हुआ होता। लागत पर संयंत्र के बंद होने के प्रभाव को अलग रखने के उद्देश्य से आपूर्ति में बाधा के कारण, हानि के विश्लेषण हेतु यह आरोपित नहीं करने हेतु कि पाटित आयातों को हानि का एक भाग, लागत का

समायोजन निष्क्रिय लागत के लिए किया गया है जैसा कि इस विश्लेषण के लिए पहले नोट किया गया है। इस कारण से उत्पादन घाटे के कारण हुई हानि पाटित आयात के कारण नहीं हुई है।

ञ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक : -

184. उपर्युक्त जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की कीमतें इसकी उत्पादन लागत से कम कीमतों पाटित आयातों के बहुत अधिक बढ़ी हुई मात्रा की मौजूद रहने के कारण बहुत अधिक दबाव में है और इससे घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री में बने रहने के लिए लाभप्रद कीमत प्राप्त करने में बाधा आई है। बिक्री की मात्रा में गिरावट से कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन घाटे को ध्यान में रखने के बाद भी उत्पादन और क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सभी कारकों के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई है। साथ ही साथ घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य ज्ञात कारकों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अविध के दौरान कुछ समय के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन में हानि का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा परंतु उस कारक को उस सीमा तक अलग रखते हुए पाटित आयातों से नहीं हुई है। अत: प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हानि पाटित आयातों से हुई है यद्यपि याचिकाकर्ता का कार्य निष्पादन भी ऊपर में उल्लिखित कच्चे माल की बाधाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई था।

ट. क्षति निर्धारण करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात निवेदन

185. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने संबंधित प्रकटन पश्चात निवेदनों में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पूर्व प्रकट किए गए अधिकतर अपने विचारों को दोहराया है जिनका निदान इस निर्णय के संबद्ध खंडों में कर दिया गया है। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए ऐसे तर्कों को यहां दोहराया नहीं गया है। क्षति और कारणात्मक संबंधों का विश्लेषण करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणियों का निदान जितना प्रासंगिक समझा गया, उतना यहां कर दिया गया है।

ट. 1 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे :

- 186. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात अन्य बातों के साथ-साथ किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :
 - i. यह कि कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है, यह स्वीकार्य तथ्य है कि घरेलू उद्योग की कीमतें, ह्रास कीमतें हैं। ये ह्रास कीमतें पाटित आयातों के कारण हो रही हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाई गई कीमत कटौती मुख्यत: इसलिए नकारात्मक है क्योंकि निर्यातकों द्वारा अत्यधिक ऋण दिया जा रहा है और प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभाव की अनदेखी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रकटन विवरण में इस तथ्य की संपुष्टि हुई है कि निर्यातकों द्वारा अत्यधिक निशुल्क ब्याज पर ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।
 - ii. यह कि पाटित आयातों के प्रभाव से अत्यधिक मात्रा में कीमतों में ह्रास हुआ है और यदि ये नहीं होते तो उनमें अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होने की संभावना होती। इस प्रकार घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटे हो रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव प्रतिकूल पड़ रहे हैं जैसािक विभिन्न संबद्ध आर्थिक कारकों और संकेतकों के सामृहिक और संचयी मूल्यांकन से सिद्ध होता है।
 - iii. यह कि प्राधिकारी ने जांच को समाप्त करने का पहले ही प्रस्ताव किया है और उन्होंने घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने का कोई अवसर दिए बिना क्षति का विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने मौके पर जांच नहीं की है और पाटन मार्जिन को न्यूनतम मानते हुए जांच को अभी समाप्त नहीं किया है।
 - iv. यह कि प्रकटन विवरण से यह पता चलता है कि एल जी के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है। उपलब्ध सूचना से यह देखा जा सकता है कि कोरिया से आयात कीमत वास्तविक रूप से जांच के अंतर्गत अन्य देशों से आयात कीमत से भिन्न है। ऐसी स्थिति में याचिकादाता को यह स्पष्ट पता नहीं लगता कि कोरिया के लिए क्षति मार्जिन कैसे नकारात्मक है।
 - v. यह कि लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट लागत लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार की गई है जिसमें लागत लेखा परीक्षकों ने निष्क्रिय समायाविध के लिए खर्चों को पहले से ही बाहर रखा है। इस प्रकार लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लागत लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किए गए व्यय वे व्यय हैं जोकि कंपनी द्वारा उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने पर खर्च किए गए थे और इनमें उस अविध के खर्चे शामिल नहीं हैं जब

याचिकादाता ने उत्पादक का उत्पादन नहीं किया था। इस प्रकार, प्राधिकारी को लागत लेखा परीक्षा विवरण के अनुसार व्यय पर विचार करना और इस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए कि याचिकादाता का संयंत्र उस अवधि में बंद पड़ा हुआ था।

vi. यह कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है, जबकि जांच अवधि के दौरान बड़ी हुई अवधि के लिए कच्चे माल में अवरोध आने के कारण उसका संयंत्र बंद पड़ा हुआ था।

ट. 2 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच :

- 187. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच कर ली गई है जोकि निम्नानुसार है :
 - i. घरेलू उद्योग द्वारा क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के बारे में प्रकट किए गए के विचारों के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी की सामान्य पद्धति के अनुसार इसका निर्धारण किया गया है और इसलिए ऐसे निर्धारण में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।
 - ii. जहां तक एल जी के लिए नकारात्मक क्षित मार्जिन का संबंध है, यह नोट किया जा सकता है कि क्षिति मार्जिन का निर्धारण वास्तविक सीआईएफ कीमत और उक्त कंपनी द्वारा निर्यात के पहुंच मूल्य के आधार पर किया जाता है। यह नोट किया जा सकता है कि जांच अविध के दौरान कोरिया जनवादी गणराज्य से कुल आयात 6413 मी.ट. के थे, एल जी कैम ने केवल मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत का ही निर्यात किया था। इसलिए समग्र कीमत की तुलना से उक्त देश से सहयोगी निर्यातक के क्षित मार्जिन के स्तर की सही छिव प्रकट नहीं हो सकती है।
 - iii. जहां तक सऊदी अरब के खिलाफ जांच को समाप्त करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी समाप्ति नियमावली के नियम-14 (ख) के अनुसार आवश्यक है और इस संबंध में घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां प्रकटन विवरण के माध्यम से मंगाई गई थी, इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि यह निर्णय घरेलू उद्योग को उसके हितों की रक्षा करने के लिए उसे कोई अवसर दिए बिना ही लिया गया है।

ट. 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन :

188. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने मुख्यतया घरेलू उद्योग के क्षति के दावों के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों को पुन: दोहराया है और घरेलू उद्योग के क्षति और कारणात्मक संबंधों के दावों और प्राधिकारी के विश्लेषण पर वही टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं । इसलिए हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है ।

(क) इंडियन प्लास्टिसाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और अन्य आयातक

- i. यह कि क्षति और आरोपित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस अविध के दौरान उसको हुए घाटे मुख्यत: दीर्घ अविध के लिए प्रोपलीन की अनुपलब्धता के कारण हुए थे जिसके परिणामस्वरूप उसे 212 दिनों का उत्पादन का घाटा हुआ था।
- ii. यह कि संयुक्त राज्य अमरीका में अपील न्यास ने हॉट-रोल्ड स्टील के मामले में यह निर्णय दिया है कि प्राधिकारी को समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग पर किसी भी अन्य कारक के प्रभाव से पाटत आयातों के प्रभाव को पृथक और विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में स्वत: ही इसका उल्लेख किया है कि उसे अन्य कारकों के कारण उत्पादन में घाटा हुआ था। तथापि, घरेलू उद्योग चतुराई जांच अवधि के दौरान निष्क्रिय समय का उल्लेख करने में विफल रहा है और उसने याचिका को उसको बेहतर ढंग से अनुकूल अपनी अवधारणाओं के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसलिए प्राधिकारी को पाटित आयातों के प्रभाव, यदि कोई है, के संबंध में निष्कर्ष देने से पूर्व उपयुक्त रूप से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और पाटित आयातों के क्षित के प्रभावों को उन ज्ञात अन्य कारणात्मक कारकों से पृथक रखना चाहिए।
- iii. यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी सामान्य अवधि की तलाश में थे क्योंकि जांच अवधि के आंकड़ों को प्रयुक्त करना अनुचित था जिससे कि बंद होने की बढ़ाई गई अवधि पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता था । यदि

बिक्रियों में संभावित गिरावट और अन्य संकेतकों को परिकलित किया जाना था तो यह अधिक उपयुक्त होता कि 2012/13 तक की क्षमता उपयोग को प्रयुक्त किया जाता ।

- iv. यह कि आफगा गेवर्ट ए जी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2001 (130) ई एल टी 741 के मामले में ट्रिब्युनल ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया है कि संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के हितों को घरेलू उद्योग के हितों के समान माना जाना चाहिए । देश के लिए प्रयोक्ताओं के हित महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए प्रयोक्ता उद्योग और आयातकों की भूमिकाओं को भी समान महत्व दिया जाए।
- V. यह कि डीजल एक मूल/प्रमुख सहायिती उत्पाद है जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पैट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करती है जोकि भारत में 80 प्रतिशत अपरिष्कृत रूप में आयातित किया जाता है। राष्ट्र के हित को सर्वोपिर मानते हुए यह अनिवार्य है कि 2 ईएच का आयात किया जाए क्योंकि यह 2-ईएचएन का विनिर्माण करने का एक कच्चा माल है जोकि सीटेन बूस्टर के रूप में डीजल के अनिवार्य अंतरभूत तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे कि भारत में डीजल की कमी को दूर किया जा सके। एपीएल भारत में 2-ईएच का एकमात्र उत्पादक है और यदि इसकी आपूर्ति में व्यवधान पड़ जाता है तो 2-ईएच के घरेलू प्रयोक्ताओं को अपने यूनिट बंद करने पड़ जाएंगे (क्योंकि इसका आयात करने में 7 से 8 सप्ताह तक का समय लग जाता है), क्योंकि 2-ईएच के घरेलू उपयोक्ताओं को कोई और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता नहीं होगा और 2-ईएच का आयात करना अनिवार्य होगा। इसलिए, इस जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ख) संबद्ध देशों के निर्यातकों और सरकारों की टिप्पणियां

189. इन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने संबंधित निवेदनों में क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में अपनी निम्नलिखित टिप्पणियां दी हैं :-

- i. यह कि प्रकटन विवरण यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि आर्थिक क्षति यदि कोई हुई है तो उसका कारण आरोपित पाटित आयात हैं।
- ii. यह कि पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों के कारण हुई क्षति की अनदेखी की गई है क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि 212 दिनों तक उत्पादन में घाटा होने के कारण भी कैसे आत्म क्षति नहीं हुई है जबिक ऐसी क्षति आयातों के कारण हुई है।
- iii. यह कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी कुछ "प्रचालनात्मक किठनाइयां" हैं, जिनके कारण जांच अविध के दौरान उसके कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका समाधन प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।
- iv. यह कि कच्चे माल के मुद्दों के कारण आत्मक्षति हुई है और प्रकटन में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि संयंत्र बंद होने के कारण याचिकादाता की लागत को कैसे परिकलित किया गया है।
- ए. यह िक कोई कीमत प्रभाव नहीं है क्योंिक कीमत कटौती नकारात्मक थी और पहुंच कीमत में लगभग 5000 रूपए/मी.ट. थीं जोिक घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए नहीं रोक सकती थीं । ऐसी अलाभप्रद कीमत का कारण कोई अन्य कारण होना चाहिए क्योंिक पहुंच कीमतें, घरेलू कीमतों की कभी भी प्रतिस्पर्धी नहीं थी ।
- vi. नकारात्मक कीमत कटौती होने के बावजूद याचिकादाता ने बिक्रियों की लागत में 20 प्रतिशत वृद्धि होने की प्रतिक्रियास्वरूप 8 प्रतिशत तक की अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है, जिसका तात्पर्य यह है कि याचिकादाता संबद्ध आयातों के कारण कीमत कटौती होने का दावा नहीं कर सकता है और उसे बिक्री कीमत में वृद्धि करने से रोका गया है।
- vii. यह कि आरोपित पाटित आयातों के कारण कीमत के न्यूनीकरण के निर्णय सिद्ध नहीं होते हैं क्योंकि याचिकादाता की बिक्रियों की लागत निर्धारित लागतों के अधिक समायोजन के कारण बड़ी है जोकि यह प्रतिबिंबित करती है कि उत्पादन कम मात्रा में था क्योंकि क्षमता का अनुकुलतम प्रयोग नहीं किया गया था।

- viii. यह कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि भारत में मांग और पूर्ति में व्याप्त अंतर को दूर करने के लिए ही हुई है । घरेलू उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने के कारण उत्पाद और बिक्रियां करने में असमर्थ था ।
- ix. यह कि यदि घरेलू उद्योग समग्र जांच अवधि के दौरान उत्पादनकर्ता बना रहता तो उस संबंध में प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के उत्पादन और बाजार के हिस्से के बारे में लगाए गए कुछ पूर्व अनुमान निराधार हैं।
- अक्षित से किसी प्रकार का पृथक्कीकरण करने के लिए सामान्य उत्पादन अविध पर विचार करना चाहिए था और न कि जांच अविध के लिए क्योंकि जांच अविध प्रितकूल रूप से प्रभावित थी। इसलिए, उत्पादन और बिक्री की मात्रा पर कीमत की कटौती का प्रभाव का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया गया है।
- **хі.** यह कि प्रकटन विवरण अनुमानित संख्याओं का परिकलन करने के लिए कार्य प्रणाली के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। विगत वर्षों के आकड़ों पर आधारित किसी भी प्रकार का भारित औसत अनुमान, वर्ष 2010-13 के बीच विद्यमान प्रवृतियों के कारण अनुचित है।
- Xii. यह कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में वृद्धि क्षति का मुख्य कारक है। कच्चे माल की अनुपलब्धता और उसके परिणामस्वरूप संयंत्र का बंद होना एक ऐसा कारक है जोकि अलग रखा गया है और यह कारणात्मक संबंध को तोड़ता है।
- xiii. यह कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो उनका भारतीय प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
- xiv. यह कि यदि कोई शुल्क लगाया जाता है तो वह भारतीय रूपए में होना चाहिए।

ट.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के अधिकतर निवेदन क्षति और कारणात्मक संबंधों के विश्लेषण करने के बारे में हैं और यह दोहराए गए हैं तथा ऐसे विचार वही हैं जोकि पहले व्यक्त किए गए हैं। तथापि, इन मुद्दों की जांच की गई है और इनका निदान निम्नानुसार है:
 - i. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में कि प्राधिकारी इस तथ्य को मानने में विफल रहे हैं कि आपूर्ति में व्यवधान होने जैसे कारकों के कारण आत्मक्षति हुई है जोिक पाटित आयातों से संबंधित नहीं है, इसिलए कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्लेषण से इस तथ्य का स्पष्ट पता चलता है कि जांच अविध के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जांच अविध के दौरान बढ़ी हुई अविध के दौरान प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान आने के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ था। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस कारक को इस अविध के दौरा याचिकादाता के निकृष्ट कार्य निष्पादन के कारकों में से एक कारक माना गया है। जबिक इस वास्तविक स्थिति पर कोई असहमित नहीं है कि जांच से यह भी सिद्ध होता है कि आपूर्ति के बहाल हो जाने के बाद घरेलू उद्योग अत्यधिक मात्रा में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण अलाभप्रद कीमतों के कारण नियमित अथवा पूरे पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं रहा था। जांच से यह स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध देशों में ऐसे कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने जिन्होंने पहले संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए थे, घरेलू बाजार में ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए विशिष्ट ऋण शर्तों के साथ अत्यधिक मात्रा में पाटित आयात किए थे। इसी कारण से कीमत का अत्यधिक न्यूनीकरण हुआ है और याचिकादाता अपनी पूरी लागत को वसूल करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने में असमर्थ रहा है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि समग्र क्षति स्वत: हुई है, वैध नहीं है।
 - ii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिए हैं कि आरोपित पाटित आयातों के कारण कीमतों में न्यूनीकरण हुआ है, प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि याचिकादाता की बिक्रियों की लागत निर्धारित लागत का अत्यधिक समायोजन करने के कारण बढ़ी है जिससे यह प्रतिबिंबित होता है कि उत्पादन की मात्रा कम है क्योंकि क्षमता का अनुकूलतम रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने संयंत्र के निष्क्रिय समय के कारण अत्यधिक निर्धारित लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए सामान्य उत्पादन चक्र का अनुमान लगाते हुए घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत की जांच की है और यहां तक कि इस सामान्य लागत के अनुसार कीमत को

न्यूनीकरण पाया गया है क्योंकि याचिकादाता ने बाजार का अत्यधिक हिस्सा गंवा दिया था। पहला इस कारण से कि उसे कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हुई थी, दूसरा इसलिए कि उसे अत्यधिक पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण सामान्य उत्पादन को बहाल करने में वह असमर्थ था। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं।

- iii. पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग की क्षित का मूल्यांकन जांच अविध में उसके विद्यमान होने के प्रसंग में किया जाता है और निक आदर्श अविध के आधार पर। विगत वर्षों के लिए आंकड़ों के विश्लेषण को प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और निक आदर्श अविध को देखने के लिए जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है। जबिक, कच्चे माल के मुद्दों सहित अनेक अन्य कारकों द्वारा घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकता है, जैसा कि इस मामले में स्थिति है, घरेलू उद्योग को क्षिति होने के कारणों में एक कारण पाटन भी माना जा सकता है और उसे पाटन के कारण इतनी क्षिति हुई है, उससे उतना संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। क्षितिरहित कीमत का नियामन, पाटन से भिन्न कारणों के कारण संयंत्र के बंद होने जैसे कारणों से उद्योग को हुई आंतरिक क्षित के कारकों द्वारा स्वत: क्षित होना सुनिश्चित होता है और इसके लिए पाटन को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- iv. क्षमता उपयोग, कच्चे माल की लागत, प्रयोज्यता लागत आदि के लिए जांच अवधि तथा विगत तीन वर्षों के अनुकूलतम आंकड़ों के आधार पर क्षतिरहित कीमत का आकलन किया गया है । एनआईपी के नियम का अनुसरण करते हुए लागत को अनुकूलतम बनाया गया है और इसका निष्क्रिय क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के यह तर्क कि पाटित आयातों के कारण आत्मक्षति हुई है, का कोई महत्व नहीं है।
- ए. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने यह मानते हुए कि याचिकादाता के वास्तविक और कार्य निष्पादन की जांच की है कि उन 212 दिनों के लिए उसका संयंत्र प्रचालन में था, जिस अविध में कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान पड़ने के कारण संयंत्र बंद पड़ा हुआ था। जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, सकारात्मक प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच अविध के दौरान जब कोई ऐसा व्यवधान नहीं था यह उत्पादन पर आधारित था। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के यह तर्क कि प्राधिकारी आत्म क्षति और कारणात्मक संबंध का निदान करने में विफल रहा है, निराधार है और किसी भी तरह से इन पक्षकारों के हितों के साथ समझौता नहीं किया गया है।
- vi. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि यह निर्णय करने के पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है और ऐसी क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयात होने तथा कुछ बाधित दशाओं के कारण उसके एकमात्र आपूर्तिकर्ता से कच्चे माल की आपूर्ति करने में व्यवधान होने के कारण हुई है। तद्नुसार, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों का निदान किया गया है।
- vii. आयातकों के इन तर्कों के बारे में कि शुल्क रूपए में लगाए जाने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुसंगत पद्धित के अनुसार शुल्कों का मूल्यांकन संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलरों के रूप में किया जाता है क्योंकि अधिकतर आयात इसी मद्रा में मूल्यांकित होते हैं। इन पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई विशेष तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस मामले में ऐसे शुल्क को भारतीय रूपए में मूल्यांकित किया जाए। इसलिए प्राधिकारी को ऐसे निवेदन का कोई अर्थ महसूस नहीं होता है।

ट. निष्कर्ष

- 191. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दे और किए गए अनुरोधों और इस प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये तथ्यों जिसे इस जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया है की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :
 - (i) संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई, मलेशिया और इण्डोनेशिया से उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयी है और इन देशों से पाटित आयातों का पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और सामान्य से अधिक है।
 - (ii) सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन सामान्य पाया गया है और इसलिए उस देश के विरुद्ध जांच को छोड़ दिया गया है।

- (iii) घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि हुई है और
- (iv) अत्यधिक हानि जांच की अवधि के एक बड़े भाग के दौरान कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा के साथ साथ उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों से पाटित आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभावों के कारण हुई है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

192. जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है प्रयोक्ता उद्योग ने इस देश में मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता तथा इसके प्रमुख कच्चे माल के लिए आपूर्ति के एक मात्र स्रोत पर निर्भरता के कारण इसकी संभाव्यता के संबंध में चिंता प्रकट की है। यह भी तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तु कुछ प्रकार के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत में एक मात्र घरेलू उत्पादक से आपूर्ति में रुकावट के कारण उनके प्रचालन और डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि एक उचित बाजार वातावरण में घरेलू उत्पादक का अस्तित्व और उसका बना रहना कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए इस उत्पाद के महत्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है। पाटन रोधी उपायों को लगाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयात पर रोक नहीं लगेगी और इस कारण से उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रयोक्ता उद्योग के हितों पर इस उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने की स्थिति में बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड. सिफारिश

- 193. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच को पाटन रोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शुरू किया गया था और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षित और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था तािक पाटन और क्षित की सीमा और मात्रा का निर्धारण किया जा सके। निर्धारित कार्यविधि के अनुसार जांच करने के बाद तथा यह सिद्ध करने के बाद की संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से पाटन हुआ है और घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण पर्याप्त क्षित हुई है, प्राधिकारी इसे आवश्यक और उपयुक्त समझते हैं कि वह नीचे दिए गए रूप में और तरीके से संबद्ध देशों/ क्षेत्रों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करें।
- 194. अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम के संबंध में प्राधिकारी इस जांच परिणाम में इस प्रकार से निर्धारित क्षित के मार्जिन और पाटन के मार्जिन में से जो भी कम है उसके बराबर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तािक घरेलू उद्योग को होने वाली क्षिति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तािलका के कॉलम 8 में दर्शायी गई रािश के समतुल्य निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क संबद्ध देशों/ क्षेत्रों में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाले किसी अधिसूचना के द्वारा इसके लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों की अविध के लिए लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रस	उप शीर्षक अथवा शुल्क मद	वस् तुओं का विवरण	उत्पत्ति देश/ क्षेत्र	निर्यातक देश/ क्षेत्र	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीएच-29 29051620	2-इथाइल हेक्सानोल (2-EH)	मलेशिया	मलेशिया	बीएएसएफ पेट्रॉन्स केमिकल्स (बीपीसी)	बीएएसएफ पेट्रॉन्स केमिकल्स (बीपीसी)	53.63	मी. ट.	अम.डॉ.

			<u> </u>	1	T 6	Ι .		l	1
					एसडीएन	एसडीएन			
					बीएचडी,	बीएचडी,			
					मलेशिया	मलेशिया			
2	उपरोक्त	उपरोक्त	मेलेशिया	मलेशिया	उपयुक्त को छोड़ युग्म	कर कोई अन्य	107.30	मी. ट.	अम.डॉ.
3	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	107.30	मी. ट.	अम.डॉ.
4	उपरोक्त	उपरोक्त	कोरिया गण राज्य	कोरिया गण राज्य	मैसर्स एलजी केम कोरिया	1.मैसर्स हुंडेई कॉरपोरेशन, कोरिया 2. मैसर्स विनमार इंटरनेशनल, लिमि., यूएसए	-	मी. ट.	अम.डॉ.
5	उपरोक्त	उपरोक्त	कोरिया गण राज्य	कोई भी	उपयुक्त को छोड़ युग्म	,	15.55	मी. ट.	अम.डॉ.
6	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	कोरिया गण राज्य	कोई भी	कोई भी	15.55	मी. ट.	अम.डॉ.
7	उपरोक्त	उपरोक्त	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	मैसर्स ओक्सिया जीएमबीएच, जर्मनी	1. मैसर्स आईसीसी केमिकल कॉरपोरेशन यूएसए 2 मैसर्स पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजैडई, दुबेई 3. मैसर्स विनमार इंटरनेशनल यूएसए	45.47	मी. ट.	अम.डॉ.
8	उपरोक्त	उपरोक्त	यूरोपियन यूनियन	कोई भी	उपयुक्त को छोड़ युग्म	कर कोई अन्य	113.47	मी. ट.	अम.डॉ.
9	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	यूरोपीय यूनियन	कोई भी	कोई भी	113.47	मी. ट.	अम.डॉ.
10	उपरोक्त	उपरोक्त	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	मैसर्स पी. टी. पेट्रो ओक्सो नूसांतरा, इंडोनेशिया	1.मैसर्स पी. टी. पेट्रो ओक्सा नूसांतरा, इंडोनेशिया 2. मैसर्स	45.65	मी. ट.	अम.डॉ.

						सोलिटज एशिया प्रा. लि. सिंगापुर			
11	उपरोक्त	उपरोक्त	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	उपयुक्त को छोड् युग्म	कर कोई अन्य	127.82	मी. ट.	अम.डॉ.
12	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	127.82	मी. ट.	अम.डॉ.
13	उपरोक्त	उपरोक्त	यूएसए	कोई भी	कोई भी	कोई भी	29.61	मी. ट.	अम.डॉ.
14	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	यूएसएस	कोई भी	कोई भी	29.61	मी. ट.	अम.डॉ.
15	उपरोक्त	उपरोक्त	ताइवान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	42.45	मी. ट.	अम.डॉ.
16	उपरोक्त	उपरोक्त	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई अन्य	ताइवान	कोई भी	कोई भी	42.45	मी. ट.	अम.डॉ.

ढ. आगे की प्रक्रिया

- 195. केंद्र सरकार के इन आदेशों के विरुद्ध अपील जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न हो सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय प्राधिकार (सेसटेट) में की जायेगी।
- 196. प्राधिकारी इस अधिनियम और नियमावली के संगत प्रावधानों तथा समय समय पर इस संबंध में जारी की गई आम सूचना के अनुसार, समय समय पर इसमें की गई सिफारिश के अनुसार निश्चयात्मक उपाय जारी रखने, उसमें संशोधन अथवा उसे समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार की समीक्षा के लिए किसी प्रकार के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित समय सीमा के अनुसार दायर नहीं किया जाता है।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February 2016

FINAL FINDING

Sub: Anti-Dumping Investigation involving import of 2-Ethyl Hexanol (2-EH) from the European Union, the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, Malaysia, Kingdom of Saudi Arabia, Chinese Taipei & the United States of America.

- **F. No. 14/24/2014-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:
- 2. WHEREAS, The Andhra Petrochemicals Ltd. (hereinafter referred to as Petitioner), the sole domestic producer of 2-Ethyl Hexanol (hereinafter referred to as the subject goods) in India, has filed an application alleging dumping of the subject goods from the European Union (EU), the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, Malaysia, Kingdom of Saudi Arabia, Chinese Taipei & the United States of America (USA) (hereinafter referred to as the "subject countries/territories") and consequent injury being caused to them and requesting for initiation of an antidumping investigation against the above countries/territories.
- 3. AND WHEREAS, the Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice dated 20th November 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating this Anti-Dumping investigations concerning import of the subject goods, originating in or exported from the above countries, in accordance with the Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry, if any.

A. Procedure

- 4. Procedure described below has been followed with regard to this investigation.
 - I. In terms of sub-Rule 5 of Rule 5 the Authority notified the Embassies/representatives of the subject countries/territories in India about the receipt of the application from the domestic industry requesting for initiation of an antidumping investigation. The Govt. of the Republic of Korea was also informed, through its Embassy in India, about the receipt of the application in accordance with the provisions of Article 2.14 of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Korea RP.
 - II. The Embassies/representatives of the subject countries/territories in New Delhi were also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
- III. The Designated Authority sent copies of initiation notifications dated 20th November 2014 to the embassies/representatives of the subject countries/territories in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as well as the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter, were also sent to the Embassies of subject countries along with a list of known exporters/producers with a request to advise the exporters/producers from the subject countries/territories to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- IV. Copies of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry were made available to the known exporters and the Embassies/representatives of the subject countries/territories in accordance with Rules 6(3) supra.
- V. Exporters' Questionnaires were sent to the following known exporters from subject countries/territories in accordance with the rule 6(4) to elicit relevant information.
 - a) BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, Pahang, Malaysia
 - b) BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, Selangor, Malaysia
 - c) ZAK, Zak S.A UL, Poland

- d) EIF Atochem S.A, France
- e) Solvents Documentation Syntheses S.A, France
- f) Exxonmobil Chemical Holland BV, Rotterdam
- g) BASF, Wohlestrasse, Germany
- h) Saudi Basic Industries Corporation, (SABIC), Saudi Arabia
- Perstorp Oxo AB, Sweden
- LG Chemicals, Korea
- k) Arkema, France
- 1) Pt Petro Oxo Nusantara, (PT PON), Indonesia
- m) Nan Ya Plastics Corporation, Taiwan
- n) Vinmar International Ltd., USA
- o) ICC Chemical Corporation, USA
- p) BASF, USA
- q) Dow Chemicals, USA
- r) Eastman Chemical Co. USA
- VI. The following producers/exporters, exporting the subject goods originating in or exported from the subject goods, have filed questionnaire responses:
 - (a) M/s PT Petro Oxo Nusantara, Indonesia (PT PON)
 - (b) M/s Sojitz Asia Pte Ltd, Singapore
 - (c) M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia, (SABIC)
 - (d) M/s Al-Jubail Fertilizer. Co Saudi Arabia (Albayroni)
 - (e) M/s Oxea GmbH, Germany (Oxea)
 - (f) M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai
 - (g) M/s BASF PETRONAS Chemicals Sdn Bhd, Malaysia (BPC)
 - (h) M/s Hyundai Corporation, Korea RP
 - (i) M/s LG Chem Ltd, Korea RP (LG Chem)
 - (j) M/s Vinmar International Ltd., USA
 - (k) M/s ICC Chemical Corporation, USA
- VII. Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4):
 - C J Shah & Co, Mumbai.
 Petrochem Middle East (India) P. Ltd., Mumbai.
 - KLJ Resources & Group of Cos, New Delhi.
 - 4. Deepak Nitrite Ltd., Mumbai
 - Lalitha Chem Industries Pvt. Ltd. Thane
 - 6. Petchem Products Guj, Mumbai
 - PCL Oil & Solvents Ltd. New Delhi

- 8. Agsar Paints Pvt. Ltd. Tuticorin
- 9. C A G Industries, Andhra Pradesh
- 10. C & E Limited, HARYANA
- 11. Indian Institute of Chemical Technology, Telangana
- 12. Kerox Chemicals Pvt. Ltd. Karnataka,
- 13. Raghunath Dye Chem Pvt. Ltd. KURNOOL
- 14. Salicylates & Chemicals Pvt. Ltd. Telangana
- 15. Ushodaya Paints, Andhra Pradesh

16.	Sannidhi Chemical Industries, Telangana	35.	Pasuparthy Polymers Pvt. Ltd., Andhra Pradesh
17.	Laxminarain Visambharnath, Uttar	36.	Rhino Resins Pvt. Ltd. Telangana
	Pradesh	37.	Spectra Coats, Nellore
18.	Meghaaarika International Pvt. Ltd. New Delhi	38.	Srivatsa Industries, Andhra Pradesh
19.	Nicholas Pigments & Inks, Kanpur	39.	Bansal Trading Company, New Delhi
20.	Nisha Dye Chem, Ahmdabad	40.	Naq lobal (India), Maharashtra
21.	Mody Enterprises, Maharashtra	41.	Maha Bhawani Chemicals, Rajasthan
22.	Industrial Products Mfg. Co. Maharashtra	42.	Neelam Aqua & Speciality Chem Pvt. Ltd., Rajasthan
23.	Associated Dyestuff Pvt. Ltd. Gujarat	43.	Meghmani Dyes And Intermediates Ltd., Ahmedabad
24.	Indocem (India) Pvt. Ltd. Gujarat	44.	Merck Limited, Maharashtra
25.	Shalimar Paints Ltd. West Bengal	45.	Troix Chemicals Pvt. Ltd.,
26.	Right Minerals Pvt. Ltd. West Bengal		Maharashtra
27.	Jagadamba Chemicals, West Bengal	46.	Jeevika Spakchem Pvt. Ltd.,
28.	Agarwal Sales Corporation West		Maharashtra
	Bengal	47.	Galaxy Surfactants Limited, Maharashtra
29.	Payal Polyplast Pvt. Ltd. New Delhi	48.	
30.	Rachna Plasticizers, Mumbai		Premier Enterprises, West Bengal
31.	Amar Industrial Services, Telangana	49.	R.K.Trading, Cuttack, Odisha
32.	Indian Additives Limited, Chennai	50.	Krishna Traders, Kolkata, West Bengal
33.	KLJ Plasticizers Ltd. (Unit 1 & 11), New Delhi	51.	Annex Chemicals, Kolkata, West Bengal
34.	Kasturi Resins And Synthetics, Vijayawada	52.	Indian Plasticizers Manufacturers Association, New Delhi
Follow	ing important/users of the subject goods have filed th	oir rospon	206.

VIII. Following importers/users of the subject goods have filed their responses:

- Indian Plastisizers Manufacturers Association
- M/s. KLJ Plasticizers Limited
- M/s. Rachana Plasticizers
- M/s. Payal Petrochem Pvt. Ltd
- Payal Polyplast Pvt. Ltd.
- M/s. Deepak Nitrite Ltd.
- M/s. Amar Industrial Services
- IX. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations;
- X. The Authority made available non-confidential versions of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- XI. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the petitioner, has been worked out, on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;
- XII. The confidentiality claims of various interested parties, in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which are by nature confidential or which have been provided on a confidential

basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, have been treated confidential.

*** in this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- XIII. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 13.08.2015. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of the investigations and written submissions after the public hearings have been addressed in this disclosure to the extent they are relevant and backed by evidence.
- XIV. In terms of Rule 16 of the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case through a disclosure statement issued on 8th February, 2016. The following parties have filed their comments on the disclosure statement and their comments have been considered to the extent they are relevant and not re-iteration of their earlier views on the subject:
 - a) M/s. TPM Consultants on behalf of the domestic industry
 - b) M/s. Lakhmikumaran and Sridharan on behalf of PT Petro Oxo Nusantara, Indonesia and Sojit Asia Pte. Ltd.; M/s Albayroni and SABIC, Saudi Arabia; M/s. Perstorp Oxo AB, Sweden
 - c) M/s. EPL on behalf of Oxea GmbH and Petrochem Middle East FZE
 - d) M/s. BASF Petronas Chemicals, Malaysia
 - e) M/s. VishvaDeep & Co. On behalf of Deeepak Nitrite Ltd
 - f) M/s. Athena Law Associates on behalf of Indian Plasticizers Manufacturers Association and M/s. KLJ Plasticizers; Payal Polyplast; Payal Petrochem; PCL Oil & Solvents; Lalitha Chem; Rachna Plasticizers
 - g) The European Commission; and
 - h) Directorate General of Foreign Trade, Government of Indonesia
- XV. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer as well as the responding exporters were carried out to the extent deemed necessary and feasible.
- XVI. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and has used "best information available" for the determinations to the extent required.
- XVII. Investigation was carried out for the period starting from April 2013- June 2014 (POI). However, the injury investigation covers the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.
- XVIII. Wherever conversion of transaction values in the countries/territories of exporters were warranted the relevant daily or weighted average exchange rates as reported by the cooperating exporters in their respective questionnaire responses have been adopted. However, for the purpose of other conversions to Indian Rupee weighted average exchange rate for the POI (April 2013- June 2014) has been adopted at Rs Rs60.77 = 1US\$ as per customs data for the said period.
 - XIX. On the request of the Authority the Central Govt. has extended the time period for completion of this investigation till 19th Feb 2016 in terms of Rule 17 of the Rules.

B. Product under consideration and 'Like Article'

- 5. The product under consideration in this investigation is "2-Ethyl Hexanol". 2-Ethyl Hexanol (abbreviated as '2-EH') is a basic organic chemical. It is a fatty alcohol, clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odour. 2-EH is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavours, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. Main application of 2-Ethyl Hexanol is as a feed stock in the manufacture of low volatility esters; the most important of it is Di-(2Ethyl hexyl) Phthalate (DOP or DEHP). The product under consideration is classified under Customs Tariff Heading No. 29051620. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- 6. The subject goods exported from subject countries/territories are identical to the goods produced by the domestic industry in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses. Consumers can use, and are using the two interchangeably. No argument has been made by any interested party about the product under consideration or the like article. Therefore, the

Authority holds that the imported goods and domestically produced subject goods are technically and commercially substitutable and hence treated as "like article" under the AD Rules.

C. Domestic Industry and Standing

7. The petition has been filed by The Andhra Petrochemicals Ltd. The Petitioner is the sole producer of the subject goods in India. Further, the petitioner has not imported the product under consideration, nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration. Therefore, the petitioner satisfies the requirements of "standing" under Rule 5 of the AD Rules and constitutes "Domestic Industry" in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. No argument has been made by any interested party regarding the stranding of the domestic industry.

D. Countries Named, Volume of Imports and de minimis limits

- 8. The investigation was initiated against alleged dumped imports from the European Union (EU), the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, Malaysia, Kingdom of Saudi Arabia, Chinese Taipei & the United States of America (USA). The product, i.e., 2-Ethyl Hexanol is classified under Chapter 29 of Customs Tariff at subheading no. 29051620. The domestic industry has contended that the major volume of imports of the subject goods takes place through Kandla Port. But there is significant data gap in the DGCI&S data on imports at Kandla port. The data obtained by them from Kandla port itself, for the injury investigation period, except 2010-11, far exceeds the import volumes reported in DGCI&S data. The domestic industry contends that apparently entire import transactions at Kandla Port have not been captured in DGCI&S data.
- 9. The data obtained from DGCI&S, Kandla Port Authorities and transaction data of the responding exporters have been examined in the light of the contentions of the domestic industry. It is noted that while significant volume of the subject goods have been imported through the Kandla Port, as per the responses of the responding exporters themselves, the transactions have not been clearly captured in DGCI&S data. Therefore, all these data have been reconciled to the extent possible for examination of volume of imports of the subject goods. The data used has also been placed in the public folder for the benefit of the interested parties.
- 10. Some of the interested parties, in their post disclosure submissions, have argued that the Authority should provide them soft copies of the impart data alongwith the reconciled statement and methodology adopted for identification of transactions. In this connection the Authority notes that entire data set used had been placed in the public folder and was available to the interested parties for their examination and comments. Therefore, these submissions of the parties are without any basis.
- 11. Volume of dumped imports from the subject countries, as per the above import data, is given in the table below. As per this data, share of imports from each of the subject countries/territories in total imports has been found to be above *de minimus* level.

Countries / Quantity (MT)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualized	Share in Import in POI
Subject Countrie	es	<u>I</u>			-1		
EU	10439	21427	17967	26248	39477	31582	28.91%
INDONESIA	0	0	3900	16386	29549	23639	21.64%
KOREA RP	171	0	2954	6413	6413	5130	4.70%
MALAYSIA	4748	8506	17441	21954	26691	21353	19.55%
SAUDI ARAB	13598	2602	12308	14208	17756	14205	13.00%
TAIWAN	0	0	3019	6499	6499	5199	4.76%
USA	1180	2039	0	4632	4632	3706	3.39%
Sub total	30137	34574	57588	96340	131017	104814	95.94%
Other Countries	3146	2491	2116	2384	5540	4432	4.06%
Total	33283	37065	59704	98724	136557	109246	100.00%

12. Imports from other countries are de minimus. Cumulative imports from the other countries is also less than 7% as imports from the subject countries account for about 96% of total imports during POI.

E Interested parties to this investigation

13. On the basis of questionnaire responses and other submissions filed by the responding producers/exporters and importers listed in sub para VI and sub para VIII in para-4 above, alongwith the Govt.s of the Countries named in this investigation and the domestic industry in India have been treated as interested parties to this investigation. No other party has contested this finding of the Authority. Therefore, the Authority confirms the above position.

F. Miscellaneous Submissions of the Interested Parties

14. The interested parties in their various submissions have raised certain issues regarding various aspects of the investigation, including dumping and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding dumping and injury determinations have been dealt in the respective sections in this finding, general procedural issues raised have been addressed hereunder.

F.1 Issues regarding Confidentiality claims

(a) Views of the other Interested Parties

- 15. The interested parties, in their various submissions, including their post disclosure submission, have *inter alia* raised the following issues with regard to the confidentiality claims of the domestic industry:
 - a) That soft copy of transaction-wise import data relied upon by the Petitioner, as obtained from DGCI&S, has not been provided to the interested parties as no confidentiality can be sought on this information;
 - b) That information on parameters in Performa IV A, such as, depreciation, interest expense, net fixed assets, working capital, capital employed, investments, net worth and capital investment for expansion has not been provided even in indexed form.
 - c) That normal value has been constructed even for market economy countries, and no evidence and figures for international price of the major raw materials for calculating normal value has been provided in the petition.
 - d) That indexed version of costing formats has not been provided.
 - e) That range of injury margin and the methodology used for determining non-injurious price has not been disclosed. Further, the Petitioner has not disclosed the rate of return adopted and the basis (whether gross fixed assets or net fixed assets). The Petitioner has also not disclosed the basis for considering cost of credit for 270 days in determining non-injurious price, even when it is not permitted in the law.
 - f) That Petitioner's plant was shut down for some part of the POI and also faced severe constraint with respect to non-availability of raw material. The Petitioner has not disclosed these intrinsic factors and how the expenses during the shut-down period were accounted for in determination of non-injurious price.
 - g) That effective submissions cannot be made in the absence of information relied up unless the same is provided to the interested parties.

(b) Views of the Domestic industry

16. The domestic industry, in its submissions, has refuted the arguments of the interested parties. The domestic industry has submitted that they have provided a meaningful summary of the information claimed confidential in indexed form to the extent possible. Further the domestic industry has submitted valid reasons for inability to provide such information on non-confidential basis have been provided. The domestic industry has also claimed that the exporters and importers have also resorted to excessive confidentiality, thus, incapacitating the domestic industry to render any constructive comments.

(c) Views of the Authority

- 17. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties to the extent feasible. Confidentiality of the information, which is by nature confidential or wherever such confidentiality is warranted due to business sensitivity, has been allowed as per the consistent practices of the Authority.
- 18. The Authority also notes that that import data relied upon has been placed in the public folder and is available for the comments of the interested parties. Therefore, the comments of the interested parties, in this regard, are not valid.

F.2 Other issues raised by the interested parties

19. M/s. Laxmikumaran and Sridharan, representing M/s. SABIC and Albayroni, Saudi Arabia, and M/s. PT PON, Indonesia; M/s. ELP, representing M/s. Oxea GmbH and M/s. Petrochem Middle East, Singapore; M/s. Vishwadeep and Company, representing Deepak Nintrite Ltd.; M/s. Athena Law Associates, representing Indian Plasticizers Manufacturers Associations and the importers; and other interested parties, including BASF Petronas, Malaysia,

Directorate General for Trade, European Commissions (EU), and Malaysian Ministry of International Trade & Industry (MITI), in their respective submissions, have *inter alia* made the following general arguments regarding initiation and various aspects of this investigation:

- That the Authority is required to satisfy itself that there is sufficient evidence with regard to dumping, injury and causal link to justify initiation in terms of Rule 5. The domestic industry has failed to fulfill the requirements of Rule 5 (1) and (2) concerning the tests of sufficiency, adequacy and accuracy of evidence as obligated by the Rules.
- That the initiation and subsequent investigation is illegal as it fails to comply with various provisions of the Act and the Rules as the domestic industry has failed to disclose certain vital facts such as their plant closure and non-availability of raw material.
- That the Initiation of the investigation does not meet the standards set out by Art. 12 of ADA and para. 6 of
 the Rules as the period of data collection has been extended beyond twelve months without giving any
 reasoning as to why the standard does not apply. As such extended POI should take into account particular
 circumstances.
- That without providing evidence of normal value in the subject countries the petitioner has constructed the normal values for all market economic countries, which is not permissible under the law. Further, the petitioner has not disclosed the details of the export price adjustment and evidence thereof.
- That the cost relating to plant shutdown, exorbitant credit cost and rate of return claimed by the petitioner makes the determination of non injurious price and injury margin doubtful.
- That the petition did not provide adequate information on injury and causal link. The injury, if any, suffered by the petitioner, is due to its intrinsic reasons and there is complete absence of causal link. Annual Report of 2013-14 clearly states that the petitioner's plant was shut down for a long period during the POI due to non availability of raw material. Therefore, the Authority should investigate whether material injury is caused by dumped imports or other reasons.

F.3 Issues raised by the domestic industry

- 20. The domestic industry has opposed the submissions made on behalf of the association and consumers and has contended that the role of association and consumers cannot merely be limited to filing of comments on the petition filed by the domestic industry. The Association and the consumers hold obligation to provide relevant information to the Authority. Therefore, it is evident that a number of importers and consumers are non cooperative with regard to the present investigations. Further, the association has not provided any information with regard to present investigations, barring filing of comments from the petition filed by the domestic industry.
- As regards the contention of other parties that the petition is not fully documented and substantiated, it is submitted that the DA is required to merely satisfy itself with regard to justification for initiation of investigation.

F.4 View of the Authority

- 22. The Authority has noted the general issues raised by the interested parties with regard to the accuracy and adequacy of the information submitted by the petitioner at the time of initiation and the injury claims in the petition.
- As far as the adequacy and accuracy of the information contained in the petition and examination by the authority is concerned, the authority notes that all the information with regard to import data, estimates of dumping and injury margins and injury information were duly examined on the basis on *prima facie* evidence submitted by the petitioner as was reasonably available with the petitioner and after being satisfied that there is a *prima facie* case of dumping, injury and causal link, requiring further investigation, the Authority initiated this investigation. The information available at the time of initiation may not be ideal or complete all respect. What is important at the stage of initiation is that the information provided should be sufficient as prima facie evidence as to existence of dumping, injury and causal link. Anti dumping investigations involve a continuous process of data collection and verification till the final determinations are made. Therefore, the issues raised by the interested parties with regard to inconsistencies and inadequacies in the data, if any, have been addressed based on the data received from various interested parties during the course of this investigation. As far as the arguments that the POI has been extended beyond 12 months without any adequate reasons the Authority notes that there is no mandatory requirement to restrict the POI to 12 months only. In the factual matrix of the case the data collection period is decided by the Authority keeping the period closer to the initiation. Therefore, the arguments of the opposing interested parties are not valid.
- 24. As regards the arguments of the interested parties that the petitioner failed to provide vital information regarding production loss and plant shutdown during the POI and attributed the entire injury to the dumped imports the Authority notes that the petition contained detailed information about loss of production in POI with reasons. The

petitioner also mentioned in the said petition that they have excluded the idle time cost from the total cost incurred for working out injury margins. Therefore, the arguments of the interested parties are not valid.

- 25. As regards the issues raised by the interested parties regarding the transaction-wise imports data, the Authority notes that the transaction-wise import data relied upon was placed in the public file and was made available to the interested parties.
- As far as the dumping determination is concerned, the Authority notes that the questionnaire response received from the participating exporters from the subject countries have vindicated the claims of the domestic industry about the dumping. However, for the purpose of final determinations data received from the exporters in their questionnaire responses have been used and therefore, the interest of the exporters and importers have not been compromised in any manner because of lack of complete information in the petition with regard to various adjustments etc.
- As regards the objections raised by the domestic industry regarding the role of the associations and users in this investigation are concerned, the Authority notes that these parties have filed their comments on various aspects of the investigation without filing any questionnaire response. However, it is also noted that no questionnaire format has been prescribed for such parties to provide any specific information. Therefore, the information and comments filed by these parties have been considered to the extent they are relevant and backed by evidence.
- 28. The interested parties, including the Government of Indonesia and the European Commission, in their post disclosure comments, have mostly re-iterated their respective stands on the above issues. The issues raised by the interested parties with regard to the claim of injury and injury margins have been dealt in a respective section in this finding and for the sake of brevity the same is not being repeated here.

G. Determination of Dumping

- 29. The Authority notes that the following producers and exporters of the subject goods in the subject countries/territories have submitted Exporter's Questionnaire Response to the initiation of anti-dumping investigations:
 - (a) M/s PT. Petro Oxo Nusantara, Indonesia (PT PON)
 - (b) M/s Sojitz Asia Pte Ltd, Singapore (Sojitz)
 - (c) M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)
 - (d) M/s Al-Jubail Fertilizer.Co, Saudi Arabia (Albayroni)
 - (e) M/s Oxea GmbH, Germany (Oxea)
 - (f) M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai
 - (g) M/s BASF PETRONAS Chemicals Sdn Bhd, Malaysia (BPC)
 - (h) M/s Hyundai Corporation, Korea RP
 - (i) M/s LG Chem Ltd, Korea RP (LG Chem)
 - (j) M/s Vinmar International Ltd., USA
 - (k) M/s ICC Chemical Corporation, USA
- 30. The responding exporters and other interested parties, in their various submissions, have argued that the domestic industry, in its petition, has failed to provide adequate and accurate information/evidence with regard to the degree and extent of dumping. It has been further argued that given the fact that the petitioner's plant was shut down for nearly 50% of the year the costs and conversion factors of the petitioner should not be accepted by the Authority to determine dumping margin as it is not in line with the requirements to conduct fair comparison.
- 31. It has been further argued that since the exporters from subject countries are fully participating and have filed their questionnaire responses, normal values and export prices should be determined based on the data submitted by them in terms of Section 9A (6A) of the Customs Tariff Act 1975 which provides that margin of dumping in relation to a producer or exporter shall be based on the records maintained by such producer or exporter.
- 32. The Authority notes that at the time of initiation the domestic industry had provided *prima facie* evidence of dumping based on information reasonably available to it and having satisfied itself about the existence of dumping form the subject countries/territories the Authority initiated the investigation. As regards the acceptance of the petitioner's cost for determination of Normal value is concerned, the Authority has noted the fact that costs of the domestic industry was affected by plant closure and therefore, actual costs have not been accepted for any determination. The costs have been normated with appropriate level of production.
- 33. The Authority further notes that since the responding producers and exporters have filed questionnaire responses the same have been used for determination of dumping margins to the extent the responses are complete and duly documented. For non-cooperating exporters and countries not responding to the initiation, to the extent possible

the data of the cooperating exporters have been used as best facts available for determination of various elements dumping margins thereby eliminating the possible distortion due to construction of normal values as argued by the responding exporters.

34. The questionnaire responses of the above producers and exporters were examined and supplementary information and clarifications were sought from them based on preliminary examination of the same. The information and data submitted by the responding exporters have been verified to the extent possible and verified data has been used for determination of dumping margins as follow:

G.1 European Union

35. As per the import data 39477 MTs of the subject goods have been imported from the European Union. Only one producing exporter from the European Union, i.e., M/s Oxea GmbH, has filed questionnaire response.

(a) M/s Oxea GmbH, European Union

- 36. M/s Oxea GmbH, Germany (Oxea), whose parent company is the Oman Oil Company S.A.O.C, Muscat, has filed a questionnaire response as the producer of the subject goods in the European Union. The Company produces Oxo-alcohols from Propylene and Syn gas. Propylene is procured from the merchant market through global contracts linked to Global Naphtha/Crude Price. The other building block for production of Oxo alcohols, i.e., Syn gas, is sourced externally from M/s [***], whose plant is located inside the factory premises of Oxea under a long term agreement.
- 37. Oxea sells the subject goods in the domestic market in Germany and other countries in the European Union which is a single European market and also exports to various countries outside the Union, including India. During the POI Oxea has exported the goods to India through three intermediary companies i.e., M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai, M/s ICC Chemical Corporation, USA; and M/s Vinmar International, USA. M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai functions as a distributor and M/s ICC Chemical Corporation, USA; and M/s Vinmar International, USA function as resellers. All these entities have filed their respective questionnaire responses. Supplementary information were sought from Oxea and its distributors/resellers wherever required and the same has been provided. The data submitted by Oxea GmbH was verified through an on-spot investigation at their plant and office in Germany to the extent possible. Due to constraints of time data submitted by the distributors/resellers could not be verified. However, for the purpose of this determination the verified data of Oxea and questionnaire responses filed by the distributor/resellers as above have been considered to the extent they are reconciled with the data filed by Oxea.

Normal Value: Oxea

- 38. Oxea has provided its domestic sales details in Appendix 1 for determination of its Normal value in the European Union. As per App-1, during the POI Oxea has sold [***] MTs of the subject goods in the European Union. Only [***] MT have been sold in drums and rest have been sold in bulk form. The exports to India are only in bulk. Therefore, for the purpose of fair comparison only the bulk sales in the domestic market have been considered.
- 39. The goods have been sold to various unrelated customers in various countries on FOB/FCA/CPT/DDP terms with various credit periods. Accordingly, Oxea has indicated applicable adjustments to the domestic sales to arrive at ex-works selling price in the domestic market. On the basis of verified cost to make and sale as reported in appendix 8 additional information was called for and the cost of production of the subject goods in bulk form has been determined as [Ero***/MT). Oxea has disputed the computation of the cost and has argued that the cost should have been determined on the basis of the cost maintained by the Company as per German GAAP. It has been argued that the adjustments reported by them are explicitly provided in German GAAP and confirmed by the authorised public accountant. Therefore, the Authority should not have rejected the cost as maintained by the Company as per the German GAAP without providing the reason of the same in the verification report. The Authority should re-calculate the Normal value taking into account the cost as maintained by them.
- 40. In this connection the Authority notes that the cost of production has been determined after taking into consideration various elements of cost as per the records of the Company as verified. However, certain negative figures i.e., sales related income and assets related income, included in 'other expenditures' have been removed as they resulted into reduction of expenditure and does not reflect the actual cost as the same principles is also followed to determine the NIP of the domestic Industry.
- 41. The domestic sales transactions have been subjected to ordinary course of trade test for determination of normal value. [***%] of the domestic sales were found to be profitable. Therefore, for the purpose of determination of normal value only profitable sales have been considered. Oxea has claimed adjustments towards inland freight and insurance wherever applicable as actual. The Company has also claimed an adjustment towards handling expenses @ Euro [***] /MT based on certain notional calculations. However, these claims are mostly towards order processing expenses and only a part of it is directly related to material handling expenses ex-works i.e., pumping and pipeline cost

for the goods transported though the river jetty. The company has claimed that this notional adjustment should be made for all transactions, including export transactions, uniformly. The Authority notes that the expenses towards order processing are not valid claims for adjustment to arrive at ex-works prices for determination of Normal value. Since the intra-EU domestic sales as well as export sales are mostly from the river jetty all comparisons are proposed to be carried out at the jetty level and therefore, expenses towards the pumping and pipelines maintenance are not relevant and therefore, have not been adjusted.

42. Apart from these Oxea has also claimed adjustments towards the post supply credit cost on domestic sales as they involved varying credit periods. The credit expenses computed on the basis of the LIBOR+ spread applicable during the POI has been applied for such adjustment to arrive at the ex-jetty prices for the purpose of fair comparison. Accordingly, ex-jetty Normal Value of Oxea has been determined as follows:

Row Labels	Sum of Quantity (MT)	Total Invoice Value (Euro)	Total adjustments (Euro)	Sum of Net Value (Euro)	Sum of Net Value (USD)	Normal Value US\$/MT
Total Bulk Sales	***	***	***	***	***	***
Profitable sales	***	***	***	***	***	***

Export Price: Oxea through M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai, M/s ICC Chemical Corporation, USA; and M/s Vinmar International Ltd., USA

- 43. Oxea had exported [***] MTs of the subject goods to India through three unrelated distributors/resellers i.e., M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai, M/s ICC Chemical Corporation, USA; and M/s Vinmar International, USA. All these entities have filed their respective questionnaire responses. Only one product type i.e., 50020050-2-ETHYLHEXANOL (in Bulk) has been exported to India during the POI. All the transactions are in FOB term. The payments have been realised against LC/TT with varying credit periods ranging from 60 to 90 days to the distributor/resellers. The distributor/resellers have resold the goods to the customers in India with similar terms.
- 44. The expenses towards internal transport and insurance have been provided and verified to work out ex-works prices. The exports have been from the river jetty alongside the plant. Since the intra-EU domestic sales are also from the jetty all comparisons have been made at the jetty level and therefore, no adjustment has been made towards pipeline maintenance and pumping cost.
- 45. Oxea has negotiated the LCs and realised the TT payments after varying credit period. The credit cost has been computed based on the number of days of credit and LIBOR+ Spread applicable during the period of investigation to adjust the export sales prices. In addition to the above the bank expenses incurred for negotiation of the LCs have also been adjusted to arrive at net export price at the jetty level. Accordingly, ex-jetty export price of Oxea has been determined as follows:

Row Labels	Sum of Quantity	Sum of Net Invoice Value (Euro)	Sum of Total adjustments in Euro	Sum of Net Value Realised Euro	Sum of Net Value in USD	Net EP US\$/MT
50020050-2- ETHYLHEXANOL	***	***	***	***	***	***
ICC CHEMICAL CORPORATION	***	***	***	***	***	***
Petrochem Middle East Fze.	***	***	***	***	***	***
Vinmar International Ltd	***	***	***	***	***	***
Grand Total	***	***	***	***	***	***

Dumping Margin: Oxea

46. The Normal Value, so determined has been compared with the net export price at the same level to arrive at the dumping margins as follows:

Row Labels	Sum of Quantity	Net EP US\$/MT	NV US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
ICC CHEMICAL CORPORATION	***	***	***	***		
Petrochem Middle East Fze.	***	***	***	***		
Vinmar International Ltd	***	***	***	***		
Grand Total	***	***	***	***	***%	25-35%

(b) All other Producer and Exporters from the European Union

47. For all other non-cooperating producers and exporters in the European Union the Normal value, export price and dumping margin have been determined on facts available basis taking into account the data of the cooperating exporter as follows:

Producer	Exporter	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Any	Any	***	***	***	***	30-40%

G.2 Malaysia

48. As per the import data 26691MTs of the subject goods were imported from Malaysia during the POI. Only one exporter of the subject goods in Malaysia, i.e., M/s BASF, Petronas Chemicals Sdn Bhd., has submitted questionnaire response as the producer and exporter of the subject goods from Malaysia.

(a) BASF PETRONS Chemicals Sdn Bhd, Malaysia (BPC) – Producer & Exporter

- BASF PETRONS Chemicals Sdn Bhd, Malaysia (BPC) is a Malaysian based joint venture between BASF SE, Germany and Petroliam National Berhad (PETRONAS), Malaysia, under its subsidiary PETRONAS Chemicals Group (PCG). BPC produces the subject goods from Natural Gas and Propylene. Major part of the Propylene is procured from Petronas, Malaysia through pipeline under long term pricing arrangement based on a formula which includes a combination of the US Gulf CFR contract price, European CFR Contract Price, and South East Asia CFR Spot Price with freight adjustments on contract term and the rates are revised from time to time. Company also procures Propylene from Mitsui & Co. Ltd. under similar terms. Natural Gas is also procured from Petronas at Govt. Regulated Price applicable to various sectors. Both the raw materials are received through pipeline and directly charged to the reactor.
- 50. BPC sells the goods in the domestic market as well as in the export markets, including India directly. On the basis of the questionnaire response filed, BPC was asked to provide additional information, which was submitted. The data submitted by BPC was also verified through an on-spot investigation carried out in Malaysia to the extent necessary. Accordingly, normal value and export prices of BPC have been determined based on the verified data as follows:

Normal Value: BPC

- 51. BPC had sold [***] MTs of the subject goods in the domestic market during the POI against [***] transactions for a total value of US\$ [***]. All sales were directly to unaffiliated end users. Cost of productions of the producer was determined based on the verified cost data and additional information called for from the producer as US\$[***] / MT. The domestic sales transactions were subjected to ordinary course of trade test against the above verified cost of sales of the subject goods for determination of normal value.
- 52. In their post disclosure submissions the exporter has disputed the determination of the cost of sales and has also pointed out certain error in the determination and Ordinary Course of Trade test. The Authority notes that cost of sales have been determined taking into account all verified accounting data of the producer. However, the error in computation of the normal value has been rectified and it was found that [***] % of the domestic sales are found to be profitable sales and in the ordinary course of trade. Therefore, all profitable domestic sale transactions have been considered for determination of normal value for this producing exporter.

- 53. The goods were sold on delivered basis to unrelated domestic customers and the supplies were in tankers (Isotanks). The invoicing to the domestic customers was mostly on monthly basis and payment is received upto the end of the second month of the invoicing month. Therefore, no credit expense is involved. Only inland freight expenses and miscellaneous expenses including bank charges and packaging are involved in domestic transactions for adjustments to arrive at ex-works prices.
- Apart from these actual expenses the Company has also claimed level of trade adjustment to the domestic sales prices at the rate of [***] % of the invoice value on the grounds that the domestic sales are to direct end users whereas the export sales to India involve a commission of [***] % to BASF India which acts as their sales agent. However, it could not be substantiated as to how this affects the prices in the domestic market or export market and therefore, affects the price comparability. Therefore, this claim has not been accepted. Accordingly, the ex-works Normal Value of BPC has been determined as follows:

BASF	Sum of Quantity (MT)	Sum of Net Invoice Value	Sum of Total adjustments US\$	Sum of Net Value US\$	NV US\$/MT
All sales	***	***	***	***	***
Profitable sales	***	***	***	***	***

Export Price: BPC

- 55. During the POI the Company exported [***] MTs of the subject goods to unrelated customers in India against [***] transactions for a total value of US\$ [***]. The sales are directly to unaffiliated customers in India who buy in bulk. The transactions are negotiated by BASF India and in turn a commission of [***] % of the invoice value is paid to BASF India against each transaction. Export sales transactions were in CIF term. The goods are directly pumped to the ship through the pipeline and jetty maintained by the Port Authority for which a user fee is charged and included in the port authority charges. Adjustments towards ocean freight and other expenses such as port authority charges/pipeline charges, surveyor charges, customs clearance charges, shipping agent charges etc. reported collectively as Inland charges were verified from the documents as well as the system. The Company also incurs marine insurance, bank charges, and customs fees etc. which have been collectively reported as other expenses.
- 56. The export sales to India are either on LC or DA terms with credit period of 60 days for which adjustment has been made at KLIBOR + spread of 1.75%. Against certain transactions additional credit period up to 180 days have been extended by BPC on payment of interests @ LIBOR rates. Therefore, for the extended period of credit with interest no adjustment has been made to arrive at net export price at ex-works level. Accordingly, the net ex-works export price works out as follows:

Sum of Qty. MT	Sum of Net Invoice Value	Sum of Total Adjustments US\$	Net Value US\$	EP US\$/MT
***	***	***	***	***

Dumping Margin: BPC

57. The Normal Value so determined at the ex-works level has been compared with the net ex-works export price to arrive at the dumping margins as follows:

Producer	Exporter	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
BPC	BPC	***	***	***	***%	0-10%

(b) All other Producer and Exporters from Malaysia

58. For all other non-cooperating producers and exporters in Malaysia the normal value, export price and dumping margin have been determined on facts available basis taking into account the data of the cooperating exporter as follows:

Producer	Exporter	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	Range
Any	Any	***	***	***	***%	20-30%

G.3 South Korea

59. As per the import data 6413 MTs of the subject goods were imported from the Korea RP during the POI. Only M/s LG Chem, Korea has filed its questionnaire response as the producer of the subject goods in Korea.

(a) LG Chem Ltd., Korea RP

- 60. M/s LG Chem, Korea has submitted its questionnaire response as the producer of the subject goods in Korera exported to India through M/s Hyundai Corporation, Korea and M/s Vinmar International Ltd., USA, who have also filed separate questionnaire responses as the reseller of the subject goods.
- 61. LG Chem produces the subject goods from Normal butyl Aldehyde Bulk, which is produced from propylene, and Syn gas. LG has its own Naptha Cracker located in the same complex for production of Propylene which is transferred to the Oxo alcohol complex on cost basis for production of 2 EH/Butanol, Acrylic Acid and IPA. Naptha is procured from another oil company located nearby and also significant quantity is imported. The vacuum gas is also procured from the oil company located nearby. The data submitted by the Company along with one of its exporters, i.e., M/s Hyundai Corporation, were verified in an on-spot investigation to the extent feasible and the determination of normal value and export prices are based on the verified data.

Normal Value: LG Chem

- 62. LG Chem sells the subject goods in the domestic market and Normal value has been claimed based on sales in home market. During the POI LG Chem sold [***] MTs of the subject goods to unaffiliated direct end-users as well as distributors against [***] transactions. Domestic sales are both in bulk and packed in drums, drum packed goods being only [***] % of total sales. The exports to India are in Bulk only. Therefore, for fair comparison only bulk sales in the domestic market have been considered. The domestic sales were subjected to ordinary course of trade test against the verified cost to make and sale. Only [***%] of bulk sales in the domestic market were found to be profitable. Therefore, only profitable sales have been considered for determination of normal value. The Company has sold the goods in the domestic market directly to end users as well as distributors. The export sales to India are through resellers only. The quantity sold to distributors/resellers in the home market is significant. Since there is a significant price difference between the prices to the end users and resellers/distributors in the home market, for fair comparison prices to the distributors/resellers have been considered for determination of normal value as the export sales are also to resellers/distributors.
- 63. Domestic sales prices have been adjusted for all direct selling expenses such as transportation and packing expenses wherever applicable, and credit expenses to arrive at net ex-works prices for determination of normal value. Accordingly, Normal value for LG Chem has been determined on the basis of profitable sales to local distributor/resellers as follows:

Row Labels	Sum of Quantity MT	Sum of Net Invoice Value KRW	Sum of Ex factory KRW	Sum of Ex Factory US\$	Price US\$/MT
Total Bulk sales	***	***	***	***	***
Profitable sales	***	***	***	***	***
End User	***	***	***	***	***
Local	***	***	***	***	***
Distributor					

Export Price: LG Chem with M/s Vinmar International Ltd., USA and M/s Hyundai Corporation, Korea

- Ouring the POI LG Chem exported [***] MT of the subject goods to India for a total value of US\$ [***] against [***] Transactions. Out of these exports only [***] transaction involving [***] MT was sold through M/s Vinmar International, USA and rest of the quantity was sold through M/s Hyundai Corporation, Korea. LG has sold the goods to the respective traders/exporters on FOB term at port in Korea and all expenses upto the port have been incurred by LG Chem. The company has provided information on adjustments on account of Inspection Fee, Inland Freight, Handling Charges, Credit Expenses, Bank Charges, and Customs Agent Fee, wherever applicable. For the consignments directly pumped from the plant to the Port the Company has provided the cost of pumping which has also been taken into account for adjustment to the export price.
- 65. The Company has also claimed a positive adjustment towards Drawback received by it on exports based on total claims received and total exports made during the period. However, the Company could not provide the

supporting documents for the drawback claimed for the exports to India and the basis for such claim. Therefore, adjustment claimed for drawback received has not been admitted. Accordingly, net ex-works export price for LG Chem and its exporters works out as follows:

Channel of Sales	Sum of Quantity in Kg	Sum of Net Invoice Value KRW	Sum of Net Ex- works without admitting DBK KWN	Sum of Net Ex-works US\$	Net EP US\$/MT
AL2EHB	***	***	***	***	***
HYUNDAI CORPORATION	***	***	***	***	***
VINMAR	***	***	***	***	***
Grand Total	***	***	***	***	***

Dumping Margin: LG Chem with M/s Vinmar International Ltd, USA and M/s Hyundai Corporation, Korea

66. The Normal Value so determined at the ex-works level has been compared with the net ex-works export price to arrive at the dumping margins as follows:

Row Labels	Sum of Quantity in MT	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
AL2EHB	***	***	***	***		
HYUNDAI CORPORATION	***	***	***	***		
VINMAR	***	***	***	***		
Grand Total	***	***	***	***	***%	0-10%

(b) All other exporters in Korea RP

67. For all other non-cooperating producers and exporters in Korea RP the normal value, export price and dumping margin have been determined on facts available basis taking into account the data of the cooperating exporter as follows:

Producer	Exporter	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Any	Any	***	***	***	***%	10-20%

68. Neither LG Chem, nor any other interested party from Korea RP, has filed any comments to the disclosure statement and therefore, has not disputed the determination with respect to Korea RP. Therefore, the determination is confirmed.

G.4 Indonesia

69. As per the import data 25,763 MTs of the subject goods were imported from Indonesia during the POI. M/s P. T. Petro Oxo Nusantara (PON), one of the major producers and exporters of the subject goods in Indonesia, has filed questionnaire response. During the POI this producer has exported the subject goods directly to India and also through M/s Sojitz Asia Pte Ltd. Singapore. M/s Sojitz Asia Pte Ltd. Singapore has also filed questionnaire response as the exporter of the subject goods. Therefore, these two parties have been examined for determination of their dumping margin.

(a) PT. Petro Oxo Nusantara (PT PON)

70. M/s P. T. Petro Oxo Nusantara (PT PON), a public sector joint venture in Indonesia, is a major producer of the subject goods in Indonesia and supplies the goods to its related downstream producer in Indonesia and exports to various countries, including India. The major raw material i.e., Propylene is imported or/and indigenously purchased

from unrelated suppliers on contractual terms or on spot basis and imported through tanker ships. Natural Gas is procured from the Govt. owned Company as well a private source. The data submitted by PT PON and Sojitz Asia were verified in an on-spot investigation carried out in the premises to the extent possible and found necessary and determination of normal value and export price of this producer and its exporter have been determined based on the verified data as follows:

Normal Value: PT PON

- 71. PT PON sold [***] MT of the subject goods in the domestic market with a value of USD [***] against [***] transactions. The entire domestic sales of the Company during the POI are to two related companies in Indonesia i.e., M/s [***]; and M/s [***]. It has been submitted by the company that these two companies consume the subject goods for manufacture of other products such are plasticizers (Dioctyl Phthalate). It was pointed out that the related buyers consume the goods and are not re-selling the subject goods to any other company and therefore, the Normal Value cannot be determined on the basis of the re-sale prices of these related parties in the domestic market. Since the domestic sales are affected by relationship between the buyer and seller and there is no sales in the domestic market at arm's length third country export transactions of PT PON were also examined.
- 72. PT PON sold [***] MTs of the subject goods in third country markets [***] % of which was to China. Exports China are at very low prices and China, being a non-market economy, have not been considered as an appropriate third country for determination of normal value based on the prices to that market. Apart from China they have sold [***] MT of the subject goods to Australia during the POI. Though the percentage of sales to Australia is insignificant compared to the total third country exports of the Company, the volume is significant compared to the exports to India. Australia, being a market economy, the Authority proposed to adopt the third country exports to Australia for determination of the Normal value in terms of Sec 9 A (1) (c) of the Act.
- 73. PT PON, in its post disclosure submissions, has argued that their domestic sales should have been considered for determination of its normal value as no evidence on record suggests that PT PON's sales to its related company in the domestic market are not at arm's length. Alternatively, PT PON's cost of production should have been considered for determining its normal value as the same has been duly verified. It has been further argued that even if the Authority wishes to determine normal value based on PT PON's sales to a third country, its exports to China should be considered for such determination as the exports to China are above the cost of production. The Authority has incorrectly disregarded exports to China PR for determination of normal value. It has been argued that the exports to Australia are insignificant in comparison to its exports to China PR and therefore, do not provide a comparative representative price and would not pass the sufficiency test for determination of Normal Value as these sales are less than 5% of exports to India. It has also been argued that the exports to Australia are not in bulk form and therefore, not comparable to Indian sales.
- 74. PT PON has also submitted that it appears that the DA has not taken all export transactions to Australia while determining the Normal value. It appears that four transactions made to Marchem Australia Pty Ltd., which were actually consigned to Australia, have been inadvertently taken as exports to Singapore and China. If all these transactions are considered dumping margin for PT PON would be either *de minimis* or nil.
- 75. The Authority notes that the disclosure clearly mentioned that since the entire domestic sales of the subject goods of PT PON are to the related parties in Indonesia, who in turn consume the same for downstream production, there was no means available to determine the Normal value by constructing the same from re-sell price in Indonesia. There is no other domestic sale in Indonesia which could have offered any basis for such a determination. Authority further notes that Art 2.2 of the ADA provides an implied hierarchy for determination of Normal value in a situation where normal value cannot be determined on the basis of the domestic sales. Therefore, the first alternative, i.e., third country exports of the company needs to be explored first before considering the second alternative of construction of the normal value based on cost of production of the producer. Therefore, third country sales were examined for such determination as this producing exporter has significant third country exports. Overwhelming exports are to China, which operates under non-market economy conditions. Therefore, China could not have been adopted as the 'appropriate' third country for the purpose of determination on normal value as the selling price to that country is likely to be affected by non-market economy condition in that country.
- As regards the arguments of the exporter that the exports to Australia does not fulfil the sufficiency criteria the Authority notes that footnote 2 under Article 2.2 provides the flexibility and discretion to the Authority to accept a lower ratio where evidence demonstrate that such lower ratio are nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison. Therefore, considering the volume of exports to Australia the same has been considered sufficient to provide for a meaningful comparison and determination of normal value.
- 77. The Authority has also examined the submissions of the exporter that some transactions to Australia have been inadvertently excluded for determination of normal value. It is noted that the exporter provided the third country transactions alongwith the names of countries to which they were consigned/exported, which showed 8 transactions to

Australia. Post disclosure they have intimated that there were 4 more transactions to Australia against which the country of export was wrongly shown in their response as Singapore and China. They have now produced the invoices against these transactions at this late stage to prove that those transactions were to Australia. However, examination of these invoices indicates that though the country the freight components claimed against these transactions are unusually high compared to other transactions making the net prices much lower compared to the other transactions. There is no way in which these transactions and the claims for adjustment can be verified at this late stage. Therefore, the Authority is constrained not to accept these transactions for determination of the normal value for this producer/exporter at this stage.

- 78. PT PON has further argued that their exports to Australia are not in bulk and therefore, not comparable with the exports to India. However, examination of the invoices shows that these goods have been shipped in Iso-tanks and flexi-bags which are bulk form of sales, not in drums which are considered as packed goods. Therefore, the arguments of the exporter in this regard are not valid.
- 79. Accordingly, the third country sales transactions to Australia have been subjected to ordinary course of trade test with reference to the verified cost which has been determined as US\$[***]/MT. All such sales are found to be profitable. Therefore, all transactions have been considered for determination of normal value. Export sales are on CFR/CIF terms with credit period upto 90 days. All ex-works expenses towards ocean freight, insurance, jetty charges, surveyor fees and port handling charges and credit expenses have been adjusted to arrive at the ex-works Normal value as follows:

Third Country Export	Sum of Quantity (MT)	Sum of Net Value US\$	Price/ Normal Value US\$/MT
Australia	***	***	***

Export Price: PT PON with Sojitz Asia Pte Ltd (PON), Singapore as Exporter

- 80. During the POI, PT PON exported the subject goods through two sales channels i.e., (i) through unrelated trader, i.e., M/s Sojitz Asia Pte. Ltd., Singapore; and (ii) directly to unrelated Indian customers. M/s Sojitz Asia Pte. Ltd., a wholly-owned subsidiary of Sojitz, Japan, and a pure trading Company, has also filed a separate questionnaire response providing details of the goods exported by them to India during the POI. PT PON exported [***] MTs of the subject goods to India during the POI out of which [***] MTS were exported through Sojitz. Rest of the quantity has been exported directly. Sojitz Asia has a 100% subsidiary company in India Sojitz India Private Ltd. However, Sojitz India is not involved in sales of the subject goods to India. Sojitz Asia, Singapore exports the subject goods directly after purchasing the same from PT PON.
- 81. PT PON sells the goods to India, directly or through Sojitz, on CIF/CFR terms. The payment terms are TT with varying credit period upto 90 days. For sales through Sojitz, Sojitz raises separate invoice on Indian customer on CFR/CIF terms against LC with credit periods varying from 60 to 180 days.
- 82. The export sales to India are in bulk and PT PON has provided details of expenses towards (i) Ocean freight, (ii) Overseas insurance, (iii) Credit cost, (iv) Bank charges, (v) Surveyor fees, (vi) Jetty Charges and (vii) port handling, customs broker fee, etc. to arrive at ex-factory price. Accordingly, export price of PON has been determined as follows:

Product	Channel	Sum of Quantity (MT)	Sum of Net Invoice value in USD	Sum of Total Adjustments (Revised) US\$	Sum of Net Value US\$	EP US\$/MT
2EH	Direct	***	***	***	***	***
	SOJITZ ASIA PTE LTD	***	***	***	***	***
	Total	***	***	***	***	***

Dumping Margin: PT PON with Sojitz Asia Pte Ltd (PON), Singapore as Exporter

83. The Normal Value, so determined at the ex-works level, has been compared with the net ex-works export prices to India to arrive at the dumping margins as follows:

Channel	Sum of Quantity (MT)	EP US\$/MT	NV US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Direct	***	***	***			

SOJITZ ASIA PTE LTD	***	***	***			
Total	***	***	***	***	***%	0-10%

(b) All other producers and Exporters in Indonesia

84. For all other non-cooperating producers and exporters in Indonesia the normal value, export price and dumping margin have been determined on facts available basis taking into account the data of the cooperating exporter as follows:

Producer	Exporter	EP US\$/MT	NV US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Any	Any	****	****	****	****%	10-20%

G.5 Saudi Arabia

85. As per the import data 17,673 MTs of the subject goods were imported from Saudi Arabia during the POI. M/s Al Jubail Fertilizer.Co (Albayroni), Saudi Arabia has submitted questionnaire response as the producer of the subject goods in Saudi Arabia and exported to India through M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) during the POI. Both the Companies have filed their questionnaire responses.

(a) M/s Al-Jubail Fertilizer Co. (Albayroni), Saudi Arabia – (Producer) & M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia – (Exporter)

Normal Value: Albayroni

- 86. The responses filed by these two producer-exporters could not be verified through on-spot investigation. However, these responses were examined and additional information/clarifications were sought from the responding parties. The determinations of Normal value and export prices have been carried out on the basis of response filed by these parties.
- 87. Albayroni is the producer of the subject goods in Saudi Arabia. In its response Albayroni has informed that Propylene, one of the major raw materials in production of the subject goods, is purchased from their related company M/s. Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya") under a long term supply agreement under which Petrokemya has allowed Albayroni to use a portion of their Olefins manufacturing unit for production of Propylene for which Albayroni pays a part of the capital cost of the plant.
- 88. The Company has also informed that they do not sale of the subject goods in the domestic market in Saudi Arabia and the entire quantity produced is exported. Albayroni sells the entire production to SABIC and M/s Taiwan Fertilizer Company Ltd (TFC). TFC was earlier marketing 2EH in China. From 2013, SABIC is the sole marketer for 2EH products in world. Saudi Arabian Government owns 70% of the shares of SABIC. SABIC is only an exporter of the subject goods produced by Albayroni and is not involved in the production of the subject goods.
- 89. Section 9A (1) (c) provides that "normal value", in relation to an article, means.
 - (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory 2 to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):
- 90. Since there is no domestic sales the responding producer/exporter was asked to provide the transaction-wise details of its export sales to third countries for selection of an appropriate third country for determination of normal

value as per the second proviso of Section 9A (1) (c) quoted above. The transaction-wise data of exports to third countries, provided by the responding exporter, have been examined for selection of an appropriate third country. In the absence of any specific guideline in this regard, either in the Agreement or in the Rules, the principles of general economic conditions in the country of imports, state of product development in the said country and volume of imports, have been taken as the guiding criteria for selection of the appropriate third country. The largest volume of exports is to China which does not operate under market economy condition. The second highest export volume is to Pakistan with [***] MT exported during the POI. The volume of export is significant. Therefore, Pakistan has been selected as the appropriate third country and Albayroni /SABIC's export sales transactions to Pakistan has been considered for determination of Normal Value for this responding exporter from Saudi Arabia.

- 91. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that USA is a more appropriate third country for determination of normal value in case of Saudi Arabia. It is for the reason that the demand for PUC in Pakistan is far lower than the demand for PUC in USA. Since the demand itself it low, the prices prevailing in Pakistan would not reasonably reflect the price of the product. Further, whereas there are large number of consumers of PUC in USA, there are very limited number of consumers of PUC in Pakistan. Additionally there is a possibility of some kind of distortion in prices because of limited number of consumers in Pakistan. Therefore, the export price from Saudi Arabia to USA should be considered for determination of normal value in case of Saudi Arabia. The domestic industry has further submitted that the disclosure statement is completely silent on issues such as the valuation of propylene from related company, Arabia Petrochemical Company or Al-Bayroni.
- 92. On the other hand the producer/exporter, in their post disclosure submissions, have argued that since they have made substantial exports of the subject goods to China the Normal value for Albayroni should be determined on the basis of their third country exports to China. Notwithstanding the above, Albayroni's cost of production should have been considered for determination of their normal value as the same is easily verifiable and more credible. It has also been argued that while determining ex-factory prices to the third country certain adjustments needs to be applied as has been done for the exports to India.
- 93. As regards the arguments of the exporter that either their own cost of production should have been considered for determination of normal value or China should have been accepted as the appropriate third country the Authority notes that there is an implied hierarchy in Art 2.2 of the ADA and the first alternative needs to be explored before jumping to second alternative. Therefore, the first alternative i.e., third country sales were examined for such determination. In this connection the Authority notes that Saudi Arabia exports the subject goods to several countries, including Pakistan and USA. Highest volumes of exports are to China, which operates under non-market economy conditions. Therefore, China could not have been adopted as the 'appropriate' third country for the determination as the selling price to that country is likely to be affected by non-market economy condition in that country. Volume of exports to USA was lowest and there are significant exports to other market economy countries significantly higher than exports to USA. Therefore, Pakistan, which accounted for highest volume in market economy category, has been adopted as the appropriate third country and all applicable adjustments have been allowed to determine the normal value at ex-factory level. Hence no change in methodology is called for.
- 94. As far as cost Propylene and cost of production of Albayroni is concerned, the Authority notes that the cost of production of the product under consideration has been determined keeping in view all the elements of cost as per the consistent practices of the Authority.
- 95. The exports to Pakistan are in significant volumes and to Independent buyers. The sales are through SABIC on provisional basis. After exports are made SABIC repatriates the money to Albayroni as net back after accounting for all selling expenses and a marketing fee. Albayroni also incurs certain expenses towards inland freight and surveyor fees. The net back from SABIC is after the credit period indicated in the response. There is a significant variation in the price of subject goods sold by Albayroni to Pakistan as well as India from month to month. Therefore, for fair comparison monthly normal values have been determined after subjecting the third country sales to ordinary course of trade test with reference to the cost of production provided by the Company and after adjusting the inland freight cost, surveyor fee and credit cost incurred by Albayroni from the net back received from SABIC the normal value of the subject goods have been determined as follows:

Sum of Sales qty (MT)	Sum of Netback Value Paid to Albayroni (USD)	Sum of Realisation net of Credit	Price US\$/MT	Other Expenses of Albayroni	Weighted Average of monthly NVs US\$/MT
***	***	***	***	***	***

Export Price: Albayroni through SABIC

As per the information filed by the responding producer and exporter from Saudi Arabia, during the POI Albayroni exported [***] MT of the subject goods to India through SABIC. SABIC has a related company in India – SABIC India Pvt. Ltd., which gets commission for sales support as per agreement between SABIC and SABIC India. SABIC procures orders from Customers and directs Albayroni to effect delivery. Albayroni raises an invoice on SABIC at a provisional price. SABIC raises an invoice on the customer. Modifications to price, after sales, are adjusted through debit or credit notes on the customer. SABIC deducts a market fee and all delivery related expenses from the final price charged to the customer and the balance amount is paid to Albayroni. Negotiations are made with the customer on spot business and CIF basis. Adjustments for ocean freight, insurance, credit cost, bank charges and marketing fees have been made to see whether the net back paid by SABIC to Albayroni covers all expenses and reasonable profit. Albayroni receives the net back payment from SABIC after the credit period and also incurs certain expenses. Therefore, from the net back paid by SABIC to Albayroni the expanses of Albayroni, i.e., Inland transport and Surveyor fee as well as the credit cost of SABIC has been deducted to arrive at the net ex-factory price.

97. Because of significant variation in prices export prices have also been determined on monthly basis which work out as follows:

Values				
Sum of Quantity (MT)	Sum of Netback from SABIC(USD)	Sum of Total Expenses of Albayroni	Sum of Net Realisation by Albayroni	Weighted average of monthly EPs US\$/MT
***	***	***	***	***

Dumping Margin: Albayroni with SABIC

98. Net ex-works Normal Value determined has been compared with the net ex-works export price to determine the dumping margin for the above producer and exporter as follows:

Producer	Exporter	DM USD/MT	DM %	DM Range
Albayroni	SABIC	***	***%	De minimis

(b) All other producers and Exporters in Saudi Arabia

99. It is noted that Albayroni is the only producer of the subject goods in Saudi Arabia and goods have been exported through its related entity SABIC. Therefore, residual dumping margin for other exporters from Saudi Arabia has not been determined.

G.6 United States of America (USA)

100. The Authority notes that none of the producing exporter from the USA has filed any questionnaire response in this case. Two exporters/traders located in the USA, i.e., M/s Vinmar International Ltd. and M/s ICC Chemical Corporation, have filed their response with regard to their export of the subject goods from other countries as intermediate traders only. Therefore, no information has been provided by any interested party about the normal value or export price of the subject goods originating in or exported from USA. In the above circumstances the dumping margin for the USA is proposed to be determined on facts available basis.

Normal Value: USA

101. The producers/exporters in the USA have not provided any information on the domestic selling price or cost of production of the subject goods in the domestic market. The Authority notes that Annex II to Anti-dumping Agreement provides as follows:

"As soon as possible after the initiation of the investigation, the investigating authorities should specify in detail the information required from any interested party, and the manner in which that information should be structured by the interested party in its response. The authorities should also ensure that the party is aware that if information is not supplied within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry".

102. Therefore, the Authority proposes to consider facts available for determination of Normal value in the USA. In this connection the Authority notes that significant volume of the subject goods have been imported into the USA from Saudi Arabia during the POI and the weighted average sales price from Saudi Arabia to USA is available. Since the goods are expected to be entering the domestic market at those prices this information has been used as the best facts available for estimating the normal value in the USA. Accordingly, the Normal value in USA has been determined as follows:

Saudi Arabia to			
Volume in MT	Value US\$	Import Price US\$/MT	Normal value US\$/MT
***	***	***	***

Export Price: USA

103. Export price form USA has been determined based on the weighted average CIF price of imports as reported in DGCI&S data after adjusting the same for freight, insurance, handling expenses etc. on facts available basis to arrive at net ex-works price as follows:

Particular	Unit	POI
Import Volume	MT	4,632
Import Value	Rs./ Lacs	4,101
CIF Export Price	Rs./Kg	88.55
Ocean freight (128 US\$ per MT)	Rs./Kg	7.79
Marine Insurance @ 0.5%	Rs./Kg	0.44
FOB Price	Rs./Kg	80.31
Commission @3%	Rs./Kg	2.41
Bank charge @ 0.5%	Rs./Kg	0.40
Port expenses @0.5%	Rs./Kg	0.40
Handling charges @0.5%	Rs./Kg	0.40
Net export price	Rs./Kg	76.70
Exchange rate	INR/US\$	60.77
Net export price	US\$/Kg	1.262

Dumping Margin: USA

104. Net ex-works Normal Value determined has been compared with the ex-works export price to determine the dumping margin for all producer and exporter in the USA as follows:

Producer	Exporter	Normal Value US\$/MT	Export Price US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Any	Any	***	1262.13	***	***%	15-25%

105. No comment has been received from any interested party regarding the methodology adopted for determination of dumping margin as above. Therefore, Authority confirms the above determination.

G.7 Chinese Taipei

106. The Authority has not received any questionnaire response from any producer/exporter of the subject goods in the Chinese Taipei. In the above circumstances the dumping margin for Chinese Taipei is proposed to be determined on facts available basis.

Normal Value: Chinese Taipei

107. In the absence of cooperation from any producer/exporter from Chinese Taipei or publicly available information/evidence of price of subject goods in the domestic market in that country the Normal Value in that country

is proposed to be determined based on provision of Annex II of the Agreement quoted above. The Authority tried to access the customs data of the subject country to analyse its exports or imports of the subject goods to/from other countries for determination of Normal Value based on third country export/import prices. However, since the harmonised tariff head for the product is not dedicated authentic information has not been available for such a determination. Under these circumstances the options available with the Authority is either to construct the normal value in Chinese Taipei based on the information on cost and prices provided by the domestic industry plus a reasonable price or on the basis of other best facts available. The Authority notes that one of the producer and exporter of the subject goods in East Asia, i.e., Korea, has filed a complete questionnaire response, including its domestic selling prices. This information has been adopted as the best facts available for determination of normal value in Chinese Taipei. Accordingly, normal value in Chinese Taipei at ex-works level has been determined as US\$[***] per MT.

Export Price: Chinese Taipei

108. Export price form Chinese Taipei has been determined based on the weighted average CIF price of imports as reported in DGCI&S data after adjusting the same for freight, insurance, handling expenses etc. on facts available basis to arrive at net ex-works price as follows:

Particular	Unit	POI
Import Volume	MT	6,499
Import Value	Rs Lacs	6,149
CIF Export Price	Rs/Kg	94.61
Ocean freight (49 US\$ per MT)	Rs/Kg	2.98
Marine Insurance @ 0.5%	Rs/Kg	0.47
FOB Price	Rs/Kg	91.16
Commission @3%	Rs/Kg	2.73
Bank charge @ 0.5%	Rs/Kg	0.46
Port expenses @0.5%	Rs/Kg	0.46
Handling charges @0.5%	Rs/Kg	0.46
Net export price	Rs/Kg	87.06
Exchange rate	INR/US\$	60.77
Net export price	US\$/Kg	1.433

Dumping Margin: Chinese Taiepi

109. Net ex-works Normal Value determined has been compared with the ex-works export price to determine the dumping margin for all producers and exporters in Chinese Taipei as follows:

Producer	Exporter	Normal Value US\$/MT	Export Price US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
Any	Any	***	***	***	***%	5-15%

110. No comment has been received from any interested party regarding the methodology adopted for determination of dumping margin as above. Therefore, Authority confirms the above determination.

G.8 Dumping Margin Table: All Subject Countries

111. Based on the above examination the dumping margins for the cooperating producers/exporters and all others from the subject countries/territories have been determined as follows:

Producer	Exporter	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %	DM Range
European Uni	on					
Germany	ICC Chemicals Corporation	***	***	***		
	Petrochem Middle East Fze.	***	***	***		
	Vinmar International Ltd	***	***	***		
	Overall	***	***	***	***%	25-35%
EU All others	1					
Any	Any	***	***	***	***%	30-40%
Malaysia						
BPC	BPC	***	***	***	***%	0-10%
Malaysia All o	others	***				
Any			***	***	***%	20-30%
South Korea						
LG Chem	HYUNDAI CORPORATION	***	***	(***)		
LG Chem	VINMAR	***	***	***		
LG Chem	Overall	***	***	***	***%	0-10%
South Korea A	All Others					
Any	Any	***	***	***	***%	10-20%
Indonesia						
PT PON	Direct Sales	***	***	***		
	SOJITZ ASIA PTE LTD	***	***	***		
	Overall	***	***	***	***%	0-10%
Indonesia All o	others					
Any	Any	***	***	***	***%	10-20%
Saudi Arabia						
Al-Bayroni	SABIC	***	***	***	***%	De minimis
USA All Expo	rters					
Any	Any	***	***	***	***%	15-25%
Chinese Taipe	i All Exporters					
Any	Any	***	***	***	***%	5-15%

- 112. The dumping margins of the subject goods so determined are significant and above *de minimis* except for the goods originating in or exported from Saudi Arabia. The dumping margin of the goods exported from Saudi Arabia has been found to be *de minimis*. Therefore, the Authority drops the investigation against Saudi Arabia in terms of Rule 14 (b) of the Rules. Accordingly, further examination of injury and causal links have been carried out with respect to the rest of the countries/territories i.e., the European Union, USA, Malaysia, Indonesia, Korea RP and Chinese Taipei. Hereafter the term subject countries/territories shall refer to these countries/territories only.
- 113. In its post disclosure submissions the producer/exporter from Saudi Arabia have argued that since the dumping margin for the producers and exporters in Saudi Arabia has been found to be *de minimis* the investigation against Saudi Arabia should have been terminated by issue of a separate public notice without issuing a disclosure statement with regard to this. The Authority notes that the investigation could not have been terminated against one country without all interested parties, particularly the domestic industry, having been given an opportunity to comment upon it keeping in view the principles of natural justice.

H. Determination of Injury to the Domestic Industry

H.1 Cumulative assessment of Injury

- 114. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
- (b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 115. The domestic industry, in its submissions, has argued that exporters from more than one country are dumping the subject goods in the Indian market and margins of dumping from each of the subject countries/territories are more than the limits prescribed above. Quantum of imports from each of the above countries is more than the *de-minimis* limits. Therefore, cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries/territories directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.
- 116. The responding exporters have argued that apart from the condition of competition between the imported products and the domestic like product, the conditions of competition between the imported products *inter se* needs to be assessed to satisfy the provision of Annex II (iii) of AD Rules as has been the practice of the Authority. By virtue of the ASEAN-India FTA and India-Malaysia CEPA, the applicable customs duties are different for imports from Malaysia and Indonesia as compared to other target countries such as EU, USA, Korea, Taiwan and Saudi Arabia. This difference in tariff rates has led to a fundamentally different development of imports from the two sets of subject countries. The duty preference allowed imports from Malaysia and Indonesia to increase at a higher rate as compared to imports from EU, US, Korea, and Saudi Arabia. As a consequence, the share in imports from countries that are amenable to preferential duties has increased by 27% (from 16% to 43%), as compared to imports from countries that are not amenable to preferential duties which decreased significantly by the same amount i.e. 27% (from 84% to 57%).
- 117. It has been further argued that the EU and Saudi Arabia are additionally singled out by the fact that they are the only two subject countries/territories not benefitting from the FTA. Their import shares have decreased significantly over the period under investigation. Accordingly, cumulative assessment of imports from the EU with the other subject countries is not appropriate in the present investigation since the conditions of competition between subject countries are not comparable.
- 118. The domestic industry has submitted that there is no basis for the above argument. It has been argued that the Rules require three conditions to be specified and all are satisfied. Since the Designated Authority considers landed price of imports, cumulative assessment of import is appropriate despite different levels of customs duty. The consumers consider landed price of import and therefore, the applicable customs duty are applied. If the level of customs duty are different, the same does not imply that the imports are not competing *inter-se*. Petitioner also refers to the decision of the Supreme Court in the matter of Holder Topse which upheld the decision of the Designated Authority to determine different quantum of injury margin for the product falling under two different HS codes with two different customs duties
- 119. The Authority notes that this investigation has been initiated against alleged dumping of the subject goods from the European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Saudi Arabia, Chinese Taipei & the USA. Determination of the margins of dumping in the previous section indicates that the margins of dumping for the subject goods from each

of the countries mentioned herein above are more than the limits prescribed above, except the imports from Saudi Arabia where the dumping margin is *de minimis* and the investigation against this country has been dropped in terms of Rule 14 (b) of the Antidumping Rules. The volume of imports from each of the other subject countries is also more than the limits prescribed. The interested parties have raised the issue of differential duties against certain countries under FTAs leading to increased imports from those countries *vis-a-vis* other named countries in this investigation. The interested parties argue that this indicates that the imports are not competing *inter-se* and therefore, cumulative assessment of injury not appropriate in this case. The Authority notes that though the volume of imports from some of the countries enjoying preferential duties have increased the CIF price range and the landed values at which the goods are being imported from the subject countries indicates a clear *inter se* competition between the imports from these sources in the Indian market. Therefore, the arguments of the interested parties that there is no *inter se* completion between the imports from the subject countries/territories do not hold good.

120. The Authority also notes that the exports from the subject countries/territories are directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Domestic producer and exporters from the subject countries/territories sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both are being used by the consumers interchangeably. In view of the above position the Authority holds that cumulative assessment of the effects of imports is appropriate and accordingly, cumulative assessment of the effects of dumped imports from all dumped sources has been carried out to examine the injury and causal links.

H.2 Issues raised by the parties to the investigation

(a) Views of the other interested parties

- 121. The other interested parties, including the responding producers and exporters in the subject countries and territories; importers and user industry associations in Indian; and the Governments of some of the subject countries/territories, in their respective submissions have inter alia argued as follows:
- That even when there is a huge demand supply gap, the petitioner was closed for substantial time during the POI due to raw material supply issues and later the petitioner claimed injury on account of dumping which is untenable. Since the domestic industry was not in operation for reasons of raw material supply issues during the substantial part of POI, the users were left with no option but to import. Therefore, existence of material injury to the petitioner on account of alleged dumped imports during the POI when their plant was closed for minimum 212 days out of 455 days during the POI, on account of identified and admitted other reasons, needs to be substantiated:
- Domestic industry has provided an additional column in the proforma IVA related to POI under the heading performance 'if there is no idle time' without disclosing any methodology based on which such figures have been worked out by the petitioner. The petitioner has attempted to make up a case of 'ideal injury', thus, the petition suffers serious and irreparable infirmities. The claim of adjustment on account of loss of production has no legal or factual basis. The petitioner has not even elaborated on the detailed methodologies adopted;
- That the methodology for working out "if there is no idle time" column in Proforma IV A has not been disclosed. Further, the essence under AD act and rule is 'material injury' and not 'ideal injury'.
- That the credit rating agency ICRA has revised and lowered the credit rating of the applicant in November, 2013 in
 view of the expected weakening of APL's profitability and debt protection metrics during the current year owing to
 disruption in supply of its key raw material, Propylene. It further states that the outlook on long term rating
 continues to be negative on account of the uncertainty regarding timelines for resumption of stable supplies from
 HPCL;
- That there is no causal link between the alleged injury to the domestic industry and the imports of subject goods from subject countries in the present case making the entire investigation *ab initio* void and liable to be terminated immediately;
- That price undercutting of the imports are negative in respect of several countries implying lack of causal links. The injury margins are negative against most of the countries. Adjustment of credit costs claimed by the domestic industry is without any basis. The petitioner has fabricated the landed price and net sales realization to create positive price undercutting. The Authority should reject such baseless and self serving claims upfront.
- That demand of propylene, which is the major raw material for production of the subject goods, shows decreasing trend and will reach around 2% by FY 2016-17. It indicates that major Propylene manufacturers convert it to Polypropylene as they use Propylene in their captive consumption. It shows source of Raw Material 2-Ethyl Hexanol in India will be unavailable or less available so it is essential to import the 2-EH;
- Profitability to Polypropylene compare to 2-EH is higher by 100 USD/MT approx. 50%, which keep refiners interest more to manufacturing Polypropylene compared to manufacturing 2-EH;

- That HPCL is the only sole supplier of Propylene to APL. Propylene is in the gas form, it can be transported directly by pipeline. If either HPCL or APL plant is affected, it makes a question mark to availability of Raw Materials of Oxo-Alcohols(2-EH). Ideally at least there must be 2 or more supplier for Raw Materials for any organization. It makes a question mark to availability of Raw Materials of Oxo-Alcohols (2-EH). In case of HPCL intended to manufacture Polypropylene what other source APL has to cater the Indian Market of 2-EH? It will force all users of 2-EH to shut down their plants.
- That some of the consumers of the subject goods like Deepak Nitrite Limited manufacture Cetane Improver called 2- Ethylhexyl Nitrate(2-EHN) from 2-Ethyl Hexanol (2-EH), which is used by refineries in boosting Octane Number of Diesel. The customers of Cetane Improver are refineries in public sector undertakings like Indian Oil Corporation, BPCL, HPCL, and also in private sectors refineries like Reliance, Essar, HMEL and Shell. The supply contracts with customers are generally on fixed price term having penalty clause on monetary values, black listing and other legal consequences, in the event of delays or no supplies to these customers. Therefore, disruption of supplies by the domestic industry affect their production and commercial interests;
- That relevant extracts in the annual report 2013-14 of the petitioner clearly establish that the company operated at 110% of the designated capacity for a period of 1.5 months covering July August 2013 after HPCL's PRU commissioning post expansion. Therefore, claim of 39% capacity utilization during POI by the domestic industry is grossly incorrect;
- That the Petitioner has evidently not lost customers as it has operated at above 100% capacity utilization and had a production to sales ratio of close to or above 100% throughout the entire investigated period. Imports have merely taken up the portion of the market that the Petitioner could not supply to due to insufficient capacities;
- That the landed import price from subject countries has increased by 11.6% over the injury period, which is more than the increase in price by the Petitioner (8%) over the injury period;
- There is no injury to the applicant in terms of volume effect (production, sales volume & capacity utilization) or price effect (negative price undercutting). The Authority should reject the illegal computation of landed value, net selling price and resultant revised price undercutting determination.
- That Hon'ble CESTAT in Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority 2006 (201) E.L.T.481 (Tribunal) had earlier quashed the duty order on the grounds of lack of evidence of injury and causal link. Therefore, the Authority is required to terminate this case and initiate a new case considering new POI when the plant was in running condition;
- That India's demand during POI was 1,18,000 MT, whereas the domestic industry has capacity to cater only about 48,000 MT. Local demand being more than 2.5 times the domestic production domestic users are dependent on imports from the Subject Countries;
- That even after operating at the rate of 104% of capacity utilization, the profitability of the domestic industry declined, which shows the degree of other reasons impacting the company.
- High and erratic cost due to internal reasons has been attributed to imports from subject countries. A comparison of
 the Petitioner's consumption of power and steam per unit produced clearly shows a substantial increase in 2013-14
 because of inefficiencies resulting from the major shutdowns and subsequent restarts of the production equipment
 due to a key raw material supply shortage;
- That the Authority should take into consideration the loans taken by the Petitioner and only those loans that relate to or may be apportioned to subject product should be taken into account while determining non-injurious price;
- Designated Authority should strictly apply the principles laid down in Annexure III of the Rules for the purposes
 of determining non-injurious price. Exorbitant 26% return on Gross Fixed Assets claimed by the domestic industry
 is without any justification.

(c) Views of the domestic industry

- 122. The domestic industry, in its various submissions, has inter alia argued:
- That the dumped imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms and in relation to production & consumption in India and the imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent;
- That the imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping;

- That the performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, inventories, market share, profits, return on investments, cash flow, and has reached negative levels;
- That the performance of the domestic industry was sub-optimal in respect of production and domestic sales. Decline in sales volumes has adversely affected the production and capacity utilization. However, decline in production and capacity utilization is partly due to dumped imports and partly due to unavailability of raw materials;
- That dumping margins of the imports from the subject countries are significant and import prices are significantly affecting the prices of the domestic industry resulting price suppression. Growth of the domestic industry is adverse in terms of a number of parameters;
- That considering the interest rate offered by the banks in India, importers, who are availing long credit periods from the exporters, are getting credit at much lower rate thereby making imports significantly cheaper as compared to domestic industry prices. That is one of the reasons for preference of imports. Therefore, suitable adjustment should be made accordingly to the net sales realization of domestic industry and landed price of imports;
- That the production in the POI declined on account of non-remunerative prices for some time and shortage in the supply of raw material for some time. Considering that the loss of production some period during the POI is due to other factors, the petitioner has made necessary adjustments for the idle time cost for the purpose of working out injury caused by dumped imports. It would be seen that even if the petitioner had achieved normal production in the POI, the selling price would have been below cost of production;
- That the Authority may either (a) eliminate the period when the plant was closed because of non-availability of raw materials from the entire injury data and examine the performance of the domestic industry thereafter; or, (b) consider the performance of the domestic industry as it would have been had the plant not suffered from raw materials non availability;
- That APL's Oxo Alcohols unit employs the latest and the best technology available globally with high efficiencies. It has established operations at high levels of production on a consistent basis, barring the Force Majeure situation;
- That the decline in profitability of the domestic industry during 2012-13 when the plant was operating at 104% clearly establishes that it is the dumping of the product which has caused injury to the domestic industry;
- That even when dumping in POI is limited to Jan, 2014 to June, 2014, the injury period is from April, 2010 to June, 2014 and the DA is required to determine whether the domestic industry has suffered injury by considering performance over the injury period;
- That the domestic industry need not be in a position to meet the demand for the product in the country as a legal pre-requisite for seeking relief under anti dumping law. This is borne out not only by repeated decisions of the Designated Authority but also decision of the CESTAT [in the matter of DSM Idemitsu Ltd. Vs Designated Authority 2000(119) ELT 308];
- That APL's production capacity is around 35% of Nation's demand for 2-EHA. The demand-supply gap is met through imports which will continue to be imported until the additional capacities are created in the country;
- That the selling prices reported by the domestic industry are on the basis of the prices of the imported product to the consumers. However, there is a significant time lag between placement of orders by the consumers on the foreign suppliers and the arrival of goods in India. By contrast, the domestic industry supplies the goods immediately;
- That since the selling price of the domestic industry is dependent on the import price prevalent in the international market petitioner submits that the price undercutting should not be determined by comparison of landed price of import with the selling price of the domestic industry. Instead, the Authority should compare the price at which orders have been placed by the consumers on the domestic industry and exporters. Petitioner refers to the issue of date of sale in this regard where extensive investigations are conducted globally;
- That since the domestic industry is negotiating its price on the basis of prices prevailing in the international market the price undercutting could alternatively be determined by adopting the price mentioned in the trade journals. This would clearly show that the price undercutting is significantly positive;
- That if the contention of the Association is that the Authority should not exclude the idle time cost, the Authority may proceed accordingly. Either way, the situation shall show far higher injury than the one claimed by the domestic industry;
- That deterioration in performance of the domestic industry clearly establishes that the domestic industry has suffered injury. Admittedly, there are three reasons for this injury to the domestic industry (a) dumping of the

product in the country and (b) inability of the domestic industry to produce the product for some time when the raw material was not available with the domestic industry and (c) decision of the domestic industry not to recommence the production despite availability of raw materials during the period Jan, 14 to June, 14 because of significant dumping in the country resulting in grossly unfair price available to the domestic industry;

- That despite achieving reasonable level of capacity utilization, the domestic industry is still suffering financial loss. This performance for the post POI period further establishes that the domestic industry is suffering significant adverse price effect in the form of financial loss, adverse return on capital employed and cash flow which is clearly due to dumping;
- That the decision of the CESTAT, referred to by the interested parties merely shows that the Authority should examine various factors of injury. The decision does not imply that merely because there are some other factors affecting the domestic industry the Authority cannot proceed with the case. Rules has provided for consideration of "a" causal relationship and not for consideration of "the" causal relationship. The placement of 'a' in place of 'the' is extremely significant in this regard and is clearly borne out by the decisions of the WTO. It is no longer *res judicata* that (a) dumping need not be the sole cause of injury, (b) there may be other factors also which may at the same time be causing injury to the domestic industry; (c) presence of other factors does not imply that the Authority shall terminate the investigation;
- That in addition to consumption of power in the production plant, significant power consumption by the company is in various operations. Further, this also includes the element of power consumed in various administration facilities. The cost of utilities in the plant is normal and reasonable and has not increased significantly at all as has been argued by the interested parties;
- The reason for foreign producers to resort to dumping is the fact that in the global market capacities for consideration of PUC are significantly higher than the demand for the PUC. Thus, while association is considering the demand supply gap in India, the Association is conveniently hiding the fact very well known to their members that the product is significantly surplus in the global market;
- That production of EHA by the petitioner, since its inception, clearly shows that there is no erratic pattern in production by the petitioner. In fact, the petitioner has consistently produced and sold close to capacities and some time even beyond capacities;
- That disruption in Propylene supply is only for a short period i.e., 2 to 3 months which is a *force meajure* situation (i.e., fire accident). The Plant was stopped for a longer period due to non-remunerative selling prices which was much lower than marginal cost of production;
- That ICRA Report quoted by the interested parties is based on the consideration of total financials of the Company i.e., lower capacity utilization and loss incurred due to non-remunerative selling prices;
- That Propylene is a specialty product produced by Oil Refining companies and/or Hydrocarbon (mostly Naphtha/Natural gas) units. Propylene, in general, is a not commodity product and mostly the Refinery's Propylene is used for downstream products other than the Polypropylene due to lack of economies of scale for Polypropylene. Oxo Alcohols is one such product. Projects based on such single source of specialty product are not uncommon in the Industry;
- That petitioner has collected DGCI&S transaction wise data after initiation of investigation. The information on record shows there is no material difference between published and transaction wise data.
- That despite high level of capacity utilization the domestic industry suffered injury even in 2012-13. Even after achieving significant production in 2015-16, the domestic industry continues to suffer financial losses, which clearly establishes injury due to dumping from subject countries;
- That various expenses for the period of non production have already been excluded. Once these expenses are excluded, petitioner wonders why the data should still show loss. The negative growth in profits, return on investment and cash flow even after excluding expenses for the shut down period clearly establishes adverse effect of dumping on the domestic industry;
- That while employees were not retrenched during the period of "non production", salaries paid during this period have not been included in determining profits of the domestic industry;
- That the position of the company is very precarious and the sole hope that company now has is the protection through imposition of anti-dumping duties on the subject goods.
- That significant interest free credit is being extended by the foreign producers to the importers directly making the domestic sales unviable as the petitioner is unable to extend any credits to the customers. On the other hand,

petitioner is buying Propylene from public sector Hindustan Petroleum Limited on cash basis. This is leading to a minimum impact of 3% on the petitioner's prices, which is very significant for its operations. Therefore, the import prices should be duly adjusted to neutralize the effects of credit benefits granted by the exporters for a fair comparison;

- That even when imports technically attract VAT, practically, the importers do not incur this cost. However, all supplies made by the domestic industry attract CST which is leading to a difference of 2% in the prices. As these are the taxes and levies imposed by the Government all business enterprises need to follow the same;
- That majority of the imports are happening at Kandla Port which is about 250-300 Kms from the major consumers of these products. As opposed to this, the domestic industry has to transport the finished products by about 1000 kms, whereas the raw material is procured across the fence through pipeline incurring no cost. It is unfair to Indian manufacturing sector that the freight cost on finished product is treated as inadmissible cost item and freight cost on raw material is treated as part of cost. If the objective of the calculations is to determine "injury to the domestic industry", it must be calculated after taking into account all the factors that affected injury.
- That the methodology followed by the Directorate for determination of NIP is leading to grossly low quantum of anti-dumping duty.

(c) Examination of the issues by the Authority

- 123. The Authority has taken note of the specific issues raised by the interested parties with regard to various injury and causal link parameters and those concerns have been addressed in the succeeding paragraphs in this analysis. Some of the general issues regarding injury and causal links have been examined as under:
- 124. As regards the issue of self inflicted injury due to closure of the plant for an extended period during the POI and lack of causal links the Authority notes that the investigation reveals that the plant was shut down for 263 days during the POI (15 months period). Detailed examination indicates that Propylene supply was disrupted due to fire and other maintenance issues at HPCL's end for a total period of 231 days. For the remaining period though Propylene was available APL failed to lift it due to un-remunerative prices of 2-EH and production facility of APL remained shut down for that period.
- 125. The interested parties have argued that the petitioner domestic industry has suffered because of dependence on a single supplier of the vital raw material. Investigation reveals that most of the production units of the subject goods are linked to the producers of Propylene across the fence and therefore, raw material linkage, in a manner in which the petitioner operates, is not uncommon in this product. As far as production loss and its impact on the cost of production is concerned, the issue has been addressed by identifying the idle costs and not attributing this cost to the cost of production and sales so that injury on account of the plant closure is not attributed to the dumped imports to establish the causal link between dumped imports and injury suffered by the domestic industry. To that extent the concerns of the interested parties have been adequately addressed.
- 126. Further examination of the monthly production and sales data of APL reveals that APL has operated well beyond rated capacity in certain moths. But the sales realization of the goods in those months shows that the prices have been bench marked against the landed values of imports from the subject countries and have not recovered the costs, giving credence to the argument of the domestic industry that they have been forced to shut down the plant due to un-remunerative prices even when propylene was available.
- 127. As regards the arguments of the interested parties that there is a significant shift in preference of refineries to produce Polypropylene in place of Propylene and thereby affecting availability of Propylene for production of 2-EH, the Authority notes that this would be true for all global producers and therefore, the petitioner domestic industry cannot be singled out for denying the protection from unfair trade practices as per the Rules.
- As regards the concerns of some of the users that their contracts with their end-users are on fixed price terms with penalties for delayed deliveries and disruption of supplies from the domestic producer affects their operations and therefore, they have to depend on imports, the Authority notes that the purpose of the antidumping duty mechanism is to remove the distortions in the market due to unfair trade practices and create a level playing field for all the players in the domestic market. Therefore, import option, in the event of domestic supply disruption, is not closed for these users. It would be in the interest of the users of the subject goods to have a viable and efficient producer in the domestic market than being fully dependant on imports.
- As regards the earlier decision of the CESTAT setting aside the earlier duty on the grounds of lack of evidence of injury and causal link, the Authority notes that it was a separate investigation and the CESTAT's order in that case was on the basis of the factual matrix of the situation that existed at that point of time and the examination of the factors examined by the Authority in that finding, therefore, has no bearing on this investigation. Earlier decision of the CESTAT no way restricts the Authority from conducting a fresh investigation in the factual matrix of the situation as exists at this point of time. The Authority has objectively examined all the injury and causal link factors afresh as it

existed during the current investigation period to arrive at the final decisions. Therefore, arguments of the interested parties in this regard are not tenable.

- 130. As regards the submissions of the interested parties that the Authority should not allow higher return on investment claimed by the domestic industry for determination of non-injurious price, the Authority notes that the principles laid down in Annex-III to the Rules are consistently followed in all investigation for determination of the NIP irrespective of the claims of the domestic industry.
- 131. The Authority notes that the domestic industry has sought several adjustments to the domestic selling prices and import prices for determination of price effects of the dumped imports and injury margins.
- 132. As regards the arguments of the domestic industry that the differential in domestic taxes paid by the domestic industry on supply of the material should be adjusted, the Authority notes that comparison of the ex-works domestic selling prices, net of all local taxes and levies is carried out with the landed value of imports which does not include such local levies. Therefore, the comparison is fair and no further adjustments on account of local levies are called for.
- 133. As regards the arguments of the domestic industry that the freight cost should be adjusted in price comparisons of domestic sales and imports due to significant freight difference, the Authority notes that all comparisons are made at a particular level. Ex-works prices of the domestic industry are compared with the entry point landed prices of imports, as they are considered as at the same level of trade for the purpose of price comparability. The geographical location of the producers and consumers may depend upon various factors, including availability of raw materials and ease of transportation of finished goods etc. Similarly, the importers may prefer to import the goods through a particular port depending upon the logistics involved. These are commercial decisions of the various players and these factors cannot be taken into consideration for price comparability.
- 134. As regards the arguments of the domestic industry seeking adjustments on account of credit being extended by the exporters to the importers, which distorts the price comparability, the Authority notes that the investigation reveals that the exporters extend two kinds of credits to the importers i.e., normal free usance period of 60-90 days (sometimes upto 180 days); and in certain cases additional credit period of 120 to 180 days on payment of interest at LIBOR rates which works out to about 2% per annum, whereas the domestic industry sales the goods on cash basis. The arguments of the domestic industry have been examined in this context. Normally, for the purpose of determination of Normal Value and Export Prices of the exporter the notional credit costs, worked out on the basis of short term credit costs denominated in local currency for domestic sales and foreign currency in export sales, are deducted from the invoice prices to arrive at the net ex-works prices for comparison as this is one factor that affects price comparability due to difference in domestic and foreign currency interest rates and also credit periods.
- 135. So far, for comparison with the ex-works net sales realization of the domestic industry in India, the CIF price of the imports paid by the importer to the exporter, after the credit period, is not being adjusted for the notional credit availed by the importer. This was on the premise that the domestic industry also extends certain credit period to its customers in normal business practice. However, in certain cases, as is the case here, the domestic industry sales the subject goods in cash whereas the exporters are extending and the importers are availing extended credit periods up to 270 days, part of which is free and part of which is paid at LIBOR rates whereas the domestic cost of credit for the similar terms are very high. Therefore, the importers are availing significant interest rate arbitrage by getting credit from the exporters at cheaper rates whereas the domestic cost of credit in India is high. It has been argued that this makes the imports cheaper to that extent and thereby significantly affects the price comparability in the importing country market for price effect analysis, particularly when the domestic industry sales the goods without any credit and the prices are generally discounted in such a situation.
- 136. The interested parties, during the public hearing, argued that any such adjustment to the domestic selling prices or the landed value of imports to account for the credit cost would affect the principles of injury margin determination as laid down in Annex-III to the Rules and such adjustments cannot be made without amending the Rules. The Authority notes that Annexure III only provides for principles for determination of the Non-Injurious Prices and does not deal with the methodology of comparisons for determination of injury margins. Therefore, any adjustments to domestic prices or import prices for price effect analysis or injury margin computation will not be hit by any provision of the law. Rather the principles for such adjustment emerge from the Agreement and Rules which allow adjustments for factors that affect price comparability.
- 137. In its post disclosure submissions the domestic industry has reiterated its arguments on various adjustments claimed by them and has argued that the Authority has rejected request of the petitioner for inclusion of freight for determination of injury margin without considering that (a) a company has to incur freight cost on raw materials and finished products; (b) any manufacturer optimizes between the two; (c) freight cost on raw materials is a part of NIP, there is no reason why freight cost on finished product should not form part of cost in determining injury margin. Merely because the Petitioner decided to avoid freight cost on raw materials, the Designated Authority should not penalize the domestic industry by disallowing the freight cost on finished product. It has been argued that Brazil has

two methodologies for determination of injury margin – a comparison of ex-factory price with CIF import price and delivered price with DDP prices. It is evident that both methodologies are appropriate and are required to be considered. It has been further argued that the Authority has rejected the contention of the domestic industry for consideration of credit period for injury margin determination because there is lack of clarity on some issues. Domestic industry argues that the impact of credit can be seen either in terms of "cost to the exporter" or "benefit to the importer". Therefore, these adjustments should have been allowed.

- 138. However, the Authority notes that though the arguments of the domestic industry in this regard have some merit the extended credit period and interest rate arbitrage also carries the exchange rate risk and cost of risk cover is often high. As far as freight adjustment for comparison with the imported goods are concerned, as noted earlier, as per the consistent practice of the Authority all comparison are carried out at a particular level. Therefore, the Authority confirms its view that without complete information actual freight on domestic sales and exports against each transaction and on various risks attached to credit period availed and implications thereof it may not be appropriate to make any such adjustments to the import prices/landed values for the purpose of price undercutting and underselling analysis.
- 139. Other issues raised by the interested parties and the domestic industry have been addressed in the relevant parts in this finding.

H.3 Examination of Injury and Causal Links

- 140. Annexure II to the Anti Dumping Rules in its relevant part provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
- 141. In accordance with the Rules all economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under: -

(a) Volume effects of dumped imports and impact on domestic industry

i. Import Volumes and share of dumped imports

142. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. As noted earlier transaction-wise import data as reported in DGCI&S data and data collected from Kandla Port has been used for this determination. As per this data the imports of the subject goods during the injury investigation are as follows:

Import Volumes	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised	POI
Dumped Imports							
EU	MT	10440	21429	17967	26248	31582	39477
Indonesia	MT	0	0	3900	16386	23639	29549
Korea RP	MT	171	0	2954	6413	5130	6413
Malaysia	MT	4748	8508	17441	21954	21353	26691
Taiwan	MT	0	0	3019	6499	5199	6499
USA	MT	1180	2039	0	4632	3706	4632
Total Dumped imports	МТ	16539	31976	45280	82132	90609	113261
Trend		100	193	274	497	548	685
Other Countries	MT	16744	5093	14424	16592	18637	23296
Trend		100	30	86	99	111	139
Total	MT	33283	37069	59704	98724	109246	136557
Trend		100	111	179	297	328	410

143. The above data indicates that the total volume of imports have increased in absolute term by over 3 times on annualised basis over the injury investigation period. However, the dumped imports from the subject countries have increased by about 5.5 times in the POI Annualised, compared to the base year.

ii. Share of dumped imports

144. The share of dumped imports in total imports is as follows:

		2010-	2011-	2012-		POI	
Market Share in Imports		11	12	13	2013-14	Annualised	POI
Dumped Imports							
EU	%	31%	58%	30%	27%	29%	29%
Indonesia	%	0%	0%	7%	17%	22%	22%
Korea RP	%	1%	0%	5%	6%	5%	5%
Malaysia	%	14%	23%	29%	22%	20%	20%
Taiwan	%	0%	0%	5%	7%	5%	5%
USA	%	4%	6%	0%	5%	3%	3%
Sub total	%	50%	86%	76%	83%	83%	83%
Other Countries	%	50%	14%	24%	17%	17%	17%
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

145. The above data shows a significant jump in the share of dumped imports from the subject countries from about 50% of total imports in the base year to about 83% in the POI indicating significant displacement of other country shares in the import basket.

iii. Assessment of Demand/Apparent Consumption

146. Demand or apparent consumption of the product in India has been estimated as the sum of domestic sales of the petitioner and imports from all sources. The demand so assessed is as follows:

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	POI
					Annualized	15 months
Sales of DI	MT	35,922	49,401	47,642	20,304	25,381
Subject Countries	MT	30,137	34,578	57,588	104,814	131,017
Other Countries	MT	3,146	2,491	2,116	4,432	5,540
Demand/						
consumption	MT	69,206	86,470	107,347	129,550	161,937
Trend		100	125	155	187	187

147. The above data indicates that there is a healthy growth in demand for the subject goods in India and the demand has increased significantly over the injury period. However, while the demand growth is about 87% compared to the base year the increase in dumped imports is almost 550% during the same period and the sale of the domestic industry has declined significantly after a healthy increase in 2011-12 and 2012-13. Thus the dumped imports have increased significantly in absolute term as well as in relation to the domestic production and demand. The Authority takes note of the fact that a major part of the decline of the domestic sales of the petitioner is due to plant shut down for an extended period during the investigation period, partly because of unavailability of raw materials and partly because of other reasons, including un-remunerative prices as claimed by the petitioner.

(b) Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

- 148. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 149. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression.
- 150. As noted in the previous paragraphs the domestic industry has argued that certain adjustments towards credit cost and transport cost should be made for price undercutting and price underselling analysis. However, this request has not been found to be acceptable in the absence of complete information on other risks involved and implications thereof. Therefore, the consistent practices of the Authority in these regards have been followed.

(a) Price undercutting effects of dumped imports

151. For the purpose of price undercutting analysis the net sales realization (NSR) of the domestic industry has been compared with landed value of imports from the subject countries. While computing the net sales realisation of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realisation at exworks level is determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the price undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Country	Price undercutting calculations	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
	Net Selling price of DI	Rs/MT	****	****	****	****
	Trend		100	101	108	108
EU	Landed Value	Rs/MT	89,426	87,455	95,918	95,247
	Price under cutting	Rs/MT	(****)	(****)	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	Range	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)
Indonesia	Landed Value	Rs/MT	0.00	0.00	95,392	95,704
	Price under cutting	Rs/MT	-	-	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	-	-	(****)	(****)
	Range	%			(0-10%)	(0-10%)
Korea RP	Landed Value	Rs/MT	85,279	-	1,01,472	96,932
	Price under cutting	Rs/MT	(****)	-	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	(****)	-	(****)	(****)
	Range	%	(0-10%)		(0-10%)	(0-10%)
Malaysia	Landed Value	Rs/MT	86,595	87,521	96,150	95,738
	Price under cutting	Rs/MT	(****)	(****)	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	Range	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)
Taiwan	Landed Value	Rs/MT	-	-	94,631	95,560
	Price under cutting	Rs/MT	-	-	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	-	-	(****)	(****)
	Range	%			(0-10%)	(0-10%)
USA	Landed Value	Rs/MT	71,570	88,759	-	96,341
	Price under cutting	Rs/MT	****	(****)	-	(****)

	Price undercutting %	%	****	(****)	-	(****)
	Range	%	15-25%	(0-10%)		(0-10%)
Subject countries as a whole	Landed Value	Rs/MT	87,297	87,555	96,239	95,640
	Price under cutting	Rs/MT	(****)	(****)	(****)	(****)
	Price undercutting %	%	(****)	(****)	(****)	(****)
	Range	%	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)	(0-10%)

152. The above data shows that the landed values of imports form the subject countries did not undercut the prices of the domestic industry during the POI. However, the price undercutting may not be relevant if the domestic prices are already depressed or suppressed significantly. Therefore, the degree and extent of price suppression or depression, if any, has also been examined in addition to the price undercutting examination as above. The domestic industry, in its submissions, has argued that the price undercutting is negative largely because of significant credit being extended by the exporters.

(b) Price suppression/depression

153. As noted above, price suppression/depression effects of the dumped imports have also been examined to see if the dumped imports have significantly suppressed or depressed the domestic prices. To examine the price suppression effect of the dumped imports on the domestic prices the trend of net sale realization of the domestic industry has been compared with the cost of production of the domestic industry and the landed price of the dumped imports. The Authority notes the arguments of the interested parties that the production unit of the petitioner was shut down for an extended period of time during the POI and therefore, its costs would be significantly affected due to production loss. Therefore, the cost of production has been adjusted for such loss in production and the adjusted cost of the POI (assuming that there was no production loss and associated idle cost) has been considered for the price suppression and depression examination.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	POI with adjusted cost
Cost of Sales	Rs/Kg	****	****	****	****	****
Trend		100.00	106.86	119.90	140.33	133.87
selling Price	Rs/Kg	****	****	****	****	****
Trend		100.00	101.12	108.15	107.68	107.68
Landed Value	Rs/Kg	87.30	87.56	96.24	95.64	95.64
Trend		100.00	100.30	110.24	109.56	109.56

- 154. The above data indicates that the cost of production has been steadily increasing and has gone up significantly since 2012-13 and again in POI even after adjusting the cist for the production loss during the POI. While the adjusted cost, after adjusting the costs for the idle costs and production loss during the POI, was almost 33% higher compared to the base year, the selling prices of the domestic industry has increased only by about 7%. The Authority notes that even the normated cost during the POI considered for determination of NIP shows an increase of 21% as compared to the base year. Analysis of the prices of basis raw material i.e. propylene during the same period shows a significant increase of about 40% compared to the base year. The weighted average landed values of the imports have increased by only by about 9% during the same period. This indicates that the domestic industry is forced to keep the prices suppressed in order to retain its market in the presence of significant dumped imports.
- 155. The domestic industry could not achieve normal production in the POI partly due to shortage of raw material from the only supplier, i.e., HPCL for some time and partly due to non-remunerative prices for an extended period. The data above indicates that even if the domestic industry was able to achieve normal production in the POI, the cost would have been significantly higher than the selling prices at which they were able to sell in the domestic market due to the effects of presence of dumped imports in the same market. The domestic industry contends that the plant shutdown, even after resumption of supplies from HPCL, was to contain the losses as the prices were not-remunerative.

Therefore, the domestic industry's prices appear to be suppressed to retain market share to the extent they could produce and sell during this period and that explains the reasons for the negative price undercutting.

(c) Price underselling effects of dumped imports

156. For the purpose of examination of the price underselling effects the landed prices of imports from subject countries/territories have been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI in accordance with the norms prescribed in Annex-III to the Rules. Price underselling margins of dumped imports are as follows:

Country	NIP Rs/Kg	Landed Values Rs/Kg	Underselling Rs/Kg	Underselling %	Range
EU	****	95.25	****	****	0-10%
Indonesia	****	95.70	****	****	0-10%
Korea RP	****	96.93	****	****	0-10%
Malaysia	****	95.74	****	****	5-15%
Taiwan	****	95.56	****	****	0-10%
USA	****	96.34	****	****	0-10%

157. The data indicates that the dumped imports are below the non-injurious prices of the domestic industry though the underselling margins are in a narrow range.

H.4 Examination of Economic parameters relating to the domestic industry

(a) Actual and Potential Impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

158. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry is given in the table below. The Authority notes that out of total 455 days of the POI the plant was in operation for only 192 days. As per the records of the petitioner the plant had to be shut down due to non-availability of the basic raw material i.e., Propylene from HPCL because of a major fire in that plant and other maintenance related issues. Even after the raw material supply was restored and the plant was put to operation, due to poor price situation, because of increased presence of dumped imports, the production was suspended intermittently for about 118 days resulting in very low production and capacity utilisation. Therefore, production, capacity utilisation and sales have been projected assuming that there was no plant shut down, to isolate the plant shut down as a factor of injury, and see whether the petitioner would have been able to produce and sell significant quantities had the plant not been shut down due to raw material unavailability.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualized)	POI (Actual)	POI (Projected)
Capacity	MT	44,000	48,000	48,000	48,000	60,000	60,000
Production	MT	36,126	48,967	49,775	18,570	23,212	40742
Trend		100	136	138	51	64	113
Capacity Utilization	%	82%	102%	104%	39%	39%	68%
Trend		100	124	126	47	47	83
Domestic Sales	MT	35,922	49,401	47,642	20,304	25,381	44548
Trend		100	138	133	57	71	124
Demand/ consumption	МТ	69,206	86,470	107,347	129,550	161,937	
Trend		100	125	155	187	187	

- 159. The data above shows that while there was about 10% capacity addition in 2011-12, in response to increase in the demand for the product under consideration, and the petitioner was achieving more than 100% capacity utilisation till 2012-13, there has been a significant production loss in the POI resulting in very low capacity utilisation and low sale volume.
- 160. The data above further indicates that even if the raw material supply was not affected and the plant was in operation for those 192 days the production and capacity utilisation would have reached only a level of 40742 MT and 68% respectively while the demand for the product shows a healthy growth during the same period. The petitioner has contended that the plant was shut down for remaining 118 days not because of the raw material supply disruption but because of un-remunerative prices due to dumped imports. While the costs had increased, the prices were suppressed due the presence of significant volume of dumped imports.

(b) Actual and Potential Impact on Profitability, Profits, return on investment and cash flow

161. Cost of production and other associated costs, as well as selling prices, of the domestic industry have been examined taking into account the arguments of the interested parties about the production losses of the petitioner during the POI. The profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market works out as follows: -

Particulars	Unit				POI	
		2010-11	2011-12	2012-13	Annualized	POI
Cost of sales	Rs./KG	****	****	****	****	****
Trend		100	106.85	119.90	133.86	133.86
Selling price	Rs./KG	****	****	****	****	****
Trend		100	101.13	108.15	107.68	107.68
Profit/loss	Rs./KG	****	****	****	(****)	(****)
Trend		100	61.50	27.10	-72.80	-72.52
Cash Profit	Rs./KG	****	****	****	(****)	(****)
Trend		100	61.94	26.48	-69.57	-69.57
Profit before Interest	Rs./KG	****	****	****	(****)	(****)
Trend		100	56.99	31.14	-38.45	-38.45
Return on Capital Employed	%	****	****	****	(****)	(****)
Trend		100	82.61	43.48	-26.09	-26.09

162. The above data indicates that the cost of sales and the selling price, increased over the injury period except a marginal decline of the selling price in the POI. However, the increase in selling price was lower than the increase in cost due to price suppression caused by significant increase in the volume of dumped imports, thus leading to decline in profitability. The cash profits and return on capital employed have declined sharply and have become negative in the POI. Even after segregating the cost incurred on account of idle time from the total cost the profitability shows significant decline apparently as a result of the dumping from the subject countries.

(C) Actual and potential impact on Market Share

163. The trends in market share of various players in Indian market have been shown below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised
Domestic Industry	%	51.91%	57.13%	44.38%	15.67%
Subject countries-Imports	%	23.90%	36.98%	42.18%	69.94%
Other Countries-Imports	%	24.19%	5.89%	13.44%	14.39%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

164. The data indicates that domestic industry had a dominant position in the Indian market till 2011-12 when it commanded over 52% of Indian demand. Thereafter the market share of the domestic industry has significantly declined whereas the dumped imports have significantly occupied that space. Even in 2012-13 when the industry was operating at almost full capacity it had lost market share to the dumped imports. Part of the loss in market share in POI is however, due to production loss on account of raw material supply disruption. Even after isolating that factor the loss in market share on account of dumped imports is significant and material. Even considering that had the raw material supply not been disrupted and the plant was in operation during this period the projected market share would have been of the order of about 30%. This indicates that the petitioner has lost a sizable market share to dumped imports during the POI.

(d) Actual and potential impact on Employment, Productivity and Wages

165. The Petitioner Company produces a number of products in the same production line. Therefore, the impact of dumped imports of the subject goods on employment may not be a very good indicator of injury. The Authority notes that the production was suspended during this period for a prolonged period for various reasons, including dumping. Therefore, the employment and wages and productivity parameters are not relevant as injury indicators in this case. However, the details are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised
No of Employees for the company	Nos	****	****	****	****
Trend		100	102	121	120
Salaries & Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend		100	116	144	129
Wages per Unit of Production	Rs./Kg	****	****	****	****
Trend		100	86	105	252
Productivity per employee	MT	****	****	****	****
Trend		100	133	114	43

166. The data indicates that keeping in line with the capacity increase and production volumes in 2011-12 the employment level and wages increased in 2012-13 and wage cost per unit remained almost constant during the first three years of the injury period. But due to significant production loss the wage cost per unit of production increased significantly in the POI. As far as productivity is concerned, per employee productivity was highest in 2011-12 when the unit achieved over 100% capacity utilisation. The productivity in the POI has fallen sharply due to low production during this period.

(e) Actual and potential impact on Growth

167. The data indicates that the industry was in the growth path upto 2012-13 with increase in capacity and production. But during the POI all physical and financial parameters show significant adverse trend. Growth, with regard to sales, production, market share, profits, return on investments and cash flow, has been significantly negative during the period of investigation.

Growth	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised
Production	Y/Y	-	36%	2%	-63%
Domestic Sales	Y/Y	-	38%	-4%	-57%
Cost of Sales	Y/Y	-	7%	12%	17%
Selling Price	Y/Y	-	1%	7%	0%

Profit/(Loss)	Y/Y	-	-38%	-56%	-532%
Return on Investment	Y/Y	-	-4%	-9%	-23%

(f) Actual and potential impact on Inventories

168. The inventory position of the domestic industry indicates that in spite of healthy demand in the country the average stock of the petitioner has increased in 2012-13 and POI apparently due to the price pressure of dumped imports and inability of the petitioners to sell in the domestic market at reasonable price.

Stock (Volume)	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised
Opening	MT	****	****	****	****
Trend		100	146	48	526
Closing	MT	****	****	****	****
Trend		100	33	362	28
Average	MT	****	****	****	****
Trend		100	79	234	231

(g) Factors affecting domestic prices

169. The preliminary examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods which goes into a number of downstream products such as plasticizers. However, the domestic capacity is about 40% of the demand. Therefore, imports play a major role in the domestic prices. The data indicates that dumped imports from the subject countries/territories initially accounted for about 30% of the domestic demand which has gone upto about 70% of the demand. These imports are at dumped prices and below the cost of production of the domestic industry causing significant price suppression and makes the prices un-remunerative for the domestic industry.

(h) Ability to raise capital investments

170. The petitioner has made investments in 2010-11 to expand the capacity in order to meet the increasing demand. After a period of good performance upto 2012-13 the performance of the domestic industry deteriorated because of various reasons, including the impact of dumped imports. The profits of the domestic industry have steeply declined to a situation of financial losses. Therefore, the ability of the industry for further expansion or capacity addition appears to have been adversely affected.

(i) Level of dumping & dumping margin

171. The dumping margins as a indicator of potential injury to the domestic industry indicates that margins of injury from each of the subject countries/territories are above de-minimus and significant.

H.5 Conclusion on injury

172. The above examination indicates that imports from the subject countries/territories are entering the Indian market at significant volumes at dumped prices. The volume of imports and the prices at which they are being exported from the subject countries are causing both volume and price impact on the domestic industry which is reflected in decline in production, (even if the production loss due to supply disruption is accounted for) and significant decline in financial performance leading to losses in the period of investigation. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales, profits, return on investments and cash profits to a very significant extent. Therefore, the Authority concludes that the impact of the dumped imports on the domestic industry has been adverse and the domestic industry has suffered material injury.

H.6 Injury Margins

173. The Non-injurious price of the domestic industry has been determined as per the principles laid down in Annex-III to the Anti-dumping Rules. Landed prices of imports from various countries have been compared with the non-injurious price so determined for determination of the injury margins of the subject dumped goods imported from the subject countries/territories. The data indicates that the landed prices of imports from most of the subject countries/territories are substantially below the non-injurious prices calculated for the domestic industry.

Exporter	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	IM US\$/MT	IM %	IM Range
nion					
ICC Chemicals Corporation	****	****	****		
Petrochem Middle East Fze.	****	****	****		
Vinmar International Ltd	****	****	****		
Overall	****	****	****	****%	0-10%
rs					
Any	****	****	****	****%	0-10%
BPC	****	****	****	****%	0-10%
Talaysia)					
Any	****	****	****	****%	0-10%
HYUNDAI CORPORATION	****	****	****		
VINMAR	****	****	****		
Overall	****	****	****	(****%)	Negative
outh Korea					
Any	****	****	****	****%	0-10%
Direct Sales	****	****	****		
SOJITZ ASIA PTE LTD	****	****	****		
Overall	****	****	****	****%	0-10%
ll others					
Any	****	****	****	****%	0-10%
rs in USA					
Any	****	****	****	****%	0-10%
pei All Exporters					
Any	****	****	****	****%	0-10%
	ICC Chemicals Corporation Petrochem Middle East Fze. Vinmar International Ltd Overall S Any BPC Malaysia) Any HYUNDAI CORPORATION VINMAR Overall Outh Korea Any Direct Sales SOJITZ ASIA PTE LTD Overall Il others Any S in USA Any Dei All Exporters	ICC Chemicals Corporation Petrochem Middle East Fze. Vinmar International Ltd Overall **** Any **** BPC **** HYUNDAI CORPORATION VINMAR Overall **** Overall **** Any **** **** **** Direct Sales SOJITZ ASIA PTE LTD Overall **** Any **** Any ***** Any ***** **** Any ***** Any ***** **** Any *****	ICC Chemicals Corporation Petrochem Middle East Fze. Vinmar International Ltd Vinnar Vi	US\$/MT	US\$/MT

I. Causal Links and Non-attribution Analysis

- 174. The above analysis indicates that domestic industry has suffered material injury. However, as recorded earlier, the interested parties have strongly argued that the injury, if any, suffered by the domestic industry is on account of other factors, including the disruption in supply of basic raw materials from their only supplier. The domestic industry has argued that dumping need not be the sole cause of injury. There may be other factors also which may at the same time be causing injury to the domestic industry. Presence of other factors does not imply that the Authority shall terminate the investigation or not find causal link between injury and the dumped imports.
- 175. The Authority notes that while the domestic industry might be getting injured because of several factors simultaneously affecting it, it is important to establish whether the dumped imports, through their volume and price effects, are affecting the performance of the domestic industry, without attributing the injury caused by the other factors

to the dumped imports. The examination in the previous section indicates that the dumped imports have significant adverse volume impact on the domestic industry. The prices of the dumped imports have caused significant price suppression for the domestic industry. Therefore, there is a positive causal link between the dumped imports and the injury suffered by the domestic industry ever after isolating injury suffered due to the production loss on account of non-availability of raw materials. Having established that, the Authority has examined other mandatory parameters to see if other factors, other than the dumped imports from the subject countries, are the cause of injury to the domestic industry as has been argued by the interested parties. In this context the following mandatory factors have been examined alongwith the factors brought out by the interested parties in their submissions as follows:

(vii) Volume and prices of imports from other sources

176. The import data analysed above indicates that the volume of imports from the other sources is very small compared to the total imports as well as in comparison to the dumped imports.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Dumped imports	MT	16539	31976	45280	82132	90609
Trend		100	193	274	497	548
Other Countries	MT	16744	5093	14424	16592	18637
Trend		100	30	86	99	111
Total	MT	33283	37069	59704	98724	109246
Trend		100	111	179	297	328

177. While the dumped imports have increased by about 450% over the base year the imports from other undumped sources have increased by only 11% over the base year while the demand has increased by about 100% showing that they could not have injured the domestic industry.

(viii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

178. The examination of demand and consumption indicates that there is a healthy demand of the subject goods in the domestic market and there is no change in consumer preferences for any competing product. Therefore, demand is not factor affecting the domestic industry.

(ix) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

179. The Authority notes that the petitioner is the sole producer of the subject goods in India. There is no trade restriction for the subject goods and goods are being freely imported and traded. Therefore, trade restrictive practices or unfair competition within India could not have been the cause of injury to the domestic industry.

(x) Development in technology

180. Technology for production of the products has not undergone any change nor are there any likely changes in the coming future. The responding producers in the subject countries also use similar technologies. No argument has been made by any interested party alleging technology as a factor affecting the domestic industry.

(xi) Export performance of the domestic industry

181. The domestic industry has not exported the subject goods during the entire injury investigation period. Therefore, the export performance could not be a reason of injury to the petitioner.

(xii) Other issues raised by the interested parties

Apart from these mandatory non-attribution factors the interested parties have argued that the Authority should address other factors relevant to this case such as injury suffered by the domestic industry due to plant shut down for an extended period during the POI because of non-availability of basic raw materials from its sole supplier i.e., M/s. HPCL. The Authority earlier noted that during the period of investigation the production unit of the petitioner, located near Vishakhapatnam, remained closed for 263 days out of the 15 months of the period of investigation covering the period 2013-14 and 1st quarter of 2014-15. Out of these 263 days the plant had to be shut down for 145 days because of supply disruption from HPCL due to a major fire in that plant. Remaining 118 days the production had to be suspended intermittently because the petitioner was unable to sell the product in the market at reasonable price even to recover the costs due to presence of dumped imports from the subject countries at prices much below the cost of the petitioners with attractive credit terms and in significantly increased volumes.

183. As noted earlier, the likely production, sales and costs, had the production not been lost due to raw material issues, have been worked out and it has been noted that even if the production was not disrupted the petitioner would have suffered significant injury on account of dumped imports on account of price parameters. In fact had the petitioner produced during this period and sold in the domestic market at prices below its cost of production the losses would have been higher. In order to isolate the impact of plant shut down on the cost, due to supply disruption, for injury analysis and not to attribute that portion of the injury to the dumped imports, the cost has been adjusted for the idle costs as noted earlier for this analysis. Therefore, the injury caused on account of the production loss has not been attributed to the dumped imports.

J. Factors establishing causal link: -

184. The above examination indicates that the domestic industry's prices are significantly suppressed because of presence of significantly increased volume of dumped imports at prices below its cost of production preventing the domestic industry to realise remunerative prices to remain in production and sale. Decline in sales volumes has adversely affected the production and capacity utilization, even taking into account the production loss due to non-availability of raw materials. All these factors have led to significant financial losses to the petitioner. Examination of other known factors simultaneously affecting the domestic industry indicates that loss of production due to disruption of raw material supply affected the domestic industry for some time during the POI. But the injury caused by that factor has not been attributed to the dumped imports by isolating that factor to the extent possible. Therefore, the Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports though the performance of the petitioner was also adversely affected by the raw material constraints explained above.

K. Post Disclosure submissions of the interested parties with regard to injury determination

185. The interested parties, in their respective post disclosure submissions, have reiterated most of their views on injury and causal link which have been addressed in the relevant sections in this finding. For the sake of brevity those arguments have not been repeated here. Only specific comments made by the interested parties with regard to the injury and causal link analysis have been addressed here to the extent they are relevant.

K.1 Issues raised by Domestic industry

- 186. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has inter alia argued
 - i. That though there is no undercutting of prices, it is admitted fact that the prices of the domestic industry are suppressed prices; the suppression being caused by dumped imports. The price undercutting found by the Designated Authority is negative largely because of significant credit being extended by the exporters and its impact being ignored by the Authority. Further, the disclosure statement establishes existence of interest bearing credit offered by the exporters on top of interest free credits;
 - ii. That the effect of dumped imports was to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, thus, causing significant losses to the domestic industry and consequent impact of the dumped imports on the domestic industry was adverse as established by collective and cumulative assessment of various relevant economic factors and indices;
 - iii. That the Authority has already proposed termination of investigation and has carried out injury analysis after excluding imports from Saudi Arabia without giving any opportunity to the domestic industry to defend its interests. Further, the authority has not conducted on the spot investigation and yet terminated the investigation holding dumping margin as de-minimis;
 - iv. That the disclosure statement shows that the injury margin for LG is negative. It would be seen from the information available that import price from Korea is not materially different from import price from other countries under investigation. Such being the case, petitioner is unclear how the injury margin for Korea is negative;
 - v. That the cost audit report has been prepared by the cost auditors wherein the cost auditors have already excluded expenses for the idle time period. Thus, expenses reported by cost auditors in cost audit report are those expenses which were incurred by the company for producing and selling the product and exclude the expenses for the period when petitioner did not produce the product. Thus, the Authority should consider the expenses as per cost audit statement and ignore the fact that the petitioner's plant was under shutdown.
 - vi. That the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports for the subject countries even if the plant was shut down for raw material disruption for an extended period of time during the POI.

K.2 Examination of the issues raised by the domestic industry

187. The issues raised by the domestic industry have been examined as under:

- i. As regards the views of the domestic industry regarding determination of the non-injurious price is concerned, the same has been determined as per the normal practice of the Authority in this regards and therefore, no changes in the determination is called for.
- ii. As far as negative injury margin for LG is concerned, it may be noted that the injury margin is determined on the basis of actual CIF price and landed value of the exports by that Company. It may be noted that while total imports from Korea RP during the POI was 6413 MTs LG Chem exported only about 50% of that quantity. Therefore, overall price comparison may not give the correct picture of the level of injury margin of the cooperating exporter from that country.
- iii. As far as termination of investigation against Saudi Arabia is concerned the Authority notes that termination is warranted in terms of Rule 14 (b) of the Rules and the comments of the interested parties, including the domestic industry were sought through the disclosure statement. Therefore, it cannot be argued that the decision has been taken without giving any opportunity to the domestic industry to defend its interests.

K.3 Submissions of Other Interested parties

188. The Authority notes that the interested parties have essentially re-iterated their views on various aspects of injury claims of the domestic industry and made similar comments on the injury and causal link claims of the domestic industry and analysis of the Authority. Therefore, comments of the interested parties have been summarized as follows:

(a) Indian Plasticizer Manufacturers' Association and other importers

- i. That there is no causal link between the injury and the alleged dumped imports. It has been argued that in its annual report the domestic industry has accepted the fact that the losses during this period was mainly due to non-availability of Propylene for a long period resulting in 212 days production loss.
- ii. That the Appellate Body in US- Hot rolled Steel, held that an authority is required to separate and distinguish the effect of dumped import, from the effects of any other factor, on the domestic industry producing the like product. In the present investigation, the domestic industry, itself has mentioned in its petition that that had loss of production due to other factors. However, cleverly, the domestic industry has failed to mention the actual idle time during the POI and presented the petition based on assumptions best suitable to them. Therefore, the Authority should undertake the process of assessing appropriately, and separating and distinguishing, the injurious effects of dumped imports from those of other known causal factors, before arriving at the conclusion with regard to impact of dumped imports, if any.
- iii. That it seems the Authority was searching for a normal period as it was awkward to use the data of POI which was adversely affected by extended period of shut down. It would have been more reflective to use the capacity utilisation till 2012/13 if a potential decline is sales and other indicators was to be calculated;
- iv. That in Afga Gevaert A.G. Vs. Designated Authority 2001 (130) E.L.T. 741 the Tribunal held that besides, Interest of the users of the subject goods must be treated at par with that of the Domestic Industry. Interests of consumers being vital for the country the role of the user industry and importers is equally paramount.
- v. That Diesel is the basic/pioneer subsidize product which runs Indian Economy. Indian economy depends on Petroleum products major Approx. 80 % Crude in India is imported. Considering Nation's interest first it is essential to import 2-EH as it is a raw material to manufacture 2-EHN which is one of the most essential ingredient of Diesel as a cetane booster to avoid Diesel Deficiency in India. APL is the only soul producer of 2-EH in India in case if supply interrupts domestic users of 2-EH has to shut down their units (as import will take 7 to 8 weeks lead time) to as there is no alternative current supplier is available to domestic 2-EH users as it is essential to import 2-EH. Therefore, the investigation should be terminated.

(b) Comments of the Exporters and the Governments of the subject countries

- 189. These interested parties, in their respective submissions, have made the following observations on the injury and causal links:
 - i. That the disclosure statement has failed to demonstrate that the material injury, if any, is caused by alleged dumped imports;
 - ii. That the injury caused by other factors other than dumped imports have been disregarded as no evidence has been placed on record to show how the production loss of 212 days did not allegedly lead to self inflicted injury but the imports did;
 - iii. That the annual report of the domestic industry clearly mentions certain 'operational constraints' affecting their performance during the POI which has not been addressed by the Authority;

- iv. That the injury is self inflicted due to raw material issues and the disclosure has not stated how the cost of the petitioner has been computed taking into account plant shut down;
- v. That there is no price effect as the undercutting was negative and the landed prices were higher by about Rs5000/ MT which could not have prevented domestic industry to increase its prices. The reason for such unremunerative price should be some other reason as the landed prices were never in competition with the domestic prices;
- vi. That despite negative price undercutting the petitioner increased its sales price only by 8% in response to a 20% increase in cost of sales which means that the petitioner cannot claim that undercutting by subject imports have prevented them from increasing the sales price;
- vii. That the findings of price suppression due to alleged dumped imports are not substantiated as the cost of sales of the petitioner has increased on account of higher absorption of fixed costs which reflects lesser production quantity as the capacity was not optimally utilized;
- viii. That the imports of the subject goods increased during the POI only to bridge the gap in demand and supply in India. Domestic industry was unable to produce and sale due to non-supply of the raw material;
- ix. That certain presumptions made by the Authority, with regard to the production and market share of the domestic industry, if it had remained in production for the entire POI, are without any basis;
- x. That any segregation of the injury would have to consider normal production period and not POI itself as the POI was adversely affected. Therefore, determination of impact of price underselling on the production and sale volume is erroneous. It has been further argued that the impact of increase in prices of raw material on the cost of the product under consideration has not been analysed;
- xi. That the disclosure statement fails to provide any explanation regarding the methodology to calculate the projected numbers. Any weighted average projection based on previous years data is not appropriate because of the trends between 2010-13;
- xii. That increase in cost of sales the domestic industry is the main factor of injury. Unavailability of raw material and resultant plant shutdown is a factor which, even taken in isolation, breaks the causal link;
- xiii. That Indian user industry would be adversely affected if the duties are imposed;
- xiv. That the duty, if any, should be in Indian Rupees

K.4 Examination by the Authority

- 190. The Authority notes that most of the submissions of the interested parties with regard to the injury and causal links analysis are repetitive and re-iteration of their respective views expressed earlier. However, the issues have been examined and addressed as follows:
 - i. As regards the arguments of the interested parties that the Authority has failed to recognise the fact that injury is self inflicted due to factors which are not related to dumped imports, such as supply disruption and therefore, break of causal link, the Authority notes that the analysis clearly recognises the fact that the domestic industry's performance during the period of investigation was significantly affected by the supply disruption of the major raw material for an extended period during the POI. This factor has also been recognised in the Annual report of the Company as one of the factors for the poor performance of the petitioner during this period. While there is no disagreement on this factual position the investigation also establishes that after the supply was restored the domestic industry was not able to go back into regular or full scale production due to un-remunerative prices because of the presence of dumped imports in significant volumes. The investigation clearly reveals that some of the producers/exporters in the subject countries, who did not export the subject goods earlier, had resorted to significant volumes of dumped imports with significant credit terms taking advantage of the situation in the domestic market. That has apparently caused significant price suppression and the petitioner was unable to raise its prices to cover its full cost. Therefore, the arguments of the interested parties that the injury is entirely self inflicted is not valid.
 - ii. Some of the interested parties have argued that price suppression due to alleged dumped imports are not substantiated as the cost of sales of the petitioner has increased on account of higher absorption of fixed costs which reflects lesser production quantity as the capacity was not optimally utilised. Therefore, the Authority examined the cost of production of the domestic industry assuming a normal production cycle to neutralise the effects of the higher fixed costs on account of idle time of the plant and even at this normated cost the price was found to be suppressed as the petitioner had lost significant market share, first due to raw material disruption, and then their inability to get back to normal production due to the presence of significant dumped imports. Therefore, the arguments of the interested parties in these regards are not valid.

- iii. Injury of the domestic industry in antidumping investigations is assessed with reference to the POI as is existed and not on the basis of an ideal period. The analysis of data for the previous years is carried out to examine the trends and not to look for an ideal period as has been contended by some interested parties. While the domestic industry may be getting affected by several other factors, including the raw material issues, as is the case in the instant matter, as long as dumping is one of the proximate causes of injury the domestic industry is entitled for protection upto the extent the injury is caused by dumping. Normation of the non-injurious price ensures that self inflicted injury caused by factors internal to the industry such as plant shut down because of reasons other than dumping are not attributed to the dumping.
- iv. The Non Injurious Price has been worked out based on the optimum figure of POI and previous 3 years for capacity utilisation, Raw material cost, utility cost, etc. Following the NIP rule the cost has been optimised and has no impact on idle capacity. In fact low capacity utilization in the POI has resulted in lower NIP. Therefore, contentions of the interested parties that self inflicted injury has been attributed to the dumped imports have no merit;
- v. Further, the Authority examined the physical and financial performance of the petitioner assuming that plant was in operation for those 212 days for which it remained closed due to raw material supply disruption based on the performance for the period in the POI when there was no disruption to see the volume and price impact of dumped imports and arrived at a positive impact outcome as discussed in the disclosure statement. Therefore, the arguments of the interested parties that the authority has failed to address the self inflicted injury and causal link are without any basis and the interests of these parties have not been compromised in any manner;
- vi. In view of the above the Authority holds that there is sufficient evidence to conclude that the domestic industry suffered material injury and the said injury has been caused due to the cumulative effects of dumped imports from the subject countries and disruption of raw-material supply from its lone supplier because of certain force majeure conditions. Accordingly, the arguments of the interested parties in this regards stand disposed off;
- vii. As far as the arguments of the importers that the duty should be imposed in Rupee term the Authority notes that as a consistent practice the duties are being denominated in US\$ term as most of the imports are also denominated in that currency. No specific argument has been made by these parties as to why the duty in this case should be denominated in Indian Rupees. Therefore, the Authority does not find any merit in this submission.

L. Conclusions

- 191. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- (i) The subject goods have entered the Indian market from the European Union, United States of America, Korea RP, Chinese Taipei, Malaysia and Indonesia at prices less than their normal values and the dumping margins of the dumped imports from these countries are substantial and above *de minimis*;
- (ii) The dumping margin of the imports of the subject goods from Saudi Arabia is found to be de minimis and therefore, the investigation against this country has been terminated;
- (iii) The domestic industry has suffered material injury; and
- (iv) The material injury has been caused by the volume and price effects of dumped imports from the countries named at (i) above coupled with disruption in raw material supply during a significant part of the period of investigation;

M. Indian industry's interest & other issues

As noted earlier the user industry has raised concern regarding the ability of the domestic producer to meet the demand in the country and also its vulnerability due to dependence on single source of supply for its critical raw materials. It has also been argued that the subject goods are critical in certain types of industries and disruption of supply from the sole domestic producer in India will significantly affect their operations and downstream users. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority further notes that existence and survival of domestic producer, in a fair market environment, is essential keeping the critical nature of the product for certain critical applications. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers. Therefore, the interests of the user industry will not be significantly affected if antidumping duties are imposed on this product.

N. Recommendations

193. The Authority notes that this investigation was initiated and notified to all interested parties in accordance with the provisions of the Antidumping Rules and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal links for determination of degree and extent of dumping and injury. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that dumping has taken place from the subject countries/territories and the domestic industry has suffered material injury on account of the dumped imports, the Authority considers it necessary and appropriate to recommend imposition of definitive duties duty on imports of subject goods, from the subject countries/territories, in the form and manner described hereunder.

194. Having regard to the lesser duty rules the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in this finding, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duties equal to the amount indicated in Col 8 of the duty table given below is recommended to be imposed, for a period five (5) years from the date of its imposition, by a notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries/territories.

Duty Table

Sl No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Countries/ territories of Origin	Countries/Territ ories of Export	Producer	Exporter (s)	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ch-29 29051620 *	2-Ethyl Hexanol (2-EH) in all forms and grades	Malaysia	Malaysia	BASF PETRONS Chemicals (BPC) Sdn Bhd, Malaysia	BASF PETRONS Chemicals (BPC) Sdn Bhd, Malaysia	53.63	MT	US\$
2	Do	Do	Malaysia	Malaysia	Any combina above	tion other than	107.30	MT	US\$
3	Do	Do	Any, other than the subject countries	Malaysia	Any	Any	107.30	MT	US\$
4	Do	Do	Korea RP	Korea RP	M/s LG Chem, Korea	1.M/s Hyundai Corporation, Korea 2. M/s	NIL	MT	US\$
						Vinmar International, Ltd. USA			
5	Do	Do	Korea RP	Any	Any combina above	tion other than	15.55	MT	US\$
6	Do	Do	Any, other than the subject countries	Korea RP	Any	Any	15.55	MT	US\$
7	Do	Do	European Union	European Union	M/s Oxea GmbH, Germany	1. M/s ICC Chemical Corporation, USA 2. M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai 3. M/s Vinmar International, USA	45.47	MT	US\$
8	Do	Do	European Union	Any	Any combination other than above		113.47	MT	US\$
9	Do	Do	Any, other than the subject countries	European Union	Any	Any	113.47	MT	US\$
10	Do	Do	Indonesia	Indonesia	M/s P. T. Petro Oxo	1.M/s P. T. Petro Oxo	45.67	MT	US\$

					Nusantara, Indonesia	Nusantara, Indonesia 2. M/s Solitz Asia Pte Ltd. Singapore			
11	Do	Do	Indonesia	Indonesia	Any combina above	ation other than	127.82	MT	US\$
12	Do	Do	Any, other than the subject countries	Indonesia	Any	Any	127.82	MT	US\$
13	Do	Do	USA	Any	Any	Any	29.61	MT	US\$
14	Do	Do	Any, other than the subject countries	USA	Any	Any	29.61	MT	US\$
15	Do	Do	Taiwan	Any	Any	Any	42.45	MT	US\$
16	Do	Do	Any, other than the subject countries	Taiwan	Any	Any	42.45	MT	US\$

^{*} the tariff classification is indicative only and not binding for the purpose of duty collection

O. Further Procedures

- 195. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.
- 196. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and the Rules, and Public Notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority